वार्षिक रिपोर्ट

1991 – 92

नीपा

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

— संस्थान के मुख्य भवन का एक दृश्य

— यूनीसेफ द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम में चीनी भागीदार

वार्षिक रिपोर्ट

1991-92

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
17- बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

150 प्रतियां

© राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 1993

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के लिए कार्यवाहक कुलसचिव, नीपा द्वारा प्रकाशित तथा शगुन कंपोजर्स, 92-बी, कृष्णा नगर, सफदरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली-29 में लेजर टाइप सेट होकर, प्रभात ऑफसेट प्रेस, कूचा चेलान, दरिया गंज, दिल्ली-2 में मुद्रित।

विषय सूची

अध्याय

1.	सिंहावलोकन	1
2.	प्रशिक्षण	8
3.	अनुसंधान	22
4.	परामर्शकारी और अन्य सेवाएं	40
5.	पुस्तकालय, प्रलेखन और प्रकाशन सेवाएं	43
6.	प्रशासन और वित्त	47

अनुबंध

1.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी/कार्यशिविर	54
2.	प्रशिक्षण सामग्रियों की सूची	63
3.	नीपा विचारमंच	64
4.	संकाय का अकादमिक योगदान	65

परिशिष्ट

I	नीपा परिषद के सदस्य	75
II	कार्यकारी समिति के सदस्य	78
III	वित्त समिति के सदस्य	81
IV	संकाय और प्रशासनिक स्टाफ	83
V	वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट	89

1991-92

अध्याय 1

सिंहावलोकन

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान को पहले शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से जाना जाता था। 1962 में, भारत सरकार के साथ यूनेस्को के एक दसवर्षीय अनुबंध के द्वारा एशिया क्षेत्र के वरिष्ठ शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए स्थापित एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान का 1970 में अधिग्रहण करके भारत सरकार ने इसे एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया था। मई 1979 में इसे वर्तमान नाम दिया गया।

एक सर्वोच्च संस्था के रूप में नीपा ने अपने अस्तित्व के विगत तीन दशकों के दौरान शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा की है। शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के प्रशिक्षण के अलावा संस्थान के प्रमुख कार्यों में परामर्शकारी सेवाएं और नवाचारों का प्रचार-प्रसार शामिल हैं। संस्थान ने अन्य देशों विशेषकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ-साथ यूनेस्को, यू.एन.डी.पी., यू.एन.इ.पी. और यूनीसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए।

संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यों से जो अकादमिक एककें संबद्ध हैं, वे इस प्रकार हैं : (1) शैक्षिक योजना एकक ; (2) शैक्षिक प्रशासन एकक ; (3) शैक्षिक वित्त एकक ; (4) शैक्षिक नीति एकक ; (5) विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक ; (6) उच्च शिक्षा एकक ; (7) प्रादेशिक प्रणाली एकक और (8) अंतर्राष्ट्रीय एकक।

इस रिपोर्ट में संस्थान के वर्ष 1991-92 की प्रमुख गतिविधियों को शामिल किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर/संगोष्ठी/डिप्लोमा

इस समीक्षा वर्ष में संस्थान ने 45 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर/संगोष्ठियां और 2 डिप्लोमा कार्यक्रम आयोजित किए।

भागीदारी

इस वर्ष संस्थान के कार्यक्रमों में कुल 1032 भागीदार शामिल हुए। इनमें राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के 894, भारत सरकार, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के 78 और 14 देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 60 भागीदार शामिल हैं।

क्षेत्रवार भागीदारी में सर्वोच्च भागीदारी उत्तरी क्षेत्र (323) की थी। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र (221), पूर्वी क्षेत्र (195) और पश्चिमी क्षेत्र (155) थे।

राज्यवार भागीदारी में सर्वोच्च स्थान दिल्ली (81) का था। इसके बाद राजस्थान (70), कर्नाटक (65), आंध्रप्रदेश (63), मेघालय (54), मध्यप्रदेश (52), महाराष्ट्र (51) और तमिलनाडु (46) थे।

शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों—आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल से कुल 364 अधिकारी शामिल हुए जो कि कुल भागीदारी का 40.72 प्रतिशत भाग है।

1991-92

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(अ) राष्ट्रीय डिप्लोमा : ग्यारहवें डिप्लोमा पाठ्यक्रम के परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण से संबंधित तीसरा चरण जुलाई 1991 में पूरा हुआ। सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा की उपाधियां प्रदान की गईं।

बारहवां डिप्लोमा कार्यक्रम नवंबर 1991 में शुरू हुआ जिसमें आठ राज्यों—आंध्रप्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी के अधिकारी शामिल हुए।

(ब) अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा : वर्ष 1990-91 में शुरू सातवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संपन्न हुआ और आठवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया गया जिसमें विदेशों—बोत्सवाना, घाना, केन्या, मारिशस, रूवांडा, तंजानिया, उगांडा, वियतनाम और जांबिया के अधिकारी शामिल हुए।

संस्थान के नियमित कार्यक्रम निम्न थे :

(1) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के योजना और प्रबंध शाखा के अकादमिक सदस्यों के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम ;

(2) महिला प्रशासकों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में दो सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम ;

(3) वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए पांच दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम ;

(4) कालेज प्राचार्यों के लिए तीन सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम ;

(5) माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए दो सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम।

अन्य विषयगत कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान जितने विषयगत कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनके विषय निम्न थे : व्यष्टि स्तरीय योजना, जिला स्तरीय योजना, लंबी अवधि की संप्रेक्ष्य योजना, वित्तीय प्रबंध, संसाधन प्रबंधन, संस्थानों का राष्ट्रीय कार्यक्रम, विद्यालय स्तर पर सांस्थानिक योजना, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा की योजना और प्रबंध, शिक्षा में संगणक का अनुप्रयोग, पर्यावरण शिक्षा, अल्पसंख्यक/पिछड़ा वर्ग, दक्षेस देशों में शिक्षा की योजना और प्रबंध तथा उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध।

यूनेस्को—यू.एन.इ.पी. के सहयोग से शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर छः प्रशिक्षण संगोष्ठियां आयोजित की गईं। दक्षेस देशों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकाध्यक्षों के लिए पुस्तकालयों की योजना और प्रबंध पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण विधि

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतराशास्त्रीय स्वरूप के थे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूलतः व्यवहारिक कार्य, सहायक कार्य, केस अध्ययन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, संगणक, फिल्में, वीडियो और प्रक्षेपकों को उपयोग में लाया गया। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों के लिए क्षेत्रीय दौरे भी आयोजित किए गए।

मूल्यांकन

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनिवार्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है। लंबी अवधि के कार्यक्रमों, जैसे—जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में छः माह के डिप्लोमा कार्यक्रम और शैक्षिक योजना और प्रशासन में 6 माह के अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया सतत चलती रहती है।

प्रशिक्षण सामग्री

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग करने और व्यापक प्रचार-प्रसार

के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में लगभग 29 माड्यूल, आलेख और सांख्यिकीय आंकड़ा भंडार तैयार किए गए।

अनुसंधान

समीक्षाधीन वर्ष में 6 अनुसंधान अध्ययन पूरे हुए, 15 अध्ययनों के कार्य जारी हैं और 4 नए अध्ययनों की मंजूरी दी गई। (इनमें संस्थान की एक अपनी अध्ययन परियोजना, 5 प्रायोजित अध्ययन और नीपा सहायता योजना का एक अध्ययन शामिल हैं)

पूरे किए गए अध्ययन

1. कालेजों के प्रभावी कार्यकलाप और विकास : क्रियात्मक अनुसंधान अध्ययन (दूसरा चरण)
2. कालेजों के विकास में कालेज विकास परिषदों की भूमिका का अध्ययन : चुने हुए 10 कालेज विकास परिषदों का सघन अध्ययन
3. बेसिक शिक्षा सेवा की गुणवत्ता (नीपा—आइ.आइ.इ.पी. सह अध्ययन)
4. आदिवासी और उप-योजना क्षेत्रों के शैक्षिक विकास का अध्ययन
5. भारत के वर्तमान पत्राचार संस्थानों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के प्रबंधन में अपनाई जाने वाली प्रणालियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)
6. मेघालय और मिजोरम की साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों का पायलट अध्ययन.

जारी अध्ययन

1. विद्यालय मानचित्रण पर परियोजना
2. द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण
3. लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध का अध्ययन—निहितार्थ और भारत के लिए सीख
4. भारत में अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों के बीच के साक्षरता स्तर की विषमताओं का जिलेवार विश्लेषण
5. शैक्षिक संस्थानों में प्रबंध की स्वायत्तता : स्वायत्त कालेजों का अध्ययन
6. शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी उपयोग—केस अध्ययन
7. उत्तर प्रदेश में सबके लिए शिक्षा
8. भारत के शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय विषमताएं—आधारभूत स्तर पर सामाजिक कल्याण के संदर्भ में शैक्षिक विषमताओं की पड़ताल
9. प्रारंभिक शिक्षा की संगणकीकृत योजना (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)
10. प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संचारेक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
11. शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग (यूनेस्को प्रायोजित)

नीपा सहायता योजना के अंतर्गत

12. भारतीय विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंध
13. तमिलनाडु में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबंध

14. भारत में कृषि स्नातकों के रोजगार के अवसर : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर का लागत-लाभ अध्ययन
15. पर्वतीय बोंडा जाति का मूल्यगत संप्रेक्ष्य और भागीदारी

स्वीकृत नए अध्ययन

1. पांडिचेरी में शैक्षिक विकास—ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी का समीक्षात्मक अध्ययन (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)
3. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना का समीक्षात्मक अध्ययन (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)
4. जम्मू और काश्मीर तथा हरियाणा के चुने गए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का अध्ययन
5. विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए जरूरी प्रशिक्षणों की पहचान करना (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

प्राथमिकता वाले प्रशिक्षण क्षेत्र

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने पर विशेष बल दिया गया। ये क्षेत्र थे : सबके लिए शिक्षा, व्यष्टि स्तरीय योजना, विद्यालय मानचित्रण, सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी जि.शि.प्र.सं. की योजना और प्रबंध, पिछड़े वर्ग, विकलांग बच्चे, पर्यावरण शिक्षा संगणक अनुप्रयोग और अकादमिक स्टाफ कालेजों का विकास।

अनेक अनुसंधान हाथ में लिए गए जिनका प्रशिक्षण कार्यक्रमों आगत सामाग्रियों के रूप में उपयोग किया गया।

नीपा विचारमंच

नीपा विचारमंच शिक्षा और विकास के महत्वपूर्ण मसलों पर विचारों के आदान-प्रदान का एक व्यवसायिक मंच है। इससे संकाय को अपनी अवधारणाओं को प्रभावी बनाने और सैद्धांतिक आधार को मजबूत बनाने के साथ-साथ शिक्षा के आधारभूत लक्ष्यों और मसलों पर स्पष्ट विचार रखने में मदद मिलती है।

इस वर्ष संस्थान में तीन विचारमंच कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें प्रमुख शिक्षाविद श्री पी.के. माइकल थोराकन, विकास अध्ययन केंद्र, त्रिवेंद्रम और प्रोफेसर कोत्सकी, मास्को विश्वविद्यालय ने व्याख्यान दिए।

विचारमंच के विषयों की सूची अनुबंध III में दी गई है।

प्रकाशन

संस्थान ने इस वर्ष निम्नांकित प्रकाशन निकाले :

1. एजुकेशन फार आल : ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन : पी. एन. त्यागी
2. शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी की रिपोर्ट (22-26 अप्रैल, 1990)
3. शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी की रिपोर्ट (29 अप्रैल-3 मई, 1991)
4. जिला स्तर के प्रयोक्ताओं के लिए कोप/डी.एस.एस. (शिक्षा की संगणकीकृत योजना) प्रयोक्ता मार्गदर्शिका

जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन

1-4. जिल्द 4, अंक 2, अप्रैल 1990, जिल्द 4, अंक 3, जुलाई 1990, जिल्द, 4, अंक 4, अक्टूबर

1990, और जिल्द 5 अंक I, जनवरी 1991.

5. 'शिक्षा का अर्थशास्त्र' विशेषांक जिल्द 5, अंक 2, अप्रैल 1991.

शैक्षिक योजना और प्रशासन जर्नल

6-7. 'शैक्षिक योजना और प्रशासन' जर्नल के 'शैक्षिक प्रशासन' विशेषांक और 'कामकाजी बच्चों की शिक्षा' विशेषांक.

8-9. जिल्द 4 अंक 2, अप्रैल 1990 और जिल्द 4, अंक 3, जुलाई 1990.

निम्नांकित प्रकाशन प्रेस में हैं :

1. 'ज़र्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन' का जिल्द 5, अंक 3, जुलाई, 1991.

2. 'शैक्षिक योजना और प्रशासन' जर्नल का जिल्द 4, अंक 4, अक्टूबर 1990.

मिमियोग्राफ प्रकाशन

संस्थान ने अनुसंधान अध्ययनों, सामयिक आलेखों और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्टों के मिमियोग्राफ प्रकाशित किए।

पुस्तकालय

संस्थान का पुस्तकालय छुट्टियों समेत पूरे साल भर विद्वानों, छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों को अबाध रूप से पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं मुहैया कर रहा है। वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों के अलावा पुस्तकालय में करीबन 45,000 पुस्तकें हैं। शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंधन और दूसरे संबंधित क्षेत्रों के 350 से अधिक पत्र-पत्रिकाएं पुस्तकालय में आती हैं।

प्रलेखन केंद्र में वर्तमान में राज्यों और जिलों के शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित 12,954 प्रलेखों का संग्रह है।

संगणक केंद्र

संस्थान का संगणक केंद्र आइ.बी.एम. संगणक प्रणालियों के विविध संगणकों से सुसज्जित हैं। वर्तमान में संगणक केंद्र में 4 पी.सी./ए.टी., 12 पी.सी./एक्स.टी., एक पी.सी./ए.टी.-386, एक लेजर प्रिंटर, एल.क्यू. के साथ आठ डाट मैट्रिक्स प्रिंटर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा केंद्र में पी.सी आधारित नवीनतम साफ्टवेअर पैकेज हैं, जैसे—लोटस 1-2-3 (3), डीबेस, एस.पी.एस.एस. पी.सी. (4) और वर्डस्टार (6) कोबोले, फ्रोट्रान, पास्कल और 'सी' की भाषाएं उपयोग में लाई जाती हैं।

कार्मिक

संस्थान की काडर योजना नीति का सदैव पालन किया गया। इस नीति के तहत संस्थान में अकादमिक और व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि और प्रशासनिक काडर में धीरे-धीरे कमी करने का लक्ष्य रखा गया हैं। 31 मार्च, 1992 के आंकड़े के हिसाब से संस्थान में स्थाई स्टाफ की संख्या 159 थी। इसके अलावा विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित 40 नियतकालिक परियोजना स्टाफ भी थे।

परिसर सुविधाएं

टाइप IV के क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उन्हें नवंबर 1991 में संस्थान के हकदार अधिकारियों को आबंटित कर दिया गया है।

अतिथि गृह के विस्तार का कार्य आरंभ हो गया है। इसमें वार्डेन आवास, संकाय अतिथि आवास, अतिथि गृह के विस्तार प्रखंड, खानपान गृह का विस्तार, मनोरंजन कक्ष और मेस का आधुनिकीकरण के कार्य शामिल हैं।

वित्त

संस्थान का राजकीय अनुदान से इस वर्ष का कुल खर्च 193.02 लाख रुपए (योजना और योजनेतर दोनों) था जबकि

पिछले वर्ष 1990-91 में यह खर्च मात्र 191.91 लाख रुपए था। इसके अलावा अन्य संगठनों के वित्तीय सहायता से चलने वाले अध्ययनों और कार्यक्रमों पर 32.17 लाख रुपए खर्च हुए। इस प्रकार समीक्षा वर्ष के दौरान राजकीय अनुदान और कार्यक्रमों तथा अध्ययनों के लिए अन्य संगठनों से प्राप्त वित्तीय सहायता से कुल 225.19 लाख रुपए खर्च हुए।

सलाहकारी, परामर्शकारी और समर्थन सेवाएं

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कार्यवाही योजना (1992) के प्रतिपादन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान संस्थान को विख्यात शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और विभिन्न अधिकरणों के साथ अनुभवों के आदान-प्रदान का मौका मिला। संस्थान ने राज्य शिक्षा सलाहकार परिषदों, जिला शिक्षा परिषदों, ग्राम शिक्षा समितियों कीं स्थापना और व्यष्टि स्तरीय योजना, विद्यालय मानचित्रण के निर्माण के लिए मार्गदर्शिकाएं तैयार कीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यान्वयन योजनाओं को तैयार करने में संस्थान ने राज्यों की व्यवसायिक मदद की। अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजना को कारगर बनाने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विभिन्न विश्वविद्यालयों की संस्थान ने व्यवसायिक मदद की।

इसके अलावा संस्थान के संकाय ने दूसरे अकादमिक और व्यवसायिक संगठनों के प्रशिक्षण और अनुसंधानात्मक गतिविधियों में अकादमिक और अधिकारिक समितियों/प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य बनाकर और प्रकाशित अनुसंधान आंकड़ों तथा अपने विशेष क्षेत्र में प्रकाशित ग्रंथों के माध्यम से अकादमिक सहयोग दिए।

नीपा की गतिविधियों की समीक्षा

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा नीपा के कार्य और प्रगति की समीक्षा के लिए गठित समीक्षा समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी। समिति की सिफारिशों की समीक्षा के लिए गठित समर्थ समिति की संस्तुतियां भारत सरकार द्वारा मंजूर होने के बाद जनवरी, 1991 में नीपा को प्राप्त हुईं।

नीपा के पिछले पांच वर्षों के कार्यों की समीक्षा करते हुए समिति ने व्यक्त किया कि नीपा अपने प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्शकारी सेवाओं के प्रमुख लक्ष्यों की पूर्ति में पूरी तरह सफल रहा है। इसके कार्यों में प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि नीपा को और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्यों को अपने हाथ में लेना चाहिए; अपने को एक विचार भंडार के रूप में विकसित करने शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में एक सर्वोत्तम केंद्र बनाना चाहिए; लीक से हटकर नए प्रायोगिक अध्ययन अपने हाथ में लेने चाहिए; शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों को कार्यक्षमताओं के विकास के लिए अपने संकाय और अन्य दूसरों के नए ज्ञान-विज्ञानों का प्रचार-प्रसार करना चाहिए और सभी संस्थानों को एकजुट करके एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि संस्थान अपने संकाय के एक से तीन सदस्यों को शामिल करके नीपा परिषद का विस्तार करे और कार्यकारिणी समिति को भी पहले से मजबूत करे जिसमें (1) राज्य सरकार का एक निदेशक और शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत राज्य शिक्षा संस्थान का, एक निदेशक और (2) नीपा परिषद में शामिल संकाय के तीन सदस्यों में से दो सदस्यों को निदेशक की मदद के लिए समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया जाए नीपा के प्रबंधन के मामले में संकाय के सदस्यों की मदद ली जाए ; कार्यक्रम सलाहकार समिति का योजना और कार्यक्रम समिति नाम दिया जाए जो संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों को मंजूरी देगी और संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करेगी। यह समिति विचार भंडार के रूप में काम करेगी और कार्यकारिणी समिति और संकाय के बीच एक सेतु की भूमिका भी निभाएगी। इससे लंबी और छोटी अवधि की अकादमिक योजनाएं विकसित

1991-92

करने में मदद मिलेगी और अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार और संकाय द्वारा सुनियोजित सलाहकारी कार्यक्रमों को एकमुश्त करने और उनकी समीक्षा तथा अध्ययन के नए क्षेत्रों की पहचान करने में भी इससे सहायता मिल सकती है।

समीक्षा समिति की सिफारिशों और इस समर्थ समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए संस्थान के स्थापना ज्ञापन के अनुच्छेद 3 में इस राष्ट्रीय संस्थान के प्रमुख कर्त्तव्यों और लक्ष्यों के अनुसार निम्नांकित संशोधन किया गया है :

> अनुसंधान अध्ययन, नए विचारों के प्रतिपादन, विचार-विमर्श के द्वारा अनुभवों और नवीनतम तकनीकों के प्रचार-प्रसार तथा बेहतर कार्यक्षमता के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्यदलों के प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक योजना और प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य की ओर उन्मुख एक सर्वोच्च राष्ट्रीय केंद्र के रूप में इस संस्थान का विकास हो।

नीपा परिषद और नीपा कार्यकारिणी समिति के विस्तार के संबंध में नीपा नियम और विनियम के नियम 6 (i) (m) और नियम 21 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं जिन पर नीपा परिषद के अध्यक्ष और मानव संसाधन विकास मंत्री का अनुमोदन मिल गया है। नीपा परिषद, कार्यकारिणी समिति और वित्त समिति के संगठनात्मक ब्योरे परिशिष्ट I, II और III में दिए गए हैं।

नीपा समीक्षा समिति की सिफारिशों और उन पर समर्थ समिति के निर्णयों के अनुसार 'कार्यक्रम सलाहकार समिति' का नाम बदलकर 'योजना और कार्यक्रम समिति' रखा गया है और इसके कार्यकलापों को परिभाषित करके नीपा नियम 3 के तहत समिति को 'राष्ट्रीय संस्थान का प्राधिकरण' माना गया है। इसके बाद योजना और कार्यक्रम समिति के गठन, कार्यकलाप और अधिकार संबंधी स्पष्टीकरण नीपा नियम के अतिरिक्त धारा 32 (i) और (ii) में दिए गए हैं।

1991-92

अध्याय 2

प्रशिक्षण

अपनी गतिविधियों में प्रमुख रूप से विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों की क्षमता का विकास करते हुए नीपा ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तीस वर्षों से नीपा शिक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए संस्थान अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ सहयोग करता हैं। निम्नांकित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है :

(i) शैक्षिक योजना के बदलते हुऐ परिप्रेक्ष्य में प्रतिभागियों को उनकी भूमिका तथा उनके कार्यों से अवगत कराना।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों/वरिष्ठ स्तरीय प्रशासकों/नीति योजनाकारों के साथ अनुभवों तथा नवीनतम विकासों का आदान प्रदान करना।

(iii) केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा चलायी गई विशिष्ट योजनाओं के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना।

(iv) शिक्षा की योजना तथा प्रशासन की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सुविधा के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रणालीबद्ध पाठ्यक्रमों को आयोजित करना।

(v) संस्थान के संकायों द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियों को अनुसंधान, विस्तार तथा परामर्शकारी सेवाओं से लैस करना।

(vi) शैक्षिक योजना और प्रबंध से संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों और राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर के संस्थाओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना।

प्रत्येक वर्ष, विभिन्न राज्य सरकारों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, राज्य शिक्षा संस्थानों, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्यरत दूसरे शैक्षिक संस्थानों के प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए नीपा व्यापक प्रयोग करता रहा है। राज्य सरकार तथा अन्य अभिकरणों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सभी प्रशिक्षण कार्य नीपा में ही आयोजित किए जाते हैं। किंतु यदि आवश्यकता पड़ी नो अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर राज्य विषयक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। नीपा की प्रशिक्षण रणनीति के अंतर्गत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है। काफी संख्या में आत्म अधिगम माड्यूल तैयार किए गए हैं जिनका उपयोग राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान अथवा इसकी समाप्ति पर प्रतिभागियों से प्राप्त औपचारिक तथा अनौपचारिक सूचनाओं का भी विशेष महत्व है।

समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान ने 47 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशिविर/तथा विभिन्न अवधियों की संगोष्ठियां आयोजित की। संस्थान द्वारा आयोजित डिप्लोमा कार्यक्रम का महत्व अभी भी जारी है और वर्ष के दौरान दो ऐसे कार्यक्रम (एक राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय

प्रतिभागियों के लिए) शुरू किए गए। इसके अलावा पिछले वर्ष शुरू किए गए दो डिप्लोमा कार्यक्रम इस वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। वर्ष के दौरान 1032 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इन 1032 प्रतिभागियों में 894 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश कॉडर के हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों संगठनों के 78 प्रतिभागी हैं और शेष 60 अन्य देशों के हैं।

भागीदारी

अनुबंध I में, कार्यक्रम की सूची, अवधि तथा प्रत्येक कार्यक्रम के भागीदारों की संख्या का पूरा विवरण दिया गया है। तालिका 1 में इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

(अ) राष्ट्रीय

तालिका 2, 3 और 4 में क्रमानुसार राज्यवार, क्षेत्रवार तथा स्तरवार भागीदारी से संबंधित विवरण दिया गया है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि :

- संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दादर तथा नागर हवेली को छोड़कर) ने हिस्सा लिया।
- 40.72% से भी अधिक भागीदार शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों विशेषतया आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल से थे।
- क्षेत्रवार भागीदारी में उत्तरी क्षेत्र की भागीदारी 323 सबसे अधिक थी, इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र 221, पूर्वी क्षेत्र 195 और पश्चिमी क्षेत्र 155 थे।
- राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त, भारत सरकार तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के 78 अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

तालिका 1

कार्यक्रमों का व्यापक वर्गीकरण

कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
I. डिप्लोमा कार्यक्रम			
(अ) राष्ट्रीय डिप्लोमा	1	176	26
(ब) अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा	1	169	39

1991-92

कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
II. विषयक कार्यक्रम			
1. विद्यालय प्रधानाध्यापकों के लिए कार्यक्रम	3	29	79
2. विद्यालय शिक्षा की योजना और प्रबंध	6	24	120
3. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की योजना और प्रबंध	3	46	72
4. प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण और व्यष्टि स्तरीय योजना	4	26	77
5. अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा	1	3	19
6. अल्पसंख्यक/पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की योजना और प्रबंध	3	13	48
7. संस्थानों के राष्ट्रीय कार्यक्रम	3	12	58
8. जिला स्तर पर शैक्षिक योजना	2	17	12
9. लंबी अवधि की संप्रेक्ष्य प्रणाली की योजना की कार्यविधि	1	5	3
10. शैक्षिक योजना में परिमाणात्मक तकनीक	1	13	44

कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
11. उच्च शिक्षा के कालेजों, अकादमिक स्टाफ कालेजों तथा विश्वविद्यालयों की योजना तथा प्रबंध	5	44	141
12. वित्त प्रबंध	1	5	24
13. संसाधनों का उपयोग	2	8	38
14. शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणक का अनुप्रयोग	3	29	54
15. पर्यावरण शिक्षा की योजना और प्रबंध	6	29	167
16. दक्षेस देशों में शैक्षिक योजना तथा प्रबंध	1	4	11
कुल योग	**47**	**652**	**1032**

तालिका 2

राष्ट्रीय भागीदारी

राज्य/के. शा. प्र.	भागीदार
आंध्र प्रदेश*	63
अरुणाचल प्रदेश*	2
असम*	22

1991-92

राज्य/के. शा. प्र.	भागीदार
बिहार*	14
गोवा	10
गुजरात	38
हरियाणा	34
हिमाचल प्रदेश	11
जम्मू और कश्मीर*	20
कर्नाटक	65
केरल	30
मध्यप्रदेश	52
महाराष्ट्र	51
मणिपुर	36
मेघालय	54
मिजोरम	10
नागालैंड	7
उड़ीसा*	18
पंजाब	17
राजस्थान*	70
सिक्किम	2
तमिलनाडू	46
त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश*	79
प. बंगाल*	24

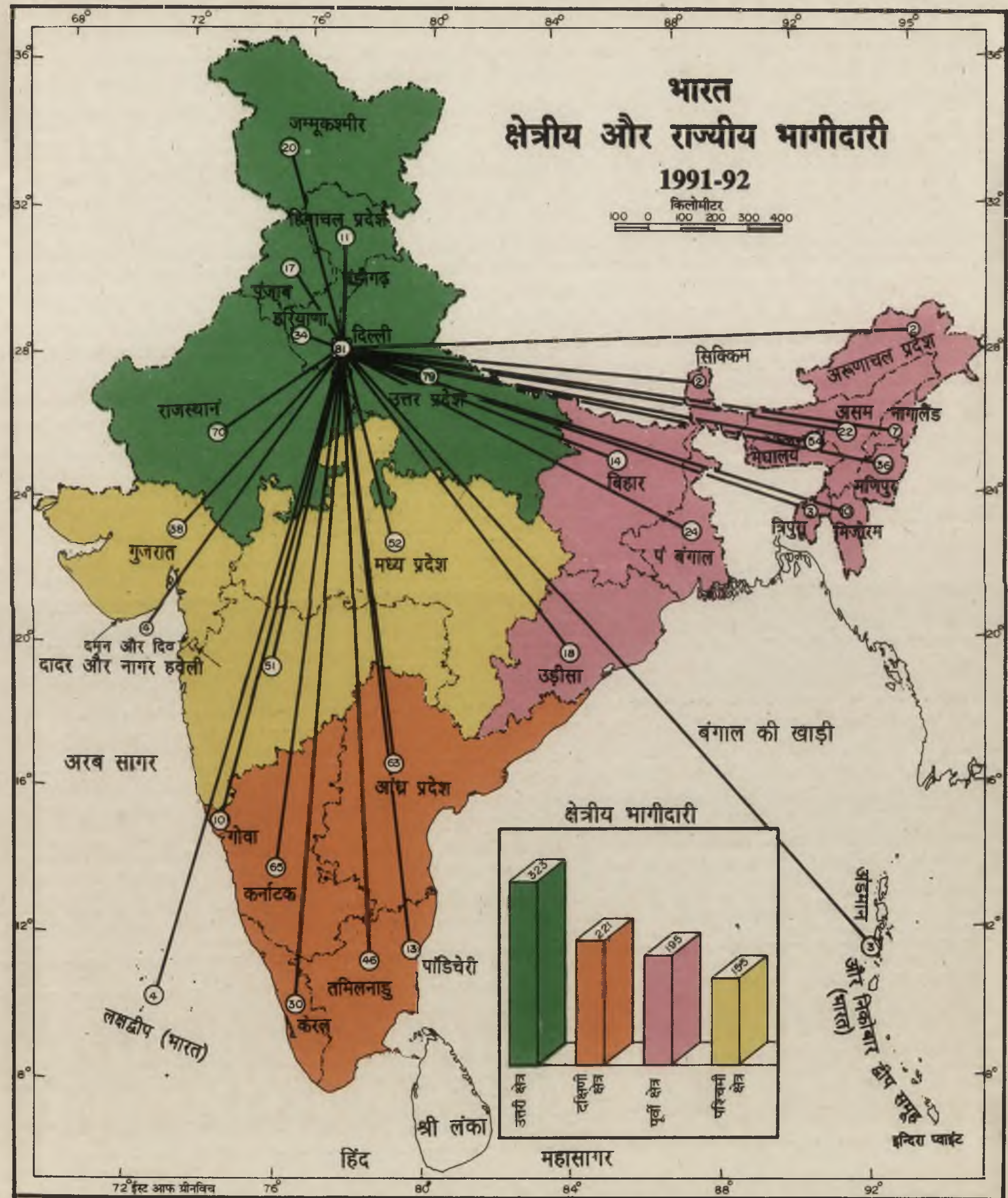

नीपा/पी.एन. त्यागी/03193

राज्य/के. शा. प्र.	भागीदार
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3
चंडीगढ़	11
दादरा और नागर हवेली	—
दमन और दीव	4
दिल्ली	81
लक्षद्वीप	4
पांडिचेरी	13
योग	894
भारत सरकार और अन्य संगठन	78
कुल योग	**972**

* शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य

तालिका 3

क्षेत्रवार भागीदारी

क्षेत्र	भागीदारी
उत्तरी क्षेत्र	323
दक्षिणी क्षेत्र	221
पूर्वी क्षेत्र	195
पश्चिमी क्षेत्र	155
योग	**894**
भारत सरकार और अन्य संगठन	78
कुल योग	**972**

तालिका 4

स्तरवार भागीदारी

स्तर	भागीदार
विद्यालय प्रधानाध्यापक	112
जिला शिक्षा अधिकारी	50
अन्य विद्यालय प्रधानाध्यापक	347
प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	11
सांख्यिकी अधिकारी	8
कालेज प्राचार्य	108
अन्य विश्वविद्यालय कार्मिक	188
अन्य	148
योग	**972**

(ब) अंतर्राष्ट्रीय

संस्थान के कार्यक्रमों में 24 देशों के 60 भागीदार शामिल हुए। इनमें सातवें और आठवें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा के 39 भागीदार भी सम्मिलित हैं। भारत को छोड़कर 22 भागीदार 6 दक्षेस देशों से थे तथा एक भागीदार यूनेस्को का विशेषज्ञ था। तालिका 5 में देशवार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी संबंधी विवरण दिया गया है।

तालिका 5

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

देश का नाम/अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम	भागीदार
अफगानिस्तान	1
बंगला देश	4
भूटान	2
बोत्सवाना	1

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 1991-92

1991-92

देश का नाम/अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम	**भागीदार**
क्यूबा	1
गांबिया	1
धाना	1
केन्या	2
मलयेशिया	1
मलावी	1
मालद्वीव	1
मारीशस	5
नामीबिया	3
नेपाल	5
नाईजीरिया	2
पाकिस्तान	2
रुवांडा	1
सेनेगल	2
श्रीलंका	6
तंजानिया	1
युगांडा	8
वियतनाम	2
जांबिया	2
जिंबाबवे	4
योग	**59**
अंतर्राष्ट्रीय संगठन (युनेस्को)	1
कुल योग	**60**

1991-92

डिप्लोमा कार्यक्रम

इस वर्ष दो डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए गए थे :

शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा

संस्थान ने जुलाई, 1983 में शैक्षिक योजना और प्रशासन विषय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया था। इस वर्ष संस्थान में ग्यारहवें डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे चरण पूरे हुए। नवंबर 1991 में बारहवां डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हुआ। इसका तीन महीने का पहला चरण फरवरी 1992 में पूरा हुआ और दूसरा चरण मई 1992 तक चलेगा। ग्यारहवें और बारहवें डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 15 राज्यों और संघीय राज्यों जिला शिक्षा अधिकारियों और तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के कार्मिकों सहित 26 प्रशिक्षार्थी शामिल हुए। तालिका 6 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संबंधी राज्यवार भागीदारी प्रदर्शित है।

तालिका 6

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्यवार भागीदारी

राज्य/संघीय राज्य	ग्यारहवां डिप्लोमा	बारहवां डिप्लोमा	योग
आंध्र प्रदेश	—	1	1
आसाम	1	—	1
हरियाणा	—	3	3
जम्मू और कश्मीर	2	4	6
कर्नाटक	2	—	2
मध्य प्रदेश	—	1	1
मेघालय	1	—	1
मिजोरम	—	1	1
राजस्थान	1	—	1
तमिलनाडु	—	1	1
त्रिपुरा	1	—	1
उत्तर प्रदेश	2	1	3
पश्चिम बंगाल	1	—	1
दिल्ली	1	—	1
पांडिचेरी	—	2	2
योग	**12**	**14**	**26**

1991-92

तीन चरणों में आयोजित डिप्लोमा कार्यक्रम 25 श्रेयांक का होता है। इसका पहला चरण तीन महीने का होता है जिसका श्रेयांक 15 होता है। इस चरण में पाठ्यचर्या का गहन अध्ययन किया जाता है। तीन महीने के दूसरे चरण में पर्यवेक्षणाधीन परियोजना कार्य शामिल है। तीसरा चरण 4-6 दिन का होता है। इसमें प्रशिक्षणार्थी के परियोजना कार्य का मूल्यांकन किया जाता है और एक साथ बैठकर विचारों का आदान-प्रदान होता है। भागीदारों से प्राप्त पुनर्निवेशन और बदलते परिवेश में उनके कार्यकलापों के मूल्यांकन के आधार पर डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण प्रणाली की पुनर्रचना की गई। विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रबंध कौशल तथा परियोजना और कार्ययोजना बनाने के लिए अपेक्षित कौशलों में वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सांस्थानिक योजना, विद्यालय मानचित्रण, विद्यालय संगम, मात्रात्मक तकनीक, संकट की चुनौतियों का सामना करने के लिए संकल्प, सामुदायिक भागीदारी इत्यादि पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। डिप्लोमा की प्रशिक्षण प्रणाली विभिन्न विषयों पर व्याख्यान-चर्चा, पैनल परिचर्चा, केस अध्ययन, सामूहिक कार्य, सामूहिक अभ्यास भूमिका प्रदर्शन, इन-बास्केट विधि और सामूहिक परिचर्चा पर आधारित थी। प्रायोगिक अभ्यास, पुस्तकालय आधारित कार्य और कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानों के दौरे पर भी पर्याप्त समय दिया गया।

भागीदारों को विद्यालय शिक्षा और समुदाय के क्षेत्र में किए गए प्रायोगिक नवाचारों से अवगत कराने के लिए महाराष्ट्र के बंबई तथा पुणे जिले का एक सप्ताह का क्षेत्रीय दौरा आयोजित किया गया।

शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा

संस्थान में पहला अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम जनवरी 1985 में शुरू किया गया। सातवं अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम जनवरी 1991 में शुरू हुआ और इस वर्ष के अंदर ही पूरा हो गया। सातवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा जनवरी 1992 में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता के कारण प्रवेश के लिए अधिक संख्या में नामित पत्र प्राप्त-हुए। सातवें डिप्लोमा में 14 देशों के 26 भागीदार, और आठवें डिप्लोमा में 9 देशों के 13 भागीदार शामिल हुए। तालिका 7 में देशवार भागीदारी का विवरण प्रदर्शित है।

तालिका 7

अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी

देश का नाम	सातवां अं. डि.	आठवां अं. डि.	योग
अफगानिस्तान	1	-	1
बोत्सवाना	-	1	1
क्यूबा	1	-	1
गांबिया	1	-	1
घाना	-	1	1
केन्या	1	1	2
मलयेशिया	1	-	1

देश का नाम	सातवां अं. डि.	आठवां अं. डि.	योग
मलावी	1	-	1
मारीशस	2	2	4
नामीबिया	3	-	3
नाईजीरिया	2	-	2
रुवांडा	-	1	1
सेनेगल	2	-	2
श्रीलंका	1	-	1
तनजानिया	-	1	1
युगांडा	5	3	8
वियतनाम	-	2	2
जांबिया	1	1	2
जिंबाबवे	4	-	4
योग	**26**	**13**	**39**

अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा दो चरणों में पूरा होता है। प्रत्येक चरण तीन महीने का होता है। पहले चरण में पाठ्यचर्या पर गहन अध्ययन कार्य किया जाता है। दूसरे चरण में प्रशिक्षणार्थी अपने देश में परियोजना कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित है। पहला भाग बेसिक और केंद्रिक पाठ्यक्रम का होता है। दूसरा भाग विशेष पाठ्यक्रम का होता है। केंद्रिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक योजना और प्रशासन की मूल अवधारणाओं और तकनीकों की जानकारी दी जाती है जबकि दूसरा भाग प्रशिक्षणार्थी द्वारा चुने गए विशेष क्षेत्र में व्यापक कार्य के विशेष कौशल पर आधारित होता है। इस पाठ्यक्रम में निम्न विषय शामिल हैं—तीसरी दुनिया में शिक्षा की योजना और प्रबंध, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और दूरवर्ती शिक्षा, संगणकों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण आदि। नीपा में क्षेत्र संलग्न कार्यक्रम इस पाठ्यक्रम का पूरक है।

आठवें डिप्लोमा कार्यक्रम के दौरान संस्थान ने निम्नांकित संस्थानों के दौरे आयोजित किए : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति के मुख्यालय तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान। इसके अलावा भागीदारों ने महाराष्ट्र राज्य के उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थानों और विद्यालयों के दौरे भी किए। इन राज्यों में दौरे वाले संस्थान और विद्यालय निम्न थे—बंबई विश्वविद्यालय और उसके कुछ कालेज, एस.एन. डी.टी. विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, पुणे, महाराष्ट्' पाठ्य पुस्तक निर्माण और अनुसंधान ब्यूरो, पुणे, तथा संस्थान और सांस्कृतिक केंद्र।

1991-92

वित्तीय सहायता देने वाले विभिन्न अभिकरणों की ओर से कार्यक्रम के बारे में औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संस्थान को सकारात्मक पुनर्निवेशन प्राप्त हो रहे हैं।

संस्थान के अन्य कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संस्थान ने 30 प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम, 9 कार्यशिविर और 5 संगोष्ठियां/बैठकें आयोजित किए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशिविरों और संगोष्ठियों के 16 विषय इस प्रकार थे : विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए सांस्थानिक योजना, विद्यालय शिक्षा की योजना और प्रबंध, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंध, शिक्षा का सार्वजनीकरण और व्यष्टिस्तरीय योजना, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा, अल्पसंख्यक/पिछड़े वर्ग की शिक्षा की योजना और प्रबंध, संस्थानों के राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिला स्तरीय शैक्षिक योजना, लंबी अवधि की संप्रेक्ष्य योजना की कार्यप्रणाली, शैक्षिक योजना की मात्रात्मक तकनीकें, उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध—अकादमिक स्टाफ कालेज और स्वायत्त कालेज, वित्तीय प्रबंध, संसाधनों का उपयोग, शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणक का अनुप्रयोग, पर्यावरण शिक्षा की योजना और प्रबंध और सार्क देशों में शैक्षिक योजना और प्रबंध।

विषयगत कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986 और कार्यवाही योजना के कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर संस्थान द्वारा विषयगत कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाती है। विभिन्न स्तरों के शिक्षाकर्मियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विषयगत कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सांस्थानिक योजना और प्रबंध पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधाना- ध्यापकों के लिए तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नीतियों और नाजुक मसलों तथा सांस्थानिक योजना की नई अवधारणाओं और तकनीकों के अलावा विद्यालय शिक्षा में सम्यक सुधार पर विशेष बल दिया गया। इन कार्यक्रमों में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के कुल 79 प्रधानाध्यापक शामिल हुए। इनमें एक कार्यक्रम क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो आंध्रप्रदेश के करीमनगर जिले के जि.शि.प्र.सं. में आयोजित किया गया।

विद्यालय स्तर के विभिन्न शिक्षाकर्मियों के लिए विद्यालय शिक्षा की योजना और प्रबंध पर छः कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमे 120 शिक्षाकर्मी शामिल हुए।

इन कार्यक्रमों में निम्न विषयों और मसलों को शामिल किया गया : प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विभिन्न स्तरों के शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान, आठवीं योजना के तहत 'सबके लिए शिक्षा' के लक्ष्य की प्राप्ति और विद्यालय शिक्षा की सामान्य योजना और प्रबंधन।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की योजना और प्रबंध विषय पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें देशभर के जि.शि.प्र.सं. के संकायों के कुल 72 अधिकारी शामिल हुए।

प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण और व्यष्टि स्तरीय योजना पर चार कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 77 भागीदार शामिल हुए। इनमें से दो कार्यक्रम मेघालय और मणिपुर में आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों में राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की योजना से संबंधित मसलों, रण-नीतियों और उपलब्ध वैकल्पिक नीतियों से भागीदारों को अवगत कराया गया तथा प्रा.शि.सा. कार्यक्रमों में सुधार और व्यष्टि स्तरीय योजना का शुभारंभ करने के लिए योजना की विभिन्न रणनीतियों और पद्धतियों के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।

अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा के सहायक निदेशकों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सामान्य रूप से अनौपचारिक शिक्षा के संचारेक्षण और प्रबंधन संबंधी मसलों पर प्रकाश डाला गया तथा

अनौ.शि.केंद्रों की अकादमिक क्षमता बढ़ाने, तथा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के केंद्रों में अनौ.शि.कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए जिलास्तर पर कार्यवाही योजना के विकास पर विशेष बल दिया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से कुल 19 सहायक निदेशक शामिल हुए।

अल्प संख्यक/पिछड़े वर्ग की शिक्षा की योजना और प्रबंध के क्षेत्र में तीन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 48 भागीदार शामिल हुए। इनमें से एक-एक कार्यक्रम 'विकलांग बच्चों की शिक्षा की क्षेत्र संसाधन योजना', 'अल्पसंख्यक प्रबंधित संस्थानों का प्रबंधन', तथा 'आदिवासी और उपयोजना क्षेत्रों का विकास' से संबंधित थे।

संस्थानों के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस विशेष विषय पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 58 भागीदार शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय कार्यक्रम के विकास के लिए सांस्थानिक प्रबंधन के माडल के विकास पर चर्चा की गई और शिक्षा के विविध पक्षों, जैसे—अकादमिक संसाधनों, कार्मिक प्रबंधन, प्रबंधकीय गुणवत्ता और प्रशिक्षण के विविध विधानों आदि पर विचार विमर्श किया गया।

शैक्षिक योजना के क्षेत्र में चार कार्यक्रंम आयोजित किए गए। इनमें दो कार्यक्रम जिला स्तरीय योजना पर और 'लंबी अवधि की संप्रेक्ष्य योजना' तथा शैक्षिक योजना की मात्रात्मक तकनीकों पर एक-एक कार्यक्रम थे। इन कार्यक्रमों में राज्यों और संघ क्षेत्र राज्यों से कुल 57 भागीदार शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में जिलास्तर की शैक्षिक योजना की प्रक्रियाएं और विधियां, जिलास्तरीय योजनाओं और लंबी अवधि की संप्रेक्ष्य योजनाओं की कार्यान्वयन रणनीतियां तथा जिला स्तर पर आंकड़ा संग्रह की मात्रात्मक विधियों के विविध प्रारूपों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई।

महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशकों के लिए पांच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें महाविद्यालय प्राचार्यों, विश्वविद्यालय कुलसचिवों और अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशकों समेत कुल 141 भागीदार शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय विकास में उच्च शिक्षा की भूमिका और अन्य ज्वलंत मसलों, जैसे—उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और प्रासंगिकता आदि पर चर्चा की गई।

वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के उपयोग पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 62 भागीदार शामिल हुए। इनमें से एक कार्यक्रम विशेष रूप से विश्वविद्यालय वित्त अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। शेष दो कार्यक्रम राज्य स्तर पर अनुदानों और संसाधनों से संबंधित कार्यों से जुड़े अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय वित्तीय प्रबंधन पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में आर्थिक विकास और विश्वविद्यालय वित्तीय प्रबंधन की भूमिका और संबद्ध मसलों तथा लागत विश्लेषण, व्यय विश्लेषण एवं विश्वविद्यालयों में बजट बनाने की तकनीकों पर चर्चा की गई।

वर्तमान युग में शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में संगणक अनुप्रयोग की मांग लगातार बढ़ रही है। अतः इस क्षेत्र में तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 54 भागीदार शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में इ.एम.आइ.एस. की अवधारणा, शिक्षाप्रणाली के मात्रात्मक विश्लेषण की विधियों/मॉडलों का उपयोग और आंकड़ा आधार तथा आंकड़ा आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए विभिन्न शैक्षिक साफ्टवेअरों के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया।

पर्यावरण शिक्षा की योजना और प्रबंध के क्षेत्र में 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कुल 167 भागीदार शामिल हुए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए यूनेस्को—यू.एन.इ.पी. और नीपा के बीच एक संयुक्त समझौता हुआ था। इन कार्यक्रमों में पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन, विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा देने एवं पर्यावरण कार्यक्रमों

और नीतियों इत्यादि के कार्यान्वयन के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से समन्वित करने पर बल दिया गया। दक्षिणी एशियाई देशों के शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए यूनेस्को की मदद से पर्यावरण शिक्षा पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशिविर का आयोजन किया गया।

इस्लामाबाद, पाकिस्तान में शिक्षा पर आयोजित दक्षेस की तकनीकी समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार दक्षेस देशों की शैक्षिक योजना और प्रबंध पर एक कार्यशिविर आयोजित किया गया। दक्षेस के सभी सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया। इस कार्यशिविर में शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी और आंतरिक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यशिविरों/सम्मेलनों/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों/दौरे और अन्य दूसरे कार्यक्रमों की सूची अनुबंध I में दी गई है।

प्रशिक्षण सामग्रियां/माड्यूल

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग करने और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न विषयों पर 29 माड्यूलों के अलावा शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित आलेख और सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किए गए। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान तैयार की गई प्रशिक्षण सामग्रियों की सूची अनुबंध II में दी गई है।

1991-92

अध्याय 3

अनुसंधान

शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न पक्षों पर अध्ययन करना, अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना तथा अनुसंधान कार्यों में दूसरे संगठनों, राज्यों और अन्य देशों के साथ सहयोग करना नीपा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इनमें विभिन्न राज्यों और विश्व के अन्य देशों की शैक्षिक योजना और प्रशासन की तकनीकों तथा विधियों के तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल हैं।

व्यष्टि और समष्टि स्तरों पर शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नीतिगत मसलों और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान से संबंधित अभिज्ञान, प्रासंगिक आंकड़े और पुनर्निवेशन के लिए व्यावहारिक अध्ययन की ओर संस्थान की अनुसंधानात्मक गतिविधियां उन्मुख होती हैं। अनुसंधान अध्ययनों के निष्कर्षों से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सदैव अद्यतन बनाया जाता है।

वर्ष 1991-92 में अनुसंधान पर कुल 13.64 लाख रुपए व्यय हुए। नीपा सहायता योजना के तहत 0.68 लाख रुपए की अनुदान राशि आवंटित की गई और प्रायोजित अध्ययनों के लिए 51.36 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

इस वर्ष 6 अनुसंधान अध्ययन पूरे हुए। 15 अध्ययनों पर कार्य चल रहा है। 4 नए अध्ययनों को आरंभ करने की स्वीकृति दी गई। इनमें से 3 अध्ययन प्रायोजित हैं और 1 अध्ययन नीपा सहायता योजना के अंतर्गत है।

पूरे किए गए अध्ययन

1. कालेजों का समुचित कार्यकलाप और विकास : क्रियात्मक अनुसंधान (दूसरा चरण)

इस क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना के दूसरे चरण के लिए रु. 5.78,410/- की राशि मंजूर की गई थी। इसके कार्यदल में डॉ. जी.डी. शर्मा, परियोजना निदेशक, डॉ. एम.एम. रहमान, परियोजना सह-अध्येता, और डॉ. (श्रीमती) कौसर विज़ारत और श्री के.के. बिस्वाल, परियोजना सहायक शामिल थे।

अध्ययन के मुख्य उद्देश्य

1. चुने हुए कालेजों के समुचित कार्यकलापों और विकास संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करना;
2. अगर आवश्यकता पड़ी तो कालेजों के कार्यों तथा विकास में सुधार के उद्देश्य से आवश्यक परिवर्तनों के लिए सलाह देना;
3. निम्नांकित को क्रियान्वित करने के लिए कालेजों को राजी करना तथा इसमें इनकी मदद करना : (अ) सुझाए गए परिवर्तन, (ब) विकास संबंधी अन्य योजनाएं, जैसे सी.ओ.एस.आइ.पी., सी.ओं.एच.एस. एस..आइ.पी. और यू.एल.पी. तथा सामाजिक जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना करना;
4. सुझाए गए परिवर्तनों के प्रभाव की समीक्षा करना;
5. समस्याओं और उनके समाधान के उपायों तथा इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त अनुभवों को सुसंबद्ध करना ताकि कालेज प्राचार्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसका उपयोग किया जा सके।

संक्षेप में इस अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं :

1991-92

1. अकादमिक गतिविधियां, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यचर्यात्मक और गैरपाठ्यचर्यात्मक गतिविधियां, योजना और प्रबंध की आधुनिक संकल्पना का कार्यान्वयन और विकास के संबंध में अध्ययनाधीन कालेजों की वर्तमान स्थितियों/समस्याओं से अवगत होना ;

2. अकादमिक, भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गुणवत्ता के विकास में कालेज के छात्रों की मदद करना ;

3. संप्रेक्ष्य ज्ञान और कौशल के माध्यम से सामाजिक और सामुदायिक विकास के लिए छात्रों, शिक्षकों और संगठन के रूप में कालेज की मदद करना ;

4. इस प्रक्रिया में प्राप्त अनुभवों के माध्यम से अन्य कालेजों को लाभान्वित करना।

निष्कर्ष

1. परीक्षा परिणाम के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि पिछले वर्ष के परीक्षा परिणाम के मुकाबले परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा था।

2. कुछ विषयों में आशा के अनुरूप सुधार नहीं हुआ। अतः इन पर विशेष ध्यान दिया गया।

3. शिक्षकों को तत्काल प्रशिक्षित करने की जरूरत है।

4. सूचनाओं के विश्लेषण से पता चला कि निदानात्मक पाठ्यक्रम, संवृद्धि कार्यक्रम तथा प्रभावी शिक्षण प्रविधि की जरूरत है।

5. विभागीय पुस्तकालय की जरूरत महसूस की गई।

6. नियमित पुस्तकालय सेवा की जरूरत है।

7. विभागीय और सांस्थानिक योजना का प्रस्ताव रखा गया।

8. शिक्षण स्टाफ का अकादमिक पृष्ठभूमि में सुधार भी जरूरी है।

9. यह भी ज्ञात हुआ कि अकादमिक स्टाफ अनुसंधानात्मक गतिविधियां शुरू करना चाहता है।

10. उनके विभिन्न गतिविधियों से जाहिर हुआ कि अकादमिक स्टाफ अन्य गतिविधियों में हिस्सेदारी चाहता है।

छात्रों का विकास

1. कालेजों में पहले से किसी प्रकार की कोई सोसाइटी गठित नहीं की गई थी।

2. यह देखा गया कि गैरपाठ्यचर्या गतिविधियों में अधिकांश छात्र सक्रिय नहीं थे।

3. यह पाया गया कि थोड़े से छात्र ही गैरपाठ्यचर्या गतिविधियों पर हावी थे।

4. ऐसे छात्रों में अधिकांश नगरीय क्षेत्रों और बड़े घरानों के थे।

5. सामान्यतया यह देखा गया कि गैरपाठ्यचर्या गतिविधियों में अधिकांश छात्रों की कोई दिलचस्पी नहीं थी।

6. यह भी देखा गया कि गैरपाठ्यचर्या गतिविधियों का प्रबंधन और मार्गदर्शन अकादमिक सदस्य ठीक से नहीं कर पाते।

7. अकादमिक सदस्यों की दिलचस्पी उत्साहवर्द्धक नहीं थी।

कालेज समुदाय संबंध

यह देखा गया कि ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में कालेज से समुदाय का कोई सीधा संबंध नहीं है।

2. महाविद्यालयों के विकास में महाविद्यालय विकास परिषदों की भूमिका : चुने हुए 10 महाविद्यालय विकास परिषदों का गहन अध्ययन

कालेज विकास परिषदों की भूमिकाओं के गहन अध्ययन के लिए रु. 1, 26, 800/- की राशि मंजूर की गई थी। डॉ. (श्रीमती) इंदिरेसन, परियोजना निदेशक और सुश्री एम.तुलसी तथा सुश्री एम. कगदियाल, परियोजना सहायक इस परियोजना दल में शामिल थीं।

अध्ययन के उद्देश्य

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शन में इन परिषदों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं और इस प्रक्रिया के दौरान उनके सामने आई समस्याएं तथा कठिनाइयों का पुनरीक्षण करना ;
- महाविद्यालयों के विकास में महाविद्यालय विकास परिषदों के प्रभाव का अध्ययन करना ;
- संस्थागत योजना और प्रबंध में महाविद्यालय प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास हेतु नोडल केंद्र की भूमिका का निर्वाह करने वाले महाविद्यालय विकास परिषद की संभावनाओं की छानबीन करना ;
- महाविद्यालयों के विकास में महाविद्यालय विकास परिषदों की भूमिका को मजबूत करने के लिए उचित उपाय सुझाना।

निष्कर्ष

महाविद्यालय विकास परिषदों की उपलब्धियों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि जब भी महाविद्यालय विकास परिषदों ने आवश्यक क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप किया तब-तब उसका नतीजा काफी प्रभावी हुआ है। सांविधानिक शक्तियों के बगैर भी संसाधनों की खोज कर ली गई तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया। सूचनाओं का प्रसार भी एक अत्यंत सरल घटक है जैसे महाविद्यालयों के कार्यदिवस पर सूचनाएं एकत्रित करके उसके प्रसार करने से इनमें परिवर्तन हुए हैं। अतः नए विद्यालयों की स्थापना, रोजगार सुविधाएं छात्र उपलब्धियां आदि से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं पर यदि सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं तो उसका उपयोग लोगों के विचार जानने तथा उसके अनुरूप कार्य करने के लिए किया जा सकता है।

एक निदेशक ने बताया कि उपकुलपति महोदय कई मामलों तथा समस्याओं के बीच घिरे होने की वजह से महाविद्यालयों के विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। महाविद्यालय विकास परिषद के निदेशक के पद को और अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए यदि इन्हें सीधे-सीधे उपकुलपति के सहयोग का जिम्मा दे दिया जाए तो यह निकाय और अधिक प्रभावी होगा। महाविद्यालय विकास परिषद के निदेशक का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः योग्य व्यक्ति का चुनाव परमावश्यक है। महाविद्यालय विकास परिषद के निदेशक के चुनाव के लिए आवश्यक मानदंड तथा पद से संबंधित कार्य की आवश्यकताओं को स्पष्ट कर देना चाहिए। अतः नियुक्ति के लिए चुनाव करते समय महाविद्यालय विकास परिषद की बदलती हुई भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

महाविद्यालय विकास परिषद की जिम्मेदारियां तथा कार्यों में विस्तार लाने तथा उन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचें का आंतरिक हिस्सा बनाने का भी सुझाव दिया गया है ताकि कार्य, भूमिका, शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र की अतिव्याप्ति से बचा जा सके।

3. बेसिक शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता (नीपा-आइ.आई.इ.पी. सहयोगी अध्ययन)

बेसिक शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता पर नीपा-आइ.आइ.इ.पी. पेरिस के सहयोगात्मक अध्ययन के लिए रु. 6,64,900/- की राशि मंजूर की गई थी। इस परियोजना अध्ययन दल में डॉ.आर.गाविंद, परियोजना निदेशक, डॉ. एन.वी.वर्गीस,

1991-92

परियोजना संयोजक और डॉ. आर.पी. कथूरिया, परियोजना संयोजक (क्षेत्रीय कार्य) शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस द्वारा विकसित देशों के लिए बेसिक शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रारंभ किया गया अध्ययन विस्तृत अंतरक्षेत्रीय परियोजना का एक भाग है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित हैं।

(अ) प्रदान की गई सुविधाएं तथा कार्यान्वयन के वातावरण को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करना।

(ब) विभिन्न स्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के कार्यान्वयन की गुणवत्ता का विशेषकर अल्पविकसित तथा अधिकतर विकसित मुहल्लों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना।

(स) विशेष रूप से साक्षरता तथा संख्यात्मक कौशल पर ध्यान देते हुए शिक्षार्थियों के उपलब्धता स्तर के संदर्भ में विद्यालय की कारगुजारी की समीक्षा करना।

(द) प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली प्रक्रिया से संबंधित घटक और विभिन्न आगत के साथ अधिगम उपलब्धि का संबंध स्थापित करना।

मध्यप्रदेश जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य के पांच चुनिंदा मुहल्लों में स्थापित विद्यालयों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह अध्ययन किया गया है। अध्ययन की मूल संरचना को ध्यान में रखते हुए पांच मुहल्ले कुछ इस प्रकार से चुने हुए हैं कि इन सभी में संपूर्ण विकास के स्तरों में अंतर हैं विशेषकर अधिकतम पिछड़े इलाके से लेकर अधिकतम विकसित इलाके तक।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से प्राप्त कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं :

(अ) प्रतिदर्शी के रूप में लिए गए विद्यालयों के स्तरवार विश्लेषण से यह पता चलता है कि पांच साल तक विद्यालय जाने के बाद भी केवल 10% बच्चों ने हिंदी में और 5 प्रतिशत बच्चों ने गणित में बेसिक ज्ञान तथा कौशल संघटक में विद्वता हासिल की। किंतु जब हम पिछड़े ग्रामीण इलाकों से विकसित शहरी इलाकों की ओर बढ़े तो तात्विक सुधार स्पष्ट रूप से देखा गया। यह स्पष्ट रूप से दोनों विषयों तथा दोनों के ग्रेड से पता चलता है।

(ब) हिंदी और गणित के शिक्षार्थियों की माध्य संख्या को देखने से पता चलता है कि प्रतिदर्श के अंतर्गत कम विकसित मुहल्लों की अपेक्षा अधिक विकसित मुहल्लों में सुधार तात्विक रूप से अधिक हुआ है। तीन पिछड़े इलाकों के शिक्षार्थियों की माध्य संख्या पूरी जनसंख्या की संपूर्ण माध्य संख्या से कम है।

(स) विद्यालयों में उपलब्ध संरचनात्मक सुविधाओं के स्तर के साथ अधिगम उपलब्धि का संबंध है।

(द) जो विद्यालय बहुश्रेणी (मल्टी ग्रेड) अध्यापन में लगे हुए हैं उन विद्यालयों में अधिगम उपलब्धि कम है।

(य) अध्यापक प्रशिक्षण का संबंध अधिगम उपलब्धि के साथ जुड़ा हुआ है।

(र) गृहकार्य (होमवर्क) भी अधिगम उपलब्धि में सुनिश्चित रूप से योगदान देता है।

(ल) सभी बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध होने से अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

(व) बालक और बालिकाओं के बीच अधिगम उपलब्धि

में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई पड़ता।

(श) शिक्षित अभिभावकों के बच्चे अशिक्षित घरानों के बच्चों की अपेक्षा पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

(ष) शहरी इलाकों के सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा उपलब्धि का स्तर निजी विद्यालयों में ऊंचा है।

(स) शहरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी ज्यादा बेहतर हैं।

(ह) विद्यालयों के आंतरिक प्रबंध का प्रभाव अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता पर पड़ता है। जो विद्यालय मासिक और वार्षिक योजनाएं बनाते हैं और अध्यापन के लिए पूर्व निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करते हैं और बच्चों का नियमित रूप से मूल्यांकन करते हैं उनका प्रदर्शन ऐसे उन विद्यालयों की तुलना में अधिक बेहतर है जो ऐसी प्रणाली का अनुपालन नहीं करते। भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रधानाध्यापक की भूमिका अहम है जो कि विद्यालयों की पूर्वनिर्धारित गतिविधियों की सारणी के अनुपालन में अपनी अकादमिक नेतृत्व की भूमिका अदा करता है।

4. आंध्र प्रदेश के आदिवासी और उपयोजना क्षेत्रों के शैक्षिक विकास का अध्ययन

इस अध्ययन के लिए रु. 1,15,000/- की राशि मंजूर की गई थी। यह अध्ययन डॉ. (सुश्री) के.सुजाता, परियोजना निदेशक के संचालन में संपन्न हुआ।

भारत में आजादी के बाद आदिवासी विकास के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों और कार्यप्रणाली में काफी बदलाव आया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना बनाते समय पिछले अनुभवों, व्यापक योजनाओं और समुचित प्रबंध प्रणाली को मद्देनजर रखा गया था। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास योजना के लिए समुचित विकास रणनीति और कार्यप्रणाली पर ध्यान दिया गया।

आदिवासी उपक्षेत्रीय कार्यप्रणाली और समेकित आदिवासी विकास की सामान्य विशेषताओं को देखने से स्पष्ट होता है कि आदिवासियों के शैक्षिक विकास की नई रणनीतियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने की जरूरत है।

निष्कर्ष

1. नीतिगत ढांचे में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के माध्यम पर खास बल दिया गया।
2. आदिवासी विकास कार्यक्रमों में लगे विभिन्न अभिकरणों और निकायों पर नियंत्रण के संदर्भ में आदिवासी विकास कार्यक्रमों की प्रशासनिक कार्य प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
3. आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा के मूल्यांकन में क्षेत्रीय असमानताएं साफतौर पर दिखाई देती हैं।
4. आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता वांछित स्तर से ऊंची है।
5. आदिवासी लोगों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है।
6. संस्थानों की कारगुजारियां वांछित स्तर से नीचे पाई गईं।
7. यह पाया गया कि शिक्षा और विकास अभिकरणों विशेषकर स्थानीय निकायों और कल्याण विभाग के बीच तनाव और टकराव की भावना विद्यमान है जोकि अभी भी कार्य की प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा है।

1991-92

5. भारत के वर्तमान पत्राचार संस्थानों में शिक्षण-अधिगम के प्रबंध के लिए अपनाई गई प्रणालियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस परियोजना के लिए नीपा सहायता योजना के तहत रु. 72,300/- की राशि मंजूर की गई थी। यह अध्ययन डॉ. एच.सी.एस. राथौड़, प्रवक्ता, शिक्षा विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने किया।

अध्ययन के उद्देश्य

1. निम्नांकित संदर्भों में शिक्षण-अधिगम के प्रबंध के लिए प्रयुक्त वर्तमान प्रणाली का अध्ययन करना :

   (i) अधिगम सामग्रियों का विकास, जैसे— सामग्री लेखन की प्रक्रिया और मूल्यांकन (दूरवर्ती शिक्षण और स्टाफ के प्रशिक्षण संबंधित अधिगम सामग्रियों की शैक्षिक उपयुक्तता का पता लगाना) और पाठ्यक्रम सामग्रियों का उत्पादन।

   (ii) अधिगम सामग्रियों का वितरण यानी वितरण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कार्य प्रणाली।

   (iii) निम्न कार्यों के पुनर्निवेशन में प्रयोग की जाने वाली विधियां :

      (अ) **अध्ययन कार्य** : उनके स्वरूप, बनाने की विधियां, प्रतिक्रिया की प्रक्रिया और समय पर वापसी इत्यादि।

      (ब) **व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम** : उनकी आवृत्ति, स्वरूप, प्रक्रिया और उद्देश्य आदि।

      (स) **ट्यूटोरियल्स और किसी अन्य प्रकार के मार्गदर्शन व परामर्श** : इनकी आवृति, स्वरूप प्रक्रिया और लाभकारी उद्देश्य इत्यादि।

   (iv) **अध्ययन केंद्रः** उनकी स्थितियां, संख्या, आकार, छात्रों की संख्या, सुविधाएं, उपयोग में लाई गई सुविधाएं, पूरे किए गए लक्ष्य इत्यादि।

   (v) **परीक्षाएं और छात्रों का मूल्यांकन** : छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन परीक्षा का स्वरूप, आवृत्ति इत्यादि।

2. प्रथम उद्देश्य के तहत किए गए अध्ययन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना :

   (अ) स्वअध्ययन सामग्रियों के रूप में अधिगम सामग्रियों की गुणवत्ता और उपयुक्तता।

   (ब) अधिगम सामग्रियों की वितरण प्रणाली की उपयुक्तता और इनका व्यावहारिक रूप।

   (स) दिए गए अध्ययन कार्य की गुणवत्ता, उन पर की गई प्रतिक्रिया की प्रभावी क्षमता और वापसी के समय की अनुकूलता।

   (द) निजी संपर्क कार्यक्रमों की प्रणाली की गुणवत्ता और प्रासंगिकता।

   (य) अन्य पुनर्निवेशन प्रणाली के माध्यम, जैसे अध्ययन केंद्रों में ट्यूटोरियल, मार्गदर्शिका, परामर्श और अन्य सेवाओं की गुणवत्ता और प्रासंगिकता

3. नवीनतम प्रयोगों, नवाचारों, दूरवर्ती शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनाई गई प्रवृतियों से उपर्युक्त अ,ब,स,द के अध्ययनों को सैद्धांतिक रूप से तुलना करने पर यह सुझाव दिया गया है कि संसाधनों के दुरुपयोग और उनकी पुनरावृति पर रोक लगाने के लिए प्रबंध की रणनीतियों पर विशेष बल देने की जरूरत है।

परिणाम और निष्कर्ष

विस्तृत प्रश्नावलियों के कारण इस अध्ययन के लिए व्यापक

रूप से आंकड़े प्राप्त हुए हैं। इन्हें इस सारांश में प्रस्तुत करने में बहुत अधिक कठिनाई है। अतः राष्ट्रीय स्तर पर पत्राचार शिक्षा की योजना और प्रबंध के लिए निहितार्थों सहित महत्वपूर्ण परिणाम और निष्कर्ष निम्नांकित उपखंडों में दिए जा रहे हैं :

सामग्री प्रणाली : भारत के वर्तमान पत्राचार अध्ययन संस्थानों में पाठ्यक्रम सामग्रियों के विकास के प्रबंध के लिए अपनाई गई प्रणालियां इस प्रकार हैं; (i) अपरिवर्तनीय है, सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से शिक्षण/विशेष लिखते हैं (ii) नवाचार की कमी है, सामग्री लेखन व मूल्यांकन के प्रस्तुतीकरण के साथ माध्यमों का कोई तालमेल नहीं है; (iii) पाठ्य सामग्रियां उच्च शिक्षात्मक गुणवत्ता की नहीं हैं और दूरवर्ती अध्ययन में छात्रों की जरूरतों के अनुकूल नहीं हैं।

प्रेषण प्रणाली : अधिकांश छात्र (67.23%) दिए गए अध्ययन के बोझ से संतुष्ट हैं। वर्तमान प्रेषण प्रणाली से 56.4% छात्र खुश हैं। सामग्री की गुणवत्ता से 67.80% छात्र संतुष्ट हैं और सामग्रियों के प्रेषण में लाई गई तेजी से 46.33% छात्र संतुष्ट हैं।

अध्ययन कार्यप्रणाली : प्रेषण नीतियों के अनुसार पाठ्य सामग्रियों के साथ नियत अंतराल पर अध्ययन कार्य भेज दिए जाते हैं। यद्यपि अध्ययन से पता चलता है कि पत्राचार अध्ययन केंद्र अध्ययन कार्यों के उत्तरपत्रों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के संप्रेषण में पूरी तरह से असफल हैं। 50% संस्थानों में अध्ययन कार्यों को प्रस्तुत करना ऐच्छिक है जबकि 35.17% संस्थानों में अनिवार्य है। 7.14% संस्थानों में न तो अनिवार्य ही है और न ही ऐच्छिक है। 50% संस्थान उत्तरपत्रों को ठीक करके भेजते हैं जबकि 42.05% संस्थान सिर्फ टिप्पणी के साथ उत्तरपत्र भेज देते हैं।

निजी संपर्क प्रणाली : इस अध्ययन के पर्याप्त साक्ष्यों से निष्कर्ष निकलता है कि भारत के पत्राचार अध्ययन संस्थान निजी संपर्क कार्यक्रमों के दौरान सिर्फ आमने-सामने के सत्र पर निर्भर हैं। दूरवर्ती अध्ययन में शिक्षक द्वारा दिए गए अध्ययन कार्य के मूल्यांकन के अंक के माध्यम से परस्पर संप्रेषण का अभाव है।

अध्ययन केंद्र समर्थन प्रणाली : इस अध्ययन के प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि शायद ही पत्राचार संस्थानों द्वारा अध्ययन केंद्रों को समर्थनकारी मदद मिलती है। 35.71% संस्थानों के पास अध्ययन केंद्र हैं। इनमें से 14.28% संस्थानों के पास प्रत्येक में केवल एक अध्ययन केंद्र है और 21.42% संस्थानों के पास प्रत्येक में पांच अध्ययन केंद्र हैं। अध्ययन के लिए 17 अध्ययन केंद्रों का चयन किया गया था जिनमें से नगर मुख्यालय या उपनगरी क्षेत्रों के 11 केंद्रों के दौरे करने का मौका मिला। आश्चर्य की बात यह है कि सभी केंद्र मुख्य नगरों या उप-नगरों में स्थित हैं। अतः इन संस्थानों के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी अध्ययन केंद्र की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

कुछ दूसरी समर्थन प्रणाली : पूर्वोक्त समर्थन सेवाओं के अलावा नए सिरे से अध्ययन शुरु करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने और बीच में अध्ययन छोड़ने वालों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान के शिक्षकों द्वारा दाखिलापूर्व मार्गदर्शन/परामर्श, शिक्षण की व्यवस्था का अध्ययन किया गया।

मूल्यांकन प्रणाली : दूरवर्ती शिक्षा के छात्रों के कार्य निष्पादन के मूल्यांक के तरीके और कार्यप्रणाली संबंधी कार्यकलापों का भी अध्ययन किया गया। संतत् मूल्यांकन संबंधी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि 78.57% संस्थानों में इस प्रणाली के कुछ तत्व मौजूद हैं। उदाहरणार्थ, 42.85% संस्थान प्रारूपित मूल्यांकन के लिए छात्रों को दिए गए अध्ययन कार्यों पर निर्भर होते हैं। 21.42% संस्थान आवर्ती/अंतरमाध्य लिखित परीक्षाएं लेते हैं और 14.28% आवर्ती मौखिक परीक्षाएं लेते हैं। 50% संस्थानों में सतत् मूल्यांकन अनिवार्य है और यह पाठ्यक्रम पूरा होने पर किया जाता है। 38.88% संस्थानों में सतत् मूल्यांकन छात्रों के कार्यनिष्पादन के

संचारेक्षण के लिए किया जाता हैं जबकि 33.33% संस्थानों में यह मूल्यांकन अंतिम परीक्षा में बैठने की योग्यता निर्धारित करते हैं। केवल 11.11% संस्थानों में सतत् मूल्यांकन के अंकों को अंतिम परीक्षा के अंकों के साथ शामिल किया जाता है।

6. मेघालय और मिजोरम की साक्षरता स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों का पायलट अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

इस पायलट परियोजना के लिए नीपा सहायता योजना के अंतर्गत रु. 32,500/- की राशि मंजूर की गई थी। यह अध्ययन डॉ. एस. होम चौधरी, नेहू, शिलांग ने किया।

अध्ययन के उद्देश्य

(1) जिलेवार आबादी की वृद्धि दर और साक्षरता का अध्ययन करना।

(2) प्रखंडवार साक्षरता में वृद्धि और साक्षरता में असमानताओं के विशेष संदर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण करना।

(3) मेघालय और मिज़ोरम में शिक्षा के प्रथम स्तर की वृद्धि के प्रतिमान का विश्लेषण और अध्ययन करना।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

साक्षरता वृद्धि प्रतिमान : मिजोरम की पहाड़ियों में 1951 तक महिलाओं में साक्षरता का विस्तार धीमी गति से हुआ। 1961 से महिला साक्षरता में पुरुष के मुकाबले तेज वृद्धि हुई मगर 1981 से इसमें कमी आने लगी। 1991 में पुरुष और महिला की साक्षरता के बीच कम अंतर पाया गया। (5.79%)

मिजोरम आदिवासी बहुल इलाका है। यहां मिजो आदिवासी सर्वाधिक संख्या में साक्षर हैं।

साक्षरता में अंतर-जनपदीय असमानताएं पाई गईं जिनमें वृद्धि दर भी दृष्टिगत हुई। एजावल सर्वाधिक आबादी और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जिसमें 1971 में साक्षरता में तेजी आई। यह तेजी पूरे राज्य के प्रत्येक जनगणना काल के मुकाबले अधिक थी। (1971,1981 और 1991)

सिरद्विप (0.1064), खावाजल (0.1145) और लुगलेई प्रखंड (0.019) को छोड़कर वर्ष 1981 में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में पुरूष और महिला साक्षरता दरों के बीच असमानता राज्य के औसत सूचकांक (0.0991) से भी कम थी। वर्ष 1991 में इसमें व्यापक कमी आई और पूर्वी लुंगेदार (0.028) को छोड़कर सभी 11 प्रखंडों में असमानता सूचकांक राज्य के औसत सूचकांक (0.0608) से कम दिखाई दिया है। एजावल जिले के थिंगसुलतलिया और तालांगुम (अधिक आबादी वाले प्रखंड) में वास्तव में असमानता न के बराबर है।

विद्यालय सुविधाओं का विकास : 1894 से मिज़ोरम में विद्यालय खोलने की शुरुआत हुई। 1946 में राज्य में विद्यालयों की संख्या 274 हो गई। इनमें राज्य के उत्तरी भाग की पहाड़ियों में विद्यालयों की संख्या अधिक थी। 1951 में उत्तरी भाग के 66% गांवों में प्राथमिक विद्यालय थे। बाकी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय दूर-दूर तक बिखरे थे। 1961 में मिज़ो पर्वतीय इलाके के ग्रामीण क्षेत्र में 77.26% प्राथमिक विद्यालय थे। 1981 में 80.86% गांवों में प्राथमिक विद्यालय थे। उस वर्ष 94.59% ग्रामीण आबादी को प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त थीं।

दाखिले में वृद्धि प्रतिमान : वर्ष 1947 की दाखिला संख्या 14,754 से बढ़कर वर्ष 1990 में 1,03,686 हो गई।

1950 तक साक्षरता कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। वर्ष 1950-1960 के दौरान दाखिला दर में 57% की वृद्धि हुई जिसमें बालिकाओं के दाखिले दर में कुल वृद्धि 89.27% थी। वर्ष 1960 में प्रत्येक 100 लड़कों

पर लड़कियों की दाखिला संख्या 90 थी। वर्ष 1960-70 के दौरान दाखिला दर में 95.65% की ऊंची उछाल आई जिसमें लड़कियों की दाखिला दर में 101.01% की वृद्धि हुई थी। भागीदारी दर में सुधार हुआ। 95 लड़कियां प्रति 100 लड़के का अनुपात हो गया। उसके बाद के दशक में वृद्धि में कमी आई।

जारी अध्ययन

1. विद्यालय मानचित्रण परियोजना

विद्यालय मानचित्रण परियोजना के लिए रु. 8.83 लाख की राशि मंजूर की गई है। श्री.एम.एम. कपूर, परियोजना निदेशक, प्रो.एल.सी.सिंह, परियोजना अध्येता; श्री आर.के. सोलंकी, वरिष्ठ शोध अधिकारी और सुश्री पुष्पा कथूरिया, परियोजना सहायक इस परियोजना दल में शामिल हैं।

इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : राज्यों और संघ क्षेत्र राज्यों में शैक्षिक सुविधाओं के मानदंड, मानक और प्रावधान के विशेष संदर्भ में स्थानीय योजना की वर्तमान प्रक्रियाओं और प्रणालियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना, क्षेत्रीय स्टाफ के मार्गदर्शन के लिए विद्यालय मानचित्रण पर संदर्शिका तैयार करना और राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों के क्षेत्रीय स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्ति तैयार करने के उद्देश्य से संसाधन व्यक्तियों के लिए विद्यालय मानचित्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

यह अध्ययन विशेष रूप से विद्यालय स्तर और सामान्य शिक्षा तक सीमित होगा। केवल चुने गए राज्यों में ही वर्तमान प्रक्रियाओं और प्रणालियों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाएगा। चुने गए राज्यों में से कुछ राज्यों में नगर योजना के एक भाग के रूप में नगरीय क्षेत्र में विद्यालय मानचित्रण का अध्ययन किया जाएगा।

कार्यक्रम सलाहकार समिति के आग्रह पर अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली को भी इस परियोजना में शामिल किया गया। मिज़ोरम और तमिलनाडु की प्रखंड योजनाएं अंतिम रूप से तैयार कर ली गई हैं और अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा असम की योजनाएं अभी प्राप्त हुई हैं। राज्यों से अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त होने पर प्रखंड योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है।

2. द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण

इस परियोजना के लिए रु. 17.04 लाख की राशि मंजूर की गई हैं। श्री एम.एम.कपूर, परियोजना अध्येता, डॉ.जे.सी.गोयल, परियोजना अध्येता; डॉ. (श्रीमती) एस. मजूमदार, परियोजना सह अध्येता; श्री आर.एस. त्यागी, परियोजना सह अध्येता; श्री वी.एस. आलोक और श्री ए. के. सिन्हा, परियोजना सहायक और श्री भारत भूषण, परियोजना मानचित्रकार परियोजना दल में शामिल हैं।

इस सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं : केंद्र सहित राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों के शैक्षिक प्रशासन की वर्तमान प्रक्रियाओं, प्रणालियों और ढांचे की पड़ताल करना एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक योजना और प्रबंध की प्रणाली के अनुसार आवश्यक बदलाव के लिए कार्यवाही योजना बनाने में मदद करना, सांस्थानिक प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, शिक्षा की न्यायिक पीठ, शैक्षिक योजना और कमजोर वर्गों की शिक्षा की समस्याएं और मुद्दों समेत शैक्षिक संगठनों और प्रशासन प्रणालियों पर राष्ट्रीय स्तर की विषयगत रिपोर्ट तैयार करना तथा विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में चुनिंदा नवाचारों पर केस अध्ययन करना।

इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार समेत सभी राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों में सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। इसमें शैक्षिक प्रशासन के सभी क्षेत्रों और स्तरों को शामिल किया जाएगा।

अनेक राज्यों से सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हुईं और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्टों की समीक्षा के लिए नीपा में 23 नवंबर 1991 को राष्ट्रीय सलाहकार समिति की उपसमिति की बैठक हुई। उप-समिति की सिफारिशों के

आधार पर रिपोर्टों में संशोधन किया जा रहा है। शैक्षिक प्रशासन पर संदर्भ सूची, राज्यों के प्रशासनिक ढांचे और शैक्षिक संकेतकों को अंतिम रूप दिया गया।

3. लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध : निहितार्थ और भारत के लिए सीख

इस परियोजना के लिए रु. 1, 46, 200/- की राशि मंजूर की गई थी। यह परियोजना अध्ययन डॉ. (श्रीमती) अंजना मंगलागिरी, परियोजना निदेशक कर रही हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

- अनौपचारिक शिक्षा की योजना की प्रक्रिया और ढांचे की समीक्षा करना,
- अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के गठन और प्रबंधन की समीक्षा करना,
- शिक्षा में अंतर-क्षेत्रीय समझ और सहयोग को मद्देनज़र रखते हुए तुलनात्मक शिक्षा के विकास में सहयोग करना।

यह परिकल्पना की जाती है कि अनौपचारिक शिक्षा से कम खर्चे और नए कौशलों के द्वारा शिक्षा स्तर में प्रभावी विकास लाया जा सकता है और तीसरी दुनिया के देशों के निर्धन वर्ग की शैक्षिक जरूरतों की पूर्ति की जा सकती है। लैटिन अमरीका प्रायद्वीप के पास एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में अनौपचारिक शिक्षा का व्यापक अनुभव है। वहां यह देखने को मिला है कि प्राथमिक और व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से पिछड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य की पूर्ति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई है। प्रणालीबद्ध प्रयास के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग इसका लाभ नहीं उठा पाता। इसका एक कारण यह है कि आज भी अनौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा विश्वसनीयता से नहीं देखा जाता। भारतीय परिप्रेक्ष्य के तहत विकेंद्रीकृत प्रणाली और सामुदायिक भागीदारी के विशेष संदर्भ में लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंधन संबंधी रणनीतियों की समीक्षा भी इस अध्ययन में शामिल है। अध्ययन से पता चलता है कि इन रणनीतियों की असफलता के कारणों में रणनीतियों और कार्यपद्धतियों को कारगर बनाने के बजाय देश द्वारा अपनाए गए विकास माडल की गत्यात्मकता पर अधिक बल दिया गया है। उद्देश्य से हटकर इस अध्ययन में मानवपूंजी माडल का आलोचनात्मक अध्ययन भी किया जा रहा है। इसके पीछे तर्क यह है कि सामान्य और विशिष्ट प्रशिक्षण के द्वारा निर्धनों की कार्यक्षमता में विकास किया जा सकता है जिससे उत्पादकता और निजी आय में वृद्धि हो सकती है। इस अध्ययन में दो सवाल उठते हैं : (अ) क्या शिक्षा की औपचारिक विश्वसनीयता के बगैर अनौपचारिक शिक्षा व्यवसायिक और जीवन स्तरों में बदलाव ला सकती है ? (ब) क्या विद्यमान मूल्यों और समाज के व्यवसायिक संस्तरण प्रक्रिया से जुड़े सामाजिक संस्थानों में बदलाव लाए बगैर अनौपचारिक शिक्षा सामाजिक-आर्थिक समानता के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती है।

इस अध्ययन में लैटिन अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंधन की रणनीतियों की समीक्षा और भारत में इनके निहितार्थ और सीख की तलाश के लिए अध्ययन जारी है।

यह अध्ययन लैटिन अमरीका की वर्तमान अनौपचारिक शिक्षा पर किए गए अनुसंधान अध्ययनों के आधार पर ही आधारित है।

4. भारत में अनुसूचित जातियों और गैर अनुसूचित जातियों के साक्षरता स्तरों के बीच की विषमताओं का जिलेवार विश्लेषण

इस परियोजना के लिए रु. 1,44,396.30 की राशि मंजूर की गई है। डॉ. वाई.पी. अग्रवाल, परियोजना निदेशक और डॉ. सुश्री सारिका सिबू, परियोजना सहायक परियोजना दल से संबद्ध हैं।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों के साक्षरता स्तरों के बीच की विषमताओं के कारकों की पड़ताल करना, अनुसूचित जातियों के विभिन्न इलाकों में साक्षरता प्रसार के देशकालिक प्रतिमानों की पहचान करना, गैर-अनुसूचित जातियों की आबादी की समान/असमान विशेषताओं का परीक्षण करना, साक्षरता स्तरों के बीच की खाई मापने की समुचित विधि का विकास करना, साक्षरता दरों के बीच के संबंधों, असमानताओं और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के बीच के संबंधों की समीक्षा करना और शिक्षाप्रणाली में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए क्षेत्र विशेष की नीतियों का प्रतिपादन करना।

साक्षरता स्तरों और अनुसूचित जातियों की भागीदारी से संबंधित आंकड़े संगणक में संसाधित किए गए। मानचित्र और आरेख बनाने का कार्य चल रहा है। 'अनुसूचित आबादी वितरण', और 'अनुसूचित जातियों में साक्षरता की स्थिति' शीषर्क से रिपोर्ट के दो अध्याय अंतिम रूप से तैयार किए गए।

5. शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता का प्रबंध : स्वायत्त कालेजों का प्रबंध

इस परियोजना के लिए रु. 1, 52, 100/- की राशि मंजूर की गई है। परियोजना दल में डॉ. (श्रीमती) के.सुधा राव, परियोजना निदेशक और श्री जार्ज मैथ्यू, परियोजना सहायक शामिल हैं।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : स्वायत्तता प्राप्त संस्थानों में स्वायत्तता के इस्तेमाल की विधियों और मार्गों का अध्ययन करना, कालेज स्वायत्तता के संगठनात्मक और कार्यात्मक मसलों का विश्लेषण करना, स्वायत्तता के प्रति छात्रों और शिक्षकों के दृष्टिकोणों का अध्ययन करना, स्तरीय कारगुजारी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कार्यों की पहचान करना, स्वायत्तता के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बदलाव लाने में कालेजों के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना, उच्चशिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए स्वायत्त कालेजों के लिए जरूरी समर्थ प्रबंध व्यवस्था की पहचान करना।

इस अध्ययन में उद्देश्यात्मक प्रतिदर्श विधि अपनाई जा रही है। दस्तावेज विश्लेषण तकनीक, प्रबंधन विशेषज्ञों, उच्च शिक्षा निदेशकों, उपकुलपतियों, संस्था प्रमुखों, स्वायत्त और गैर स्वायत्त कालेजों के शिक्षकों और छात्रों के साथ विचार-विमर्श द्वारा इस अध्ययन के लिए आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इसके अलावा स्वायत्तता के विविध पक्षों के अध्ययन के लिए प्रश्नावली विश्लेषण विधि का भी उपयोग किया जाता है।

आंध्रप्रदेश के 6, तमिलनाडु के 13 और राजस्थान के तीन कालेजों—राजकीय कालेज, अजमेर, कोटा, बीकानेर से आंकड़े एकत्र कर लिए गए हैं। आंकड़ों का विश्लेषण और समीक्षा कार्य चल रहा है।

6. शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी उपयोग—केस अध्ययन

इस परियोजना के लिए रु. 1,19,100.00 की राशि मंजूर की गई है। परियोजना दल में डॉ. जे.बी.जी. तिलक, परियोजना निदेशक और श्री के.डी. मूर्ति, परियोजना सहायक शामिल हैं।

अध्ययन के उद्देश्य हैं : एक तरफ सांस्थानिक शैक्षिक लागत और दूसरी तरफ सांस्थानिक निर्गत के आधार पर शिक्षा की लागत प्रभाविता का विश्लेषण करना, विभिन्न समयोपरि कार्यकलापों के लिए विद्यालय शिक्षा के वास्ते संसाधनों की लामबंदी और उपयोग के प्रतिमानों का विश्लेषण करना और लामबंदी/ उपयोग के प्रतिमानों में पाई जाने वाली विविधता के कारकों की समीक्षा करना।

यह अध्ययन जिले के प्रारंभिक प्रतिदर्श आंकड़े पर आधारित है। प्रश्नावलियां अंतिम रूप से तैयार कर ली गई हैं और उनका पूर्व परीक्षण भी किया जा चुका है। बहुत हद तक

आंकड़े भी एकत्र किए जा चुके हैं। आंकड़ा संसाधन कार्य चल रहा है।

7. उत्तरप्रदेश में सबके लिए शिक्षा

'उत्तरप्रदेश में सबके लिए शिक्षा—प्रारंभिक अध्ययन' परियोजना का कार्य श्री एस. सी. बेहर (भा.प्र.से.), सलाहकार कर रहे हैं। परियोजना सहायक के रूप में सुश्री सुनीता, सुश्री दीपा खारवाल और सुश्री पुष्पा कथूरिया हैं।

नीपा संकाय के सदस्यों ने परियोजना दस्तावेज का पुनरीक्षण किया। नीपा और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आयोजित बैठकों में आवश्यक संशोधनों/सुधारों के लिए सुझाव दिए गए। आवश्यक संशोधनों/सुधारों के सुझावों के साथ मूल दस्तावेज को राज्य के शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के पास भेज दिया गया है ताकि सुझावों के अनुसार संशोधन किया जा सके।

8. भारत के शैक्षिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएं—आधारभूत स्तर पर सामाजिक कल्याण के विशेष संदर्भ में शैक्षिक विषमताओं की पड़ताल

इस परियोजना के लिए रु. 3, 48, 840/- की राशि मंजूर है। परियोजना दल में डॉ. एस.सी. नुना, परियोजना निदेशक, सुश्री वासवी सरकार, परियोजना सहायक और श्री जमालुद्दीन फारूकी, परियोजना मानचित्रकार शामिल हैं।

परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं : विद्यालय स्तर पर शैक्षिक विकास की असमानताओं का विश्लेषण करना और असमानताओं को दूर करने के मार्गदर्शन के उद्देश्य से एक चक्रीय प्रणाली का विकास करना, शिक्षा और विकास के दूसरे अवयवों के बीच के परस्पर संबंधों का विश्लेषण करना एवं आधारभूत स्तरों पर समेकित योजना के ढांचे के विकास की दृष्टि से विकास की वर्तमान प्रणाली का मूल्यांकन करना।

आंकड़ा संग्रह की योजना का विकास किया गया। प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित आंकड़े एकत्र करके संसाधित किए गए। परियोजना के एक भाग के रूप में 'पंचवर्षीय योजनाओं में समेकित योजनाएं' शीर्षक से एक आलेख तैयार किया गया। पांचवा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण से सभी जिलों के नामांकन संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए और संगणक में उनका संसाधन किया गया। विभिन्न आंकड़ों की तालिकाएं तैयार की जा रही हैं।

9. शिक्षा की संगणकीकृत योजना (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

यह परियोजना शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है। इसके लिए रु. 12, 22, 534/- की राशि मंजूर की गई है। परियोजना दल में श्रीमती अनिता चोपड़ा, श्री पी. रघू राम राव, मु. अहमद अंसारी और श्री अरूप बनर्जी शामिल हैं।

फरवरी के पहले सप्ताह में एन.आइ.सी. में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 8 विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय संचारेक्षण ब्यूरो, एन.आइ.सी. और कोप परियोजना के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। इसके बाद फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह में हिमाचल प्रदेश के राज्य शिक्षा परिषद के आमंत्रण पर राज्य के सांख्यिकीय अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और बिहार में आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य चल रहा है। मध्यप्रदेश के 24 जिलों और उत्तरप्रदेश के इटावा जिले में आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य पूरा हो गया है।

इस दौरान राज्य स्तरीय प्रणाली के विकास और विश्लेषण का कार्य आरंभ किया गया।

10. 'प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण–1991-92' का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

इस परियोजना के लिए शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 10,000,00/- की राशि मंजूर की गई है। परियोजना दल में श्री.एम.एम. कपूर, परियोजना निदेशक डॉ. डी.एन अब्रोल , परियोजना संयोजक, डॉ.जी.पी. सिंह, परियोजना सह अध्येता शामिल हैं।

इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धियों के संचारेक्षण के लिए आयु वर्ग 11+ से 13 + तक कक्षा V की शिक्षा अथवा अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में इसके समतुल्य स्तर की शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों से संबंधित आंकड़ा एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श माडल का विकास करना और राज्य/संघ क्षेत्र राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतिदर्श माडल के माध्यम से आंकड़े एकत्र करना, आंकड़ों को संकलित करना तथा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करना।

25 राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करके उसकी प्रतियां शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और परियोजना सलाहकार समिति को भेजी गईं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बैठक में 'प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संचारेक्षण के लिए वहु पक्षीय संकेतक विषय पर तैयार एक आलेख पर विचार-विमर्श किया गया। संचारेक्षण में वहु पक्षीय संकेतकों से संबंधित 5 तालिकाओं का उपयोग किया जाना है। (जैसे—आधारभूत नामांकन अनुपात, प्रवेश दर, सफलता दर, कक्षावार प्रतिधारण दर) 32 राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों के इन आंकड़ों को संगणक में संसाधित करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया।

शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से परामर्श और गहन विचार विमर्श के बाद इस परियोजना के दूसरे चरण के परियोजना प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भेज दिया गया।

11. शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग (यूनेस्को प्रायोजित)

इस परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा 20,000 अमरीकी डालर की राशि मंजूर की गई है। परियोजना दल में प्रो. श्रीप्रकाश, परियोजना निदेशक, डॉ. अरुण सी. मेहता, डॉ. (सुश्री) रंजना श्रीवास्तव, डॉ. एस.एम.आइ.ए. ज़ैदी और सुश्री तरुज्योति बुड़ागोहाई, सुश्री सुमित्रा चौधरी, और सुश्री आभा अग्रवाल शामिल हैं।

इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं : वर्तमान आंकड़ा प्रणाली में अनुपस्थित मुख्य सांख्यिकीय अवयवों की पहचान करना; आंकड़ा कालेज की समय सीमा, आंकड़ा संसाधन और वर्तमान आंकड़ा की उपयोगिता के मानदंड की समीक्षा करना, वर्तमान में एकत्रित आंकड़ों की विश्वसनीयता की परख करना, अनुपस्थित अवयवों की पहचान के बाद उनके आधार पर आंकड़ा संग्रह के प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीकों का विकास करना और तकनीकों का व्यावहारिक परीक्षण करना एवं योजना के उद्देश्य से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना।

'शैक्षिक आंकड़ों की कमियां और सीमाएं' शीर्षक से एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की गई और उसे पेरिस स्थित यूनेस्को कार्यालय को भेजा गया।

प्रश्नावलियों के हिंदी और गुजराती अनुवाद तैयार किए गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गुजरात के गांधी नगर और पंचमहल जिले में क्षेत्रीय कार्य चल रहा है।

12. भारतीय विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंध (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

यह परियोजना नीपा सहायता योजना के अंतर्गत है और इसके लिए रु. 48, 000/- की राशि मंजूर की गई है। इस

परियोजना पर डॉ. मालती सोमैया, भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर अध्ययन कर रही है।

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं : भारतीय विश्वविद्यालयों के लक्ष्य, विषय, सांगठनिक स्थिति और कार्यप्रणालियों के सापेक्ष उनके वित्तीय कार्यकलापों के बदलते संदर्भ और फलकों को समझना, विश्वविद्यालयों के वित्तीय कार्यकलापों की शर्तों और कार्य के दबावों की पहचान करना, संस्थागत स्तर पर वित्तीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के सांगठनिक ढांचे की आलोचनात्मक समीक्षा करना, कालेजों और विभागों, जैसे इकाई स्तरों पर नीतिगत और कार्यगत दिशाओं के बीच वित्तीय हस्तगन अधिकारों और विविध संबंधों की प्रणाली का परीक्षण करना और विश्वविद्यालयों के विभिन्न कार्मिकों को वित्तीय प्रबंधन के कौशलों में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के क्षेत्रों की पहचान करना।

13. तमिलनाडु में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबंधन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

नीपा सहायता योजना के अंतर्गत इस परियोजना अध्ययन के लिए रु. 63,000/- की राशि मंजूर की गई है। यह अध्ययन डॉ. सी. सुब्रमणिया पिल्लई, प्रोफेसर और अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई ने अपने हाथ में लिया है।

इस अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं : तमिलनाडु में उच्च शिक्षा के स्तर पर रेडियो, टी.वी. और वी.डी.ओ. प्रौद्योगिकियों के हार्डवेअर और साफ्टवेअर पक्षों के संदर्भ में अब तक की प्रगति की समीक्षा करना, यह पता करना कि अब तक इन प्रौद्योगिकियों का संकाय ने कितना उपयोग किया और इनकी संभावित उपयोगिता क्या थी, इन प्रौद्योगिकियों के प्रबंधन संबंधी कमियों को उजागर करना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अध्ययन में प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समुचित सुझाव देना।

आंकड़ा संग्रह का कार्य संपन्न हो गया है। विभागाध्यक्षों और कालेजप्राचार्यों की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें परियोजना संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इस प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सुझावों के आधार पर परियोजना रिपोर्ट लिखने का कार्य चल रहा है।

14. भारत में कृषि स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर का लागत-लाभ अध्ययन (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

नीपा सहायता योजना के अंतर्गत इस परियोजना के लिए रु. 61,200/- की राशि मंजूर की गई है। यह अध्ययन डॉ. बी.सी.मेहता, प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर कर रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं : कृषि शिक्षा नीति में सुधार के लिए सुझाव देने के वास्ते राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के स्नातकों के रोजगार के अवसरों का विस्तृत मात्रात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना; कृषि शिक्षा की मांग और आपूर्ति का अध्ययन करना; कृषि शिक्षा की लागत प्रभाविता, उत्पाद तथा वित्तीय पक्षों का अध्ययन करना; कृषि स्नातकों के उर्ध्व और क्षैतिज गतिकी का अध्ययन करना; भारत में आर्थिक विकास के सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी प्रवेश नीति और निहितार्थों के मूल्यांकन के उद्देश्य से वर्तमान सत्र के कृषि स्नातकों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना और यह पता लगाना कि क्या कृषि शिक्षा के अभिविन्यास से सामाजिक निर्गत में वृद्धि की जा सकती है।

आंकड़े संबंधी कमियों की पहचान की गई। तालिकाकरण और विश्लेषण का कार्य चल रहा है।

15. बोंडा जनजातियों के मूल्यगत दृष्टिकोण और भागीदारी (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

नीपा सहायता योजना के अंतर्गत 11 मई, 1990 को 18 महीने की अवधि के लिए इस परियोजना हेतु रु. 50,000/- की राशि मंजूर की गई थी। यह अध्ययन प्रो. एल.के. महापत्र, अध्यक्ष, सामाजिक अनुसंधान और कार्यवाही संगठन, मुदुलीपाड़ा, कोरापुट, उड़ीसा कर रहे हैं।

1991-92

अध्ययन के उद्देश्य

- यह पता लगाना कि क्या विद्यालय जाने वाले छात्रों के माता-पिता छात्रों को अपनी शिक्षा ठीक प्रकार से पूरी करने के लिए विद्यालय में उनका पढ़ना पसंद करते हैं।
- यह पता करना कि क्या विद्यालय जाने वाले छात्र अपने परिवार व गांव के लिए घर तथा बस्ती के कृषि और वन संबंधी कार्यों में हाथ बंटाते हैं।
- 20 वोंडा लड़के और लड़कियों पर एक साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रायोगिक परीक्षण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन बच्चों पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है।
- जीवन और शिक्षा की बदलती भूमिका के संबंध में वोंडा के दृष्टिकोणों का मूल्यांकन प्रकाश में लाना जिसमें बच्चों के संबंध में उनके विचार भी हों।
- यह पता लगाना कि आवासीय आश्रम विद्यालय और आवासीय सेवाश्रम विद्यालयों की वर्तमान सुविधाओं से वोंडा किस हद तक लाभान्वित हो सकते हैं।
- विद्यालय छोड़ने वाले या कभी विद्यालय न जाने वाले बच्चों की गतिविधियों के आर्थिक मूल्य का पता लगाना।

गांव में विद्यालय के प्रति सजगता को देखते हुए दमुरीपाड़ा गांव के ग्रामीणों की राय से विद्यालय के लिए भूखंड की व्यवस्था की गई। दिसंबर, 1991 में विद्यालय खोल दिया गया और एक ऐसे शिक्षक की नियुक्ति की गई जो वोंडा जीवन और भाषा से भली-भांति परिचित है।

पहले महीने में बच्चों को दो समूहों में बांटकर खेलने के लिए छोड़ दिया गया।

नए अध्ययन

1. पांडिचेरी में शैक्षिक विकास– ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

पहले फ्रेंच एन्कलेव और अब संघ क्षेत्र राज्य पांडिचेरी में शैक्षिक विकास प्रणाली देखने से अनेक महत्वपूर्ण और सकारात्मक पक्ष सामने आते हैं। भारत संघ में शामिल होने के 35 वर्ष के भीतर पांडिचेरी में साक्षरता स्तर 55.85% तक पहुंच गया है जबकि भारत की औसत साक्षरता 36% ही है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन की स्थिति देखने से साफ जाहिर है कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की उल्लेखनीय सूची में इसका स्थान बेहतर कहा जा सकता है। विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं के प्रावधान का सतत विस्तार होता रहा है। इसका कारण यह है कि अन्य राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों के मुकाबले पांडिचेरी में शिक्षा के लिए सर्वाधिक संसाधन जुटाए गए हैं।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों के परीक्षा परिणाम तमिलनाडु के परिणामों से बेहतर हैं जबकि पांडिचेरी और तमिलनाडु की परीक्षाएं तमिलनाडु माध्यमिक शिक्षा परिषद के ही अधीन संचालित होती हैं। इससे शिक्षा की प्रबल आंतरिक क्षमता और बढ़िया कारगुजारी का पता चलता है। यही बात उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी है।

शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर ऐसा प्रेरणादायक विस्तार कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि इसके पीछे जनता की शिक्षा के प्रति पहले के फ्रांसीसी शासन की प्रतिबद्धता और 1954 में भारत में विलय के बाद सुनियोजित प्रयास और नीतिगत प्रतिबद्धता है।

यद्यपि प्रबंधन के दायरे में कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। प्रबंधन का शिक्षाप्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक प्रशासन के प्रतिमान, सांस्थानिक प्रबंधन, वृत्तिक क्षमता और शिक्षकों की पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण सहित उनकी संवर्गनीति और उपलब्ध सुविधाओं का संस्थानों द्वारा उपयोग संबंधी कार्यकलाप प्रबंधन में शामिल हैं।

उपर्युक्त पक्षों को देखते हुए पांडिचेरी की शिक्षाप्रणाली का निदान जरूरी है ताकि योजना और प्रबंधन के प्रति संशोधनात्मक कार्य किया जा सके। इस दृष्टिकोण से प्रस्तावित अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :

- फ्रांसीसी शासन के तहत पांडिचेरी के शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति और नीति का अध्ययन करना,
- भारत में शामिल होने के बाद पांडिचेरी की शिक्षा प्रणाली पर फ्रांसीसी प्रभाव का मूल्यांकन करना,
- पांडिचेरी में 1954 से हुए शैक्षिक विकास की आलोचनात्मक समीक्षा करना,
- योजना और प्रबंध के प्रमुख मसलों की पहचान करना और बदलते परिवेश में संशोधनात्मक कदम उठाने के लिए सुझाव देना।

अनुसंधान दल : डॉ. के. एस. मैथ्यू, डॉ. ए. मैथ्यू — परियोजना निदेशक
श्री सी.जे.चेल्हो, श्री वेंकटेसन — परियोजना सहायक

2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मूल्यांकात्मक अध्ययन (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

इस परियोजना के लिए शिक्षा विभाग, मानव संमाधन विकास मंत्रालय द्वारा रु. 6,72,000/- की राशि मंजूर की गई है। परियोजना दल में शामिल हैं : डा. एम. मुखोपाध्याय, परियोजना निदेशक, श्रीमती उषा अयंगर, परियोजना सह अध्येता, श्री जय देवन परियोजना सहायक।

अध्ययन के उद्देश्य

निम्नांकित की समीक्षा करना :

- विद्यालय में उपलब्ध संचार सुविधाएं, जैसे— रेडियो/श्रव्य कैसेट रिकार्डर, टी.वी./वीडियो कैसेट प्लेयर,
- विद्यालय में विभिन्न संचार सुविधाएं उपलब्ध होने की अवधि,
- संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली योजनाएं,
- संचार सेटों की कार्यात्मक स्थितियां—कार्य करने की हालत में,
- विद्यालय में सेट रखने का स्थान,
- समय सारणी का प्रावधान,
- संचार माध्यमों के उपयोग के लिए शिक्षकों का अभिविन्यास,
- कार्यक्रम आदि की आवृत्ति और उपयोग एवं देखने के तरीके,
- सेटों के रखरखाव—मरम्मत और बदलने के प्रावधान,
- कार्यक्रम के प्रति छात्रों की प्रतिक्रियाओं और शिक्षकों की उपयुक्तता, गुणवत्ता और सार्थकता आदि।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना का मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

यह परियोजना मंजूर कर ली गई है। इसके परियोजना दल में शामिल हैं : डॉ. के.जी. विरमानी, डॉ. (श्रीमती) कुसुम प्रेमी और सुश्री वाइ. जोसफीन

अध्ययन के उद्देश्य

- राज्यों और उनके जिलों में इस योजना की उपयोगिता के विस्तार का अध्ययन करना,
- पुरुष की तुलना में स्त्रियों और गैर अनुसूचित जातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों द्वारा इस योजना की उपयोगिता का पता लगाना,

- लाभान्वित छात्र-छात्राओं की आर्थिक-सामयिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना,
- विभिन्न राज्यों द्वारा प्रतिभा खोज के लिए अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रियाओं की आलोचनात्मक समीक्षा करना और प्रक्रियाओं की वैधता का अध्ययन करना।
- योजना के प्रबंधन ढांचे और उसके वास्तविक कार्यकलापों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना और कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना,
- छात्रवृत्तियों के भुगतान की विधि का अध्ययन करना और उसे और प्रभावी रूप से कारगर बनाने के लिए जरूरी कदमों का सुझाव देना,
- छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उत्थान में योजना के प्रभाव का अध्ययन करना,
- नवोदय विद्यालयों के खुलने के बाद इस योजना की प्रासंगिकता का अध्ययन करना,

इस परियोजना की अब तक की प्रगति इस प्रकार है :

- परियोजना के आठों उद्देश्यों से संबंधित आंकड़ों के स्वरूप पर विचार किया गया और आंकड़ों के संभावित स्रोतों का पता लगाया गया।
- प्रतिदर्श डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए तार्किक आधार पर 10 राज्यों/संघ क्षेत्र राज्यों को अध्ययन के लिए चुना गया।
- आंकड़ा संग्रह के लिए राज्यस्तर, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों और छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र-छात्राओं हेतु तीन प्रश्नावलियों का प्रस्ताव है। इसके लिए आंकड़ा संग्रह की युक्तियां तैयार की जा रही हैं।
- आंकड़ा संग्रह के लिए तैयार दो प्रपत्रों के माध्यम से छात्रवृत्ति की उपयोगिता से संबंधित 5 वर्ष (1985-86 से 1989-90 तक) के आंकड़े एकत्र करने का कार्य चल रहा है। मेघालय से सभी आंकड़े पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।
- मेघालय, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तरप्रदेश से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया संबंधी विवरण प्राप्त हो चुके हैं।

4. हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर के चुने हुए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का अध्ययन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

इस परियोजना के लिए रु. 97,000/- की राशि मंजूर की गई है। यह परियोजना अध्ययन डॉ. (श्रीमती) सुदेश मुखोपाध्याय और डॉ. (श्रीमती) प्रमिला मेनन कर रही हैं।

इस अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं :

- पूरे राज्य में जि.शि.प्र.सं. की योजना के कार्यान्वयन की सामान्य स्थिति और चुने गए जि.शि.प्र.सं. पर विशेष रूप से प्रकाश डालना,
- जिले की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों के संदर्भ में चुनिंदा जि.शि.प्र.सं. के शैक्षिक हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करना
- उपर्युक्त 1 और 2 और उपलब्ध आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के संदर्भ में जि.शि.प्र.सं. की स्थापना के बाद की गतिविधियों का सर्वेक्षण करना।
- अपनी गतिविधियों की रूपरेखा बनाने, उनके कार्यान्वयन और संचारेक्षण कार्यों के लिए जि.शि.प्र.सं. को जिले, राज्य और राष्ट्रीय अधिकरण से प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय और अकादमिक समर्थन सेवाओं का अध्ययन करना,

1991-92

* जि.शि.प्र.सं. को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संस्तुतियां प्रतिपादित करना।

हरियाणा के जि.शि.प्र.सं. से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं। अप्रैल 1992 तक इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। जम्मू और कश्मीर के जि.शि.प्र.सं. के आंकड़ों का अभी इंतजार है।

5. विद्यालय प्रधानाध्यापक के लिए जरूरी प्रशिक्षणों की पहचान करना (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

यह अध्ययन डॉ. (श्रीमती) एस.जोशी, अध्यक्ष, शैक्षिक प्रशासन विभाग, बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा, कर रही हैं। इसके लिए नीपा सहायता योजना के अंतर्गत रु. 9,800/- की राशि मंजूर की गई है।

सांस्थानिक प्रबंधन के संदर्भ में प्रबंध परिवर्तन दुनियाभर में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में सामने आया है। परिवर्तन के शुभारंभ और परिवर्तन की प्रक्रिया की कुंजी संस्था प्रमुख के हाथ में होती है। बूच (1973), हेवलाक (1971), हाउस (1981), मुखोपाध्याय (1981) इसे केंद्र में लाकर देखते हैं। यह आम धारणा है कि प्रबंधकीय गतिविधियों जैसे अकादमिक प्रबंधन के अलावा, अनुशासन, वित्तीय प्रशासन, अधिरचना प्रबंधन, स्टाफ विकास, सह पाठ्यचर्या प्रबंधन और बाह्य संबंधों से प्रधानाध्यापक पूरी तरह वाकिफ़ होता है। संस्थान के विकास के लिए अपेक्षित मानव क्षमता और संसाधनों के महत्तम विकास में भी प्रधानाध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मगर पाया गया है कि ये सभी गुण प्राचार्यों में नहीं मिलते।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से अपेक्षित भूमिकाओं संबंधी प्रशिक्षण के जरूरी तत्वों की पहचान करना है। अतः विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के कार्यक्षेत्र में आने वाले विविध पक्षों, जैसे—अकादमिक क्षेत्र, (ii) कार्मिक प्रबंधन, (iii) वित्तीय प्रबंधन, (iv) विद्यालय की योजना और अधिरचना, (v) बाह्य और आंतरिक संबंध, (vi) छात्र सेवाएं, (vii) प्राविधिक क्षमताएं और (viii) व्यवहारिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के जरूरी पक्षों की पहचान करना ही प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

अध्ययन के उद्देश्य

(अ) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के सामने आने वाली समस्याओं की समीक्षा करना,

(ब) प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण के उन प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें वे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं,

(स) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने की सलाह देना।

अध्याय 4

परामर्शकारी और अन्य सेवाएं

भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में परामर्शकारी, समर्थनकारी तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान करना संस्थान के प्रमुख कार्यों में से एक है। समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान के संकाय ने यूनेस्को/यू.एन.डी.पी तथा इसके सहयोगी आइ.आइ.इ.पी. जैसे संगठनों को परामर्शकारी सेवाएं प्रदान की हैं। संस्थान ने मानव संसाधन मंत्रालय को विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी सेवाएं भी प्रदान की हैं। संस्थान ने परिचर्चाओं में भाग लेकर, विशेषज्ञ/कार्यकारी दल के सदस्य बनकर बाह्य अभिकरणों के अनुदान द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में तकनीकी सेवाएं प्रदान करके तथा विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित योजनाबद्ध चर्चाओं में भाग लेकर ये सेवाएं प्रदान की हैं। इस वर्ष संस्थान ने योजना आयोग, राज्य लोक प्रशासन संस्थानों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा नवोदय विद्यालय समिति जैसे संगठनों को व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की।

संकाय ने राज्य सरकारों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में तथा विभिन्न मसलों पर विशेष रिपोर्ट तैयार करने में अपनी तकनीकी तथा व्यावसायिक समर्थन सेवाएं प्रदान की हैं।

समर्थ समिति की बैठकें

संस्थान के संकाय ने बिहार, केरल, मणिपुर, लक्षद्वीप तथा तमिलनाडु में राज्य स्तरीय समर्थ समिति की बैठकों में प्रतिनिधित्व किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बैठकें

केब समिति, संसदीय सलाहकार समिति, अनुदान सहयोग समिति (उच्च शिक्षा तथा स्वयंसेवी संगठनों के सहायता अनुदान पर) शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकों में संस्थान ने प्रतिनिधित्व किया।

योजना आयोग की बैठकें

संस्थान ने योजना आयोग में शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के शैक्षिक कार्यदल में प्रतिनिधित्व किया।

योजना आयोग द्वारा 'खुली शिक्षा' पर गठित केंद्रीय दल की बैठक में संस्थान ने प्रतिनिधित्व किया। संस्थान ने योजना आयोग की आठवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए आयोजित बैठकों में भी प्रतिनिधित्व किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठकें

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अकादमिक स्टाफ कालेजों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठकों में संस्थान ने भाग लिया तथा 'सबके लिए विश्वविद्यालय शिक्षा' विषय पर आयोजित बैठक में भी संस्थान की भागीदारी रही।

राज्य सरकारों के अनुरोध पर अध्ययन/परियोजनाएं

आंध्रप्रदेश सरकार के अनुरोध पर संस्थान द्वारा आंध्रप्रदेश में शिक्षा और विकास पर मोनोग्राफ तैयार किया गया। इसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर इसी विषय पर मोनोग्राफ तैयार किया गया।

1991-92

विशेष मसलों पर व्यावसायिक समर्थन

'सबके लिए बेसिक शिक्षा—उत्तरप्रदेश' विषय पर परियोजना के लिए संस्थान ने उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट तैयार करने में अपनी समर्थन सेवाएं प्रदान की। इस रिपोर्ट को परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक भेजा जाएगा। संस्थान ने 'लोक जुंबिश' नामक परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में भी अपना सहयोग दिया।

व्यावसायिक समर्थन

डॉ. जे.बी.जी. तिलक ने शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को 'लोक जुंबिश' परियोजना के संदर्भ में समर्थन सेवा प्रदान की।

'सबके लिए बेसिक शिक्षा— उत्तरप्रदेश' परियोजना में शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय को परियोजना से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने में परामर्शकारी सेवाएं प्रदान की।

डॉ. एम. एम. कपूर ने मानव संसाधन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही 'सबके लिए बेसिक शिक्षा' परियोजना के लिए अपना समर्थन प्रदान किया। शैक्षिक प्रबंध, विद्यालय मानचित्रण तथा लघु स्तर योजना के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा।

अरुणाचल प्रदेश के शैक्षिक विकास के लिए एजुकेशन कांसल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लंबी अवधि की संप्रेक्ष्य योजना पर चलाई जा रही परियोजना में मुख्य परामर्शदाता के रुप में कार्य किया।

डॉ. वाई. पी. अग्रवाल ने शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के 'सबके लिए बेसिक शिक्षा—उत्तर प्रदेश' परियोजना के दस्तावेज तैयार करने में सहयोग दिया।

डॉ. एन. वी. वर्गीस ने 'सबके लिए शिक्षा—उत्तरप्रदेश' परियोजना के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दस्तावेज तैयार करने में परामर्शकारी सहयोग दिया।

अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां/परामर्श

डॉ.जी.डी. शर्मा ने कैंब्रिज एजुकेशन कांसल्टैंट्स लिमिटेड, इंग्लैण्ड की ओर से यूनेस्को—यू.एन.डी.पी. कार्यक्रमों के तहत 'जिला स्तर का बजट और लागत तैयार करना" विषय पर घाना में सलाहकार का पदभार संभाला (1.3.1991 से 23.7.1991)

डॉ. एम. मुखोपाध्याय ने विश्व बैंक की बेसिक शिक्षा परियोजना के तहत दूरवर्ती शिक्षा विशेषज्ञ (परामर्शदाता) के रूप में साना, यमन में कार्य किया (27.1.1992 से 14.2.1992)

डॉ. आर गोविंद ने आइ.आइ.इ.पी. पेरिस में 'बेसिक शिक्षा सेवाओं की गुणवत्तता' परियोजना से संबंधित परियोजना में आवासीय अध्येता के रूप में कार्य किया। (8.2.1991 से 7.4.1991)

यूनेस्को, बैंकाक में साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए ए.पी.पी.इ.ए.एल. मार्गदर्शिका के संपादन और उसे अंतिम रूप देने में परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। (15.4.1991 से 26.4.1991 और 12.8.1991 से 28.8.1991)

डॉ. वाई.पी. अग्रवाल कैंब्रिज एजुकेशन कांसल्टैंट्स लि., यू. के. की ओर से यूनेस्को-यू.एन.डी.पी. की परियोजना 'नामांकन प्रक्षेपण और लागत आकलन' में परामर्शकारी सेवाएं प्रदान की। (अक्तूबर-नवंबर, 1991)

चीन की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में चीन का दौरा किया। इसके अतिरिक्त जून 1991 में 'बेसिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास : चीन और भारत के अनुभव' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। यह संगोष्ठी शंघाई मानव संसाधन योजना संस्थान, शंघाई, द्वारा आयोजित की गई थी।

डॉ. के सुधा राव को सी.आइ.इ.एस.इ., अमेरिका द्वारा सात

महीने के लिए जलब्राइट छात्रवृत्ति दी गई। इस दौरान उन्होंने हार्बर्ड विश्वविद्यालय, कैंब्रिज अमरीका के शिक्षा स्नातक संस्थान में 'अवस्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन पर संरचनात्मक प्रभाव' विषय पर अध्ययन किया।

आगंतुक/शिष्टमंडल

श्रीमती मीना सीतुल सिंह, निदेशिका, राष्ट्रीय शैक्षिक दृश्य-श्रव्य उत्पादन केंद्र, मॉरिशस ए.आइ.आर. कालेज ने 'भारत में दूरवर्ती शिक्षा के स्वरूप विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 11.9.1991 को संस्थान के संकाय तथा संयुक्त निदेशक महोदय से विचार विमर्श किया।

श्री अहमद सफी, सलाहकार--शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, तेहरान, इरान ने दिनांक 22.11.1991 को निदेशक महोदय तथा संयुक्त निदेशक महोदय से भेंट की तथा 'बेसिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा' विषय पर चर्चा की।

अफगानिस्तान के उपमंत्री डॉ. हिलाली तथा डॉ. अब्दुल वदूद वफ़ामाल दिनांक 18.2.1992 को संस्थान के संकाय तथा निदेशक महोदय से मिले तथा अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर चर्चा की।

श्री विक्तर ओरदोनोज, निदेशक, बेसिक शिक्षा, यूनेस्को, पेरिस ने दिनांक 28.2.1992 की शैक्षिक प्रबंध सूचना व्यवस्था विषय पर संस्थान के संकाय से परिचर्चा की।

चीनी शिष्टमंडल

एक उच्चस्तरीय चीनी शिष्टमंडल ने 29.10.1991 से 7.11.1991 तक भारत का दौरा किया। यह शिष्टमंडल तमिलनाडु और केरल राज्यों में भी गया। शिष्टमंडल ने 'भारत में शिक्षा का विकास' विषय पर नीपा के साथ विचार-विमर्श किया।

रूसी शिष्टमंडल

श्री वी.डी. शारडीकोब, अध्यक्ष, राज्य शिक्षा समिति के नेतृत्व में एक चार सदस्यी रूसी शिष्टमंडल ने दिनांक 16.12.1991 को संकाय के निदेशक से मिला। संस्थान के निदेशक से इन्होंने शैक्षिक योजनाकारों के सामने आने वाले वर्तमान मसलों पर चर्चा की। शिष्टमंडल ने नीपा से संबंध स्थापित करने में रुचि दिखाई।

विशेष क्षेत्रों में संस्थान का अकादमिक योगदान

संस्थान के संकाय ने अन्य शैक्षिक संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों व व्यावसायिक संगठनों को प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्य में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की हैं। संकाय में सरकारी समितियों/शिष्टमंडलों व अकादमिक संगठनों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। संकाय ने इन संगठनों के अनुसंधान से संबंधित विशेष क्षेत्रों में अपने प्रकाशनों के द्वारा अकादमिक सहयोग दिया तथा विभिन्न राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, देश के विभिन्न भागों में विद्यालयों तथा कालेजों विद्यालय शिक्षा के विभिन्न परिषदों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानों, शिक्षक कालेजों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, योजना आयोग, अकादमिक स्टाफ कालेजों, अनुप्रयुक्त मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान नगरीय मामलों के राष्ट्रीय संस्थान तथा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अकादमिक समर्थन दिया।

अनुबंध IV में संस्थान के अकादमिक योगदान का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है।

1991-92

अध्याय 5

पुस्तकालय, प्रलेखन और प्रकाशन सेवाएं

संस्थान के विविध प्रकार के अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधानों और अन्य अकादमिक गतिविधियों में पुस्तकालय, प्रलेखन और प्रकाशन विभागों की मदद ली जाती है। इनसे शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारी अनुभवों और सूचनाओं के प्रसार प्रचार में मदद मिलती है।

इनकी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

पुस्तकालय

संस्थान के पुस्तकालय में शैक्षिक योजना, प्रशासन और अंतरशास्त्रीय विषयों से संबंधित पुस्तकों का बहुत बढ़िया संग्रह है। यह पुस्तकालय वर्षों से शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों, विद्वानों, छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों को किसी प्रकार की विघ्न बाधा के बगैर पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं मुहैया कर रहा है। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र भौतिक सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित हैं तथा अध्ययन के लिए बढ़िया वातावरण भी उपलब्ध है।

वर्ष 1991-92 के दौरान 520 पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रलेख भी संग्रहीत किए गए। यू. एन. ओ., यूनेस्को, ओ. इ. सी. डी., आइ. एल. ओ., यूनीसेफ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों की रिपोर्टों के समृद्ध संग्रह के अलावा वर्तमान में पुस्तकालय में कल 45,098 पुस्तकें हैं।

जर्नल

पुस्तकालय में शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंध तथा अन्य सहायक क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुल 350 जर्नल आते हैं। इनमें प्रकाशित महत्वपूर्ण आलेखों का सूचीकरण किया जाता है। इस वर्ष इन जर्नलों से 2123 आलेखों को सूचीबद्ध किया गया।

समाचार पत्रों की कतरनें

पुस्तकों और जर्नलों के अलावा समाचारपत्रों में शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित प्रकाशित आलेखों/समाचारों के कतरनों का भी पुस्तकालय में संग्रह किया जाता है। वर्तमान में पुस्तकालय में 150 विषयों के कतरनों की फाइलें मौजूद हैं।

अमुद्रित सामग्री

वर्ष 1986 में पुस्तकालय को आधुनिक बनाने और बहुमाध्यमीय संचार केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से वीडियो, कैसेट, आडियो कैसेट, फिल्में, माइक्रो फिल्में मंगाई जा रही हैं। इस वर्ष के दौरान 1 वीडियो कैसेट और 10 माइक्रो फिल्मों का संग्रह किया गया। पुस्तकालय के वर्तमान संग्रह में 6 फिल्में, 34 वीडियो कैसेट, 80 आडियो कैसेट, 54 माइक्रो फिल्में और 58 माइक्रोफिचेज हैं।

पुस्तकों का वितरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के भागीदारों, संकाय तथा अन्य संस्थाओं को अंतर-पुस्तकालय ऋण के तहत कुल 58,090 दस्तावेज जारी किए गए। पुस्तकालय में शोधार्थियों ने 1,00,813 दस्तावेजों का उपयोग किया।

1991-92

समसामयिक जानकारी सेवा

शैक्षिक जर्नल : प्राप्त शीर्षक और उनकी विषय वस्तु

पाठकों को शैक्षिक जर्नलों की विषय वस्तु की समसामयिक जानकारी देने के उद्देश्य से एक पक्ष में प्राप्त सभी जर्नलों पर आधारित 'शैक्षिक जर्नल : शीर्षक और उनकी विषयवस्तु' नाम से पुस्तकालय ने नियमित रूप से पाक्षिक मिमियोग्राफ निकाले।

नीपा पुस्तकालय प्राप्तियां

प्रलेखों, नई पुस्तकों और रुचिकर आलेखों से पाठकों को नियमित रूप से अवगत कराने के लिए पुस्तकालय में शामिल किए गए नए दस्तावेजों, पुस्तकों और आलेखों की संगणकीकृत मासिक सूची भी तैयार की गई।

संदर्भ सूची

समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए पुस्तकालय ने 90 संदर्भ सूचियां तैयार की।

नीपा प्रलेखन सेवाएं

शैक्षिक नीति, योजना, प्रशासन और प्रबंध के क्षेत्र में कार्यरत, व्यक्तियों और विद्वानों दोनों के लिए नीपा प्रलेखन केंद्र में समसामयिक जानकारी सेवा की एक शृंखला तैयार की गई है। इस शृंखला के तहत संदर्भ सूचियां, पुस्तक समीक्षाएं, अनुसंधान अध्ययन और राज्यों की रिपोर्टें इत्यादि तैयार करने का प्रस्ताव है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सूचना संसाधन और पुनः प्राप्ति के महत्व और जरूरत को देखते हुए नीपा पुस्तकालय ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान तथा विभिन्न राज्यों व संघ राज्यों से कुल 21 पुस्तकालयाध्यक्षों ने भाग लिया।

प्रलेखन केंद्र

संस्थान के कार्यक्रमों के लिए प्रभावी सूचना आधार विशेषकर राज्यों और संघीय राज्यों की जरूरतों से संबंधित सूचना आधार प्रदान करने के लिए, प्रलेखन केंद्र शैक्षिक योजना और प्रशासन और शिक्षा संबंधी दस्तावेजों का संग्रह करता है। ये दस्तावेज प्रायः राज्यों/संघीय राज्यों के शिक्षा विभागों, जिला प्राधिकरणों तथा प्रादेशिक स्तर के संस्थानों द्वारा प्रकाशित होते हैं। केंद्र का प्रमुख कार्य जिला स्तर तक की सूचनाओं का संग्रह करना और उनका प्रचार-प्रसार करना है ताकि संस्थान सूचनाओं और दस्तावेजों को शुद्ध रूप से प्रतिपादित करने में सक्षम हो सके।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रलेखन केंद्र में 954 दस्तावेज़ शामिल किए गए। केंद्र के पास 12,954 दस्तावेज़ हैं। इनमें मुख्य दस्तावेज़ निम्न हैं : राज्य गजट, राज्य जनगणना हैंडबुक, शैक्षिक सर्वेक्षण, राज्य शैक्षिक योजना, पंचवर्षीय योजना, बजट, राज्य विश्वविद्यालय पुस्तिका, संदर्भ ग्रंथ और संदर्भ ग्रंथ सूची, प्रेस कतरनें, राज्य शैक्षिक संहिता अधिनियम, नियम और विनियम, प्रौद्योगिक आर्थिक और प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जिला गजट, जिला जनगणना, पुस्तिका, वार्षिक योजना, शैक्षिक योजना, जिला क्रय योजना, लीड बैंक रिपोर्ट, जिला प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जिला शैक्षिक सर्वेक्षण, जिला सांख्यिकी पुस्तिका, ग्राम और प्रखंड स्तरीय योजना तथा अध्ययन, अनुसंधान और परियोजना अध्ययन, संसाधन सूची अध्ययन, प्रौद्योगिक—आर्थिक सर्वेक्षण। शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में नवाचारी अनुभवों से संबंधित सूचनाओं का प्रसार प्रलेखन केंद्र निम्नांकित माध्यमों से करता है :

(1) शोधकर्ताओं तथा संकाय के सदस्यों के लिए चयनित सूचना प्रसार सेवा (च.सू.प्र.से.),

(2) मासिक 'भारत में शिक्षा' और प्रेस कतरन सेवा,

(3) प्रलेखन सूची,

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संदर्भ ग्रंथों का संकलन

1991-92

प्रकाशन

संस्थान की विभिन्न रिपोर्टों आदि के प्रकाशन में जरूरी सभी सुविधाएं प्रकाशन एकक प्रदान करता है। इसके अलावा एक मुख्य पत्राचार सूची की मदद से विभिन्न संस्थानों और संगठनों में प्रकाशित सामग्रियों का प्रचार-प्रसार भी प्रकाशन एकक ही करता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नांकित प्रकाशन निकाले गए :

शैक्षिक प्रशासकों तथा योजनाकारों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी

यह रिपोर्ट यूनेस्को-यू.एन.इ.पी. तथा आइ.इ.इ.पी. के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम के बारे में है। इसे संस्थान के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यह रिपोर्ट संगोष्ठी के उद्देश्य, कार्यक्रम रूपरेखा तथा प्रगति प्रस्तुत करती है। इसमें देशकालीन रिपोर्ट तथा सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए तकनीकी आलेखों का सारांश सम्मिलित है। यह रिपोर्ट पर्यावरण शिक्षा के सिंहावलोकन; अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा के विकास, पर्यावरण शिक्षा में शिक्षकों के प्रशिक्षण की रणनीति, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों में पर्यावरण शिक्षा; शैक्षिक पाठ्यक्रम के विकास का तथा पर्यावरण शिक्षा के प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है।

सबके लिए शिक्षा : सचित्र प्रस्तुतीकरण —पी. एन. त्यागी

सबके लिए शिक्षा पर सचित्र प्रस्तुतीकरण नीति विशेषज्ञों, वरिष्ठ प्रशासकों तथा शोधकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक प्रयास है। यह दस्तावेज निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया :

(i) संस्थानों, नामांकन, शिक्षकों तथा शैक्षिक वित्त जैसे महत्वपूर्ण शैक्षिक संकेतकों के व्यवहार के बारे में ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करना ;

(ii) जनांकीकीय व्यवहार विशेषतः विशिष्ट आयु वर्ग से संबंधित जनसंख्या के तथ्यों के बारे में जानकारी देना;

(iii) संगठनात्मक, शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक निवेश जैसे महत्वपूर्ण शैक्षिक क्षेत्रों में व परिणाम की गुणवत्ता जैसे शैक्षिक असंतुलनों की वर्तमान व्यवस्था प्रस्तुत करना;

(iv) शैक्षिक विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों विशेषतः प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा पर किए गए निवेशों तथा उपलब्धियों को प्रस्तुत करना।

शिक्षा के इन क्षेत्रों से संबंधित एक तुलनीय समय शृंखला तथा विशेष आंकड़े प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। इन उद्देश्यों की प्रस्तुति के लिए दस्तावेज को सात भागों में बांटा गया है। (i) प्रशासनिक ढांचा; (2) जनांकीकी; (3) साक्षरता; (4) संस्थान; (5) शिक्षक; (6) नामांकन; तथा (7) शिक्षा पर व्यय।

एक तुलनीय समय शृंखला का निर्माण करने का हर संभव प्रयास किया गया। कुछ मामलों में पूर्ण समय शृंखला उपलब्ध नहीं है, परिणामस्वरूप अनेक मसलों पर तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत किए गए। प्रकाशन का काम जब समाप्ति पर था तभी 1991 की जनगणना के परिणाम उपलब्ध हुए। 1991 की जनगणना से संबंधित आंकड़े भी इस दस्तावेज में सम्मिलित किए गए हैं।

शैक्षिक योजनाकारों तथा प्रशासकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर अखिल भारतीय सम्मेलन (नई दिल्ली 1991)

यह रिपोर्ट यूनेस्को-यू.एन.इ.पी के तत्वावधान में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित है। इस कार्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा की रूपरेखा, योजना तथा प्रबंध के क्षेत्र में कार्यरत शैक्षिक कार्मिकों ने भाग लिया। यह रिपोर्ट निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित उद्देश्यों, कार्यक्रम रूपरेखा तथा कार्यवाही योजना को प्रस्तुत करती है। ये मुद्दे हैं :

(i) पर्यावरण और विकास

(ii) पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे;

(iii) पर्यावरण शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए विधियों तथा रणनीतियों का पता लगाना।

कोप/डी.एस.एस. (शिक्षा की संगणकीकृत योजना) जिला स्तर के प्रयोक्ताओं के लिए मार्गदर्शिका

कोप/डी.एस.एस. प्रयोक्ता मार्गदर्शिका में कोप/डी.एस.एस. साफ्टवेअर से संबंधित सूचनाएं हैं। इससे साफ्टवेअर संचालित करने और अपनी जरूरत के अनुसार सूचनाएं प्राप्त करने में प्रयोक्ता को मार्गदर्शन मिलता है। इस मार्गदर्शिका में आंकड़ा शब्दकोश के अलावा हार्डवेअर और साफ्टवेअर संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी दिशानिर्देश भी दिए गए हैं। यह प्रयोक्ता मार्गदर्शिका पहली बार तैयार की गई है। यह आशा की जाती है कि इस मार्गदर्शिका के अध्ययन के साथ-साथ प्रयोक्ता कोप/डी.एस.एस. साफ्टवेअर में आंकड़ा भरने और रिपोर्टें निकालने में समर्थ होंगे।

जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन

निम्नांकित विषयों पर विशेषांक प्रकाशित किए गए

1-4. जिल्द IV अंक 2, अप्रैल 1990; जिल्द IV अंक 3, जुलाई 1990; जिल्द IV अंक 4, अक्तूबर 1990 तथा जिल्द V अंक 1 जनवरी 1991

5. 'शिक्षा का अर्थशास्त्र' विषय पर विशेष अंक जिल्द V अंक 2, अप्रैल 1991

6-7. 'शैक्षिक प्रशासन' तथा 'कामकाजी बच्चों की शिक्षा' विषय पर विशेषांक (हिन्दी अनुवाद)

8-9. जिल्द IV अंक 2, अप्रैल 1990 तथा जिल्द IV अंक 3, जुलाई 1990 (हिंदी अनुवाद)

प्रेस में

निम्नांकित प्रकाशन प्रेस में हैं :

(1) जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन जिल्द V अंक 3, जुलाई 1991

(2) जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन जिल्द IV, अंक 4, अक्तूबर 1990 (हिन्दी अनुवाद)

मिमियोग्राफ प्रकाशन

संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्टें और अनुसंधान अध्ययनों के मिमियोग्राफ भी प्रकाशित किए गए।

1991-92

अध्याय 6

प्रशासन और वित्त

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (शिक्षा विभाग) द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। संस्थान के प्रमुख प्राधिकरण निम्न हैं :

(अ) अध्यक्ष

(ब) उपाध्यक्ष

(स) परिषद

(द) कार्यकारी समिति

(य) वित्त समिति

(र) योजना और कार्यक्रम समिति

निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। प्रशासन, वित्त, प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी मामलों में निदेशक की मदद के लिए कार्यकारी निदेशक होता है। इसे अब संयुक्त निदेशक का पदनाम दिया गया है। नीपा परिषद, वित्त समिति तथा योजना और कार्यक्रम समिति में संस्थान का कुलसचिव सचिव होता है।

परिषद

संस्थान का सर्वोच्च निकाय परिषद है। इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार करती है। नीपा का निदेशक इसका उपाध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर की शिक्षा प्रणाली के सर्वोच्च अधिकारी और विख्यात शिक्षाविद् इसके सदस्य होते हैं। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार के चार सचिव (शिक्षा, वित्त, कार्मिक और योजना आयोग), निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के छः शिक्षा सचिवों और छः निदेशकों, छः प्रसिद्ध शिक्षाविदों, कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों तथा नीपा संकाय के एक सदस्य से नीपा परिषद का गठन होता है। समीक्षा समिति की संस्तुतियों के आधार पर नीपा संकाय के एक सदस्य के बदले अब तीन सदस्यों को परिषद में शामिल किया जाएगा। संस्थान का कुलसचिव परिषद का सचिव होता है।

संस्थान के सभी कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण तथा उद्देश्यों की प्राप्ति परिषद के प्रमुख कार्य हैं।

परिशिष्ट-I में 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार परिषद के सभी सदस्यों की सूची दी गई है।

कार्यकारी समिति

संस्थान का निदेशक कार्यकारी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अन्य सदस्य होते हैं : मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), वित्त और योजना आयोग के सचिवों द्वारा नामित व्यक्ति, एक राज्य का शिक्षा सचिव, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद्, राज्य सरकार का एक निदेशक, शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में सक्रिय रूप से संबद्ध राज्य शिक्षा संस्थान का एक निदेशक, नीपा का संयुक्त निदेशक और नीपा परिषद के संकाय सदस्यों के तीन

सदस्यों में से दो सदस्य। नीपा का कुलसचिव कार्यकारी समिति का सचिव होता है।

परिषद के वित्तीय और अन्य मामलों के प्रबंध का उत्तरदायित्व कार्यकारी समिति पर होता है। यह परिषद के सभी अधिकारों का उपयोग भी कर सकता है।

परिशिष्ट-II में 31 मार्च, 1992 की स्थिति के आधार पर कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची दी गई है।

वित्त समिति

वित्त समिति का गठन अध्यक्ष करता है। संस्थान के निदेशक की पदेन अध्यक्षता में इसमें 5 सदस्य होते हैं जिनमें वित्त सलाहकार तथा अध्यक्ष द्वारा नामित परिषद के सदस्य शामिल होते हैं। नीपा का कुलसचिव इसका सचिव होता है।

वित्त समिति लेखा तथा बजट निर्धारण की जांच-पड़ताल करती है और नए व्यय तथा वित्त संबंधी अन्य मामलों के प्रस्तावों की सिफारिश करती है।

परिशिष्ट-III में 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार वित्त समिति के सदस्यों की सूची दी गई है।

योजना और कार्यक्रम समिति

इस समिति में नीपा का निदेशक पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अन्य सदस्य होते हैं—संयुक्त निदेशक, नीपा के अकादमिक एककों के अध्यक्ष; मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), योजना आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक-एक प्रतिनिधि; विश्वविद्यालयों से एक उपकुलपति (राष्ट्रपति द्वारा नामित); दो शिक्षा सचिव तथा राज्य सरकारों के शिक्षा निदेशालयों के दो निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित); छः शिक्षाविद्/समाजशास्त्री/प्रबंध विशेषज्ञ (जिनमें से दो महिला या बालिका शिक्षा से संबंधित हों; एक अनुसूचित जाति और जनजाति तथा एक अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित हो)

31 मार्च 1992 तक अध्यक्ष, नीपा परिषद और भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा योजना और कार्यक्रम समिति में सदस्यों का नामांकन नहीं हुआ था।

इस समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह संस्थान के कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी। समिति दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन अकादमिक परिप्रेक्ष्यों और योजनाओं का विकास करेगी। इसके अतिरिक्त समिति से उम्मीद की जाती है कि वह संस्थान के संकाय द्वारा आयोजित अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार तथा सलाहकारी कार्यक्रमों को वार्षिक रूप से संघटित करके अध्ययन करेगी व कमियों तथा जरूरतमंद क्षेत्रों की पहचान करेगी।

संगठनात्मक ढांचा

अकादमिक एककें

संस्थान के संकाय को निम्नांकित 8 अकादमिक एककों में गठित किया गया है :

शैक्षिक योजना

शैक्षिक प्रशासन

शैक्षिक वित्त

शैक्षिक नीति

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा

उच्च शिक्षा

प्रादेशिक प्रणाली

अंतर्राष्ट्रीय

शैक्षिक नीति एकक को छोड़कर सभी अकादमिक एककों के अध्यक्ष वरिष्ठ अध्येता हैं। शैक्षिक नीति एकक का अध्यक्ष अध्येता है।

1991-92

संस्थान की नीतियों और अनुदान की उपलब्धता के अनुसार सभी अकादमिक एककों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास तथा विभिन्न प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें तथा अपने क्षेत्र में परामर्शकारी तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करें।

कृतिक बल और समितियां

विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर संस्थान का निदेशक विशेष कार्यबल तथा समितियों का गठन करता है।

अनुसंधान परियोजना पर सलाह देने और उनकी प्रगति का संचारेक्षण करने के लिए विशेषज्ञों की परियोजना सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं।

सहायता अध्ययन योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय करने के लिए एक अनुसंधान अध्ययन सलाहकार परिषद होती है। नीपा का निदेशक इसका अध्यक्ष होता है। अकादमिक एककों के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। नीपा का कुलसचिव इसका सचिव सदस्य होता है।

अधिरचनात्मक समर्थन सेवा

संस्थान के बहुमुखी कार्यक्रमों, अनुसंधान तथा अन्य अकादमिक गतिविधियों के विकास में संस्थान के पुस्तकालय, प्रलेखन केंद्र, प्रकाशन एकक, संगणक केंद्र, हिंदी कक्ष और मानचित्रण कक्ष एक मजबूत आधार तथा समर्थनकारी सेवाएं प्रदान करते हैं।

अध्याय 5 में प्रकाशन, पुस्तकालय तथा प्रलेखन सेवाओं के विस्तृत ब्योरे दिए गए हैं।

संगणक केंद्र

संगणक केंद्र में 4 आइ.बी.एम.-विप्रो पी.सी.ए.टी. है। प्रत्येक में 1 एम.बी.आर.ए.एम. 40 एम.बी. हार्ड डिस्क और 1.2 एम.बी. के 5.25" के फ्लापी ड्राइव है। उपर्युक्त 4 पी.सी./ए.टी. में से 3 का प्रयोग संस्थान के अनुसंधान और प्रशिक्षण गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों के संसाधन में किया जाता है। एक का प्रयोग डेस्क टॉप पब्लिशिंग के लिए किया जाता है। इसमें एक लेजर प्रिंटर (QMS PS 810) है। उसकी गति 8 पृष्ठ प्रति मिनट हैं। डी.टी.पी. प्रणाली में वेंचुरा पब्लिशिंग साफ्टवेअर लगा है। इससे संस्थान की सभी प्रकाशन सामग्रियों, वार्षिक रिपोर्टों और जर्नल का कार्य किया जाता है। इसके अलावा केंद्र में 10 पी.सी.-एक्स.टी. हैं। प्रत्येक में 640 के.बी.आर.ए.एम., 20 एम.बी. हार्ड डिस्क और दो 360 के.बी. फ्लापी ड्राइव है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अभ्यास के लिए इनका उपयोग किया जाता है।

केंद्र में एक एच.सी.एल./ए.टी. 386 और दो पी.सी. एक्स.टी., जिनमें एक विप्रो का और दूसरा ब्लू स्टार का है। इनमें 640 के.बी.आर.ए.एम. 20 एम.बी. हार्ड डिस्क हैं। 1.2 एम.बी. तथा 1.4 एम.बी. संग्रह क्षमता के 5.25" और 3.5" के दो फ्लापी ड्राइव हैं। संगणक केंद्र में एक एच.सी.एल. पी.सी.ए.टी. 386 भी है।

इसके अलावा संगणक केंद्र में पी.सी. आधारित नवीनतम साफ्टवेअर जैसे लोटस 1-2-3 (Rel.3), डीबेस IV, SPSS P+ (Ver.4) और वर्ड स्टार (Rel-6) भी हैं। कार्यक्रम संसाधन के लिए हमारे पास कोबोल, फोर्टान और पास्कल तथा 'C' के भाषा संकलनकर्त्ता हैं।

मानचित्रण कक्ष

मानचित्रण कक्ष अनुसंधान और प्रशिक्षण में मानचित्रण की प्रस्तुति संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है। विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधी चित्रलेखों आंकड़ों और सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुतीकरण की नई विधियों से आरेख ग्राफ, चार्ट, तालिकाएं व पारदर्शियां बनाई गईं। समीक्षाधीन वर्ष में केंद्र के महत्वपूर्ण कार्य निम्न थे : उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा, आदिवासी क्षेत्रों का अध्ययन, प्राथमिक शिक्षा पर संगणक परियोजना तथा द्वितीय

अखिल भारतीय प्रशासनिक सर्वेक्षण परियोजना के लिए आरेख और मानचित्र तैयार किए गए।

'सबके लिए शिक्षा : सचित्र प्रस्तुतीकरण' विषय पर मानचित्रण कक्ष ने दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष तुलनीय समय श्रृंखला की झलक मिलती है। इस दस्तावेज में पिछले 40 वर्षों से 1991 तक के आंकड़ें दिए गए हैं। इस दस्तावेज में शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े भी हैं।

हिंदी कक्ष

हिंदी कक्ष ने संस्थान के संपादन कार्य, अनुवाद कार्य तथा प्रश्नावलियों के अनुवाद, रिपोर्ताज तथा अन्य कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इसके अतिरिक्त जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हिंदी अनुवाद 'शैक्षिक योजना और प्रशासन' के पांच अंकों का अनुवाद, पुनरीक्षण और संपादन कार्य भी हिंदी कक्ष ने किया। "सबके लिए शिक्षा—सचित्र प्रस्तुतीकरण" का हिंदी अनुवाद भी संपन्न हुआ।

हिंदी कक्ष ने 16 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया तथा एक बैठक का आयोजन भी किया। इस अवसर पर प्रो. कृष्ण कुमार, अध्यक्ष (शिक्षा विभाग,) दिल्ली विश्वविद्यालय ने 'उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम की संभावना' विषय पर व्याख्यान दिया। इस बैठक की अध्यक्षता नीपा के संयुक्त निदेशक श्री बलदेव महाजन ने की।

हिंदी कार्यान्वयन रणनीति के अंतर्गत हिंदी कक्ष ने हिंदी टंककों को प्रशिक्षित किया। सभी प्रशिक्षणार्थीयों ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की।

प्रशासनिक ढांचा

प्रशासन और वित्त प्रभाग को चार अनुभागों तथा दो कक्षों में बांटा गया है। ये अनुभाग तथा कक्ष हैं—अकादमिक प्रशासन, लेखा, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन तथा प्रशिक्षण कक्ष और समन्वयन कक्ष। अकादमिक प्रशासन और समन्वयन कक्ष प्रत्यक्ष रूप से कुलसचिव के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्मिक, सामान्य प्रशासन और प्रशिक्षण कक्ष का पर्यवेक्षण प्रशासनिक अधिकारी करता है। इन सभी का सर्वाधिकारी कुलसचिव होता है। वित्त अनुभाग का पर्यवेक्षण अधिकारी वित्त अधिकारी होता है। दिनांक 31.1.1991 को कुलसचिव के सेवानिवृत्त होने के कारण प्रशासनिक अधिकारी कार्यकारी कुलसचिव का पदभार संभाल रहे हैं।

संवर्ग योजना

31 मार्च, 1992 को संस्थान में संवर्ग संख्या 176 थी।

संवर्ग पद	संख्या
संकाय	33 (19%)
(निदेशक, संयुक्त निदेशक, वरिष्ठ अध्येता, अध्येता और सह-अध्येता)	
अकादमिक सहयोग	24 (14%)
(प्रकाशन अधिकारी, पुस्तकाध्यक्ष, प्रलेखन अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, हिंदी संपादक, सहायक प्रकाशन अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी-II और श्रेणी-III, प्रकाशन सहायक, हिंदी अनुवादक, पुस्तकालय सहायक तथा तकनीकी सहायक)	

1991-92

संवर्ग पद	संख्या
प्रशासनिक और सचिव स्टाफ	41 (23%)
तकनीकी स्टाफ	33 (19%)
निदेशक के निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक, वरिष्ठ आशुलिपिक, मशीन चालक, कनिष्ठ आशुलिपिक, टेलिफोन संचालक, वाहन चालक, संगणक, बिजली मिस्त्री, कार्यक्रम परिचर, पुस्तकालय परिचर, वरिष्ठ तथा कनिष्ठ गेस्टेटनर (परिचालक)	
वर्ग घ (गैर तकनीकी)	45 (26%)
योग	**176**

स्टाफ परिवर्तन

1. श्री बलदेव महाजन, वित्त सलाहकार तथा संयुक्त निदेशक, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने 12 जून 1991 को संस्थान में संयुक्त निदेशक का पदभार संभाला।

2. श्री. एस.सी. बेहर आई.ए.एस. (मध्यप्रदेश, 1961) को दिनांक 8.10.1991 को कार्यमुक्त किया गया। श्री बेहर ने प्रधान सचिव, आदिवासी कल्याण विकास, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल का पदभार ग्रहण किया।

3. श्री मुकेश कक्कर, आई.ए.एस. (मध्य प्रदेश : 1979) ने दिनांक 17.1.1992 (पूर्वाह्न) नीपा में विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित परियोजना में परामर्शदाता का पदभार संभाला।

सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. श्री. एन. डी. कांडपाल ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के अकादमिक स्टाफ कालेज में पुस्तकालय विज्ञान पर आयोजित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लिया। (दिनांक 12.8.1991 से 10.9.1991)

2. डॉ. श्रीमती प्रमिला मेनन ने 'शैक्षिक परिवर्तन के लिए सहयोग—सरकारों, विद्यालयों तथा गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी' विषय पर जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (29 मई से 7 जून, 1991)

अध्ययन अवकाश

1. डॉ (श्रीमती) सुषमा भागिया, अध्येता, नीपा दिनांक 20.6.1991 से अध्ययन अवकाश पर हैं : वे ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा, के प्रो. जेमी वेलिन के सहयोग से 'नवाचार तथा सन 2000 की पाठ्यचर्या' विषय पर पुस्तक लिख रही हैं।

2. डॉ. (श्रीमती) के. सुधा राव; अध्येता, नीपा दिनांक 3.9.1991 से 31.3.1992 तक अध्ययन अवकाश पर हैं। उनके अध्ययन का विषय है 'उच्च अध्ययन के संस्थान में पाठ्यक्रम पुनर्गठन की योजना और प्रबंध पर संरचनात्मक प्रभाव'।

3. सुश्री एन. जुनेजा, सह-अध्येता, नीपा पी-एच.डी. शोधकार्य के लिए अध्ययन अवकाश पर हैं।

4. सुश्री जे. जलाली, सह अध्येता, पी-एच. डी. उपाधि हेतु शोध कार्य के लिए दिनांक 18.2.1992 से दो वर्ष के अध्ययन अवकाश पर हैं।

विदेशी नियुक्तियां

1. डॉ. ब्रह्म प्रकाश, वरिष्ठ अध्येता तथा अध्यक्ष, शैक्षिक योजना एकक मनीला में एशियाई विकास बैंक के शैक्षिक एकक में परियोजना अर्थशास्त्री के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2. डॉ. जी.डी. शर्मा, वरिष्ठ अध्येता तथा अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एकक, ने कैंब्रिज एजुकेशन कांसल्टैंट्स लिमिटेड, इंग्लैंड की ओर से यूनेस्को-यू.एन.डी.पी. कार्यक्रम के तहत 'जिला स्तर का बजट और लागत तैयार करना' विषय पर घाना में दिनांक 1.3.1991 से 3.5.1991 तथा पुनः 3.6.1991 से 23.7.1991 तक सलाहकार के रूप में कार्य किया।

3. डॉ. एम. मुखोपाध्याय, वरिष्ठ अध्येता तथा अध्यक्ष, शैक्षिक योजना एकक, ने साना (यमन) में दिनांक 12 से 26 नवंबर 1991 तथा पुनः 27.1.1992 से 14.2.1992 तक विश्व बैंक की बेसिक शिक्षा परियोजना में दूरवर्ती शिक्षा विशेषज्ञ (परामर्शदाता) के रूप में कार्य किया।

4. डॉ. आर गोविंदा, वरिष्ठ अध्येता तथा अध्यक्ष, विद्यालय और अनौपचारिक एकक, ने 'साक्षरता और सतत शिक्षा' की ए.पी.पी.इ.एल. मार्गदर्शिका के संपादन और अंतिम रूप देने के लिए यूनेस्को, बैंकाक में परामर्शकारी सेवा प्रदान की। (दिनांक 15.4.1991 से 26.4.1991 तथा पुनः अगस्त 12-26, 1991 तक)

विदेशी दौरे

5. डॉ.जी.बी.जी तिलक, वरिष्ठ अध्येता तथा अध्यक्ष, शैक्षिक वित्त एकक, ने वाशिंगटन डी. सी. में 22-25 जनवरी 1992 को अमेरिकन कौंसिल ऑफ एजुकेशन की 74वीं वार्षिक बैठक में 'उच्च शिक्षा का खर्च—अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य' विषय पर आयोजित परिचर्चा में भाग लिया।

6. डॉ. (श्रीमती) कुसुम के. प्रेमी, अध्येता तथा अध्यक्ष, शैक्षिक नीति एकक ने यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय, हुआहीम, थाईलैण्ड में आयोजित क्षेत्रीय कार्य शिविर में भाग लिया। इस कार्य शिविर का विषय था—'महिलाओं और लड़कियों के लिए कौशल प्रधान प्रशिक्षण' (दिनांक 9.11.1991 से 1.12.1991 तक)

7. डॉ. एस.सी. नुना, अध्येता ने बैंकाक में यूनेस्को द्वारा मानव संसाधन विकास के लिए शैक्षिक प्रबंध तथा एकीकरण योजना विषय पर आयोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया। (16-21 दिसंबर 1991)

परिसर सुविधाएं

संस्थान का कार्यालय चार मंजिला इमारत में है। इसका अतिथि गृह सात मंजिला है जिसमें 48 कमरे हैं। ये पूर्णतः सुसज्जित हैं। प्रत्येक कमरे में शौचालय वगैरह जुड़ा हैं। एक आवासीय परिसर भी है। इसमें टाइप-I के 16, टाइप II, III और V के आठ-आठ क्वार्टर हैं। एक निदेशक आवास है। टाइप IV के आठ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा योग्य अधिकारियों को आवंटित कर दिया गया है।

हमारी संशोधित योजनाओं पर दिल्ली नगर निगम की मंजूरी मिलते ही वार्डन, मेहमान संकाय आवास सुविधा और अतिथि गृह में अतिरिक्त प्रखंड का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। संशोधित योजना पहले से ही दिल्ली नगर निगम को पेश कर दी गई हैं।

1991-92

दिल्ली अग्नि शमन सेवा की सलाह पर अग्नि सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। इस कार्य में लगभग 9.50 लाख रुपये व्यय हुए। ड्राइ राइजर-कम-डाउन कमर, फाइबर ग्लास की पानी की टंकियां और अतिथिगृह के लिए सीमेंट और कंकरीट से बनी सड़कें तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के साथ मिलकर 2 लाख लिटर धारिता वाली भूमिगत पानी टंकी आदि का कार्य संपन्न हुआ। इसके अलावा डी.जी.सेट, पानी आपूर्ति पंप आदि लगाने का कार्य भी संपन्न हुआ तथा दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने इन्हें संतोषजनक बताया।

एन.सी.इ.आर.टी के वर्तमान उपकेंद्र से नीपा को विद्युत की आपूर्ति हो रही है जो कि दोनों संस्थाओं में विद्युत की बढ़ती मांग की पूर्ति करने में अपर्याप्त है। दोनों संस्थानों में भवनों का विस्तार हो रहा है। इसलिए के.लो.नि.वि. ने नीपा को अपना विद्युत उपकेंद्र अलग से बनाने की सलाह दी है। नीपा की बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए संस्थान ने के.लो.नि.वि के पास अलग से विद्युत उपकेंद्र खोलने के लिए 22 लाख रुपए की राशि जमा की है। साथ ही, नीपा ने डेसू से विद्युत उपकेंद्र के लिए 720.96 किलोवाट की बिजली मंजूरी करने का आवेदन किया है। इस सिलसिले में दिल्ली अग्नि शमन सेवा से स्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है परंतु डेसू ने अभी अपनी स्वीकृति नहीं दी है। के. लो.नि.वि. के विद्युत एकक सं. XIII द्वारा विद्युत उपकेंद्र की स्थापना के लिए विद्युत उपकरण तथा एच.टी पैनल का प्रबंध किया जा चुका है।

वित्त

वर्ष 1991-92 के दौरान संस्थान ने 185.25 लाख रुपए (योजनेत्तर के तहत 95.28 लाख रुपए और योजना के तहत 89.97 लाख रुपए) प्राप्त किए जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान यह राशि 167.56 लाख रुपये (योजनेत्तर के तहत 98.24 लाख रुपए और योजना के तहत 69.32 लाख रुपए) थी। वर्ष के शुरू में संस्थान के पास 8.75 लाख रुपए (योजनेत्तर के तहत 3.72 लाख रुपए और योजना के तहत 5.03 लाख रुपए) जमा थे। इस वर्ष ऑफिस और अतिथि गृह से 24.02 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार इस वर्ष प्राप्त कुल 218.02 लाख रुपए में सरकारी अनुदान से कुल 193.02 लाख रुपए व्यय हुए जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान कुल व्यय 191.91 लाख रुपए था।

प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों के लिए वर्ष के शुरू में संस्थान के पास 35.36 लाख रुपए जमा थे और वर्ष 1991-92 के दौरान इसके लिए अन्य अभिकरणों से 51.36 लाख रुपए प्राप्त हुए। इस वर्ष प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों पर 32.17 लाख रुपए व्यय हुए।

वर्ष 1991-92 के दौरान सरकारी अनुदान और प्रायोजित कार्यक्रमों तथा अध्ययन के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता से कुल 225.19 लाख रुपए व्यय हुए। वर्ष 1990-91 के दौरान यह राशि मात्र 227.53 लाख रुपए थी।

अनुबंध-I

वर्ष 1991-92 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशिविरों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों की सूची

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि तथा अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4
I	**डिप्लोमा कार्यक्रम** **राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम** *जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में ग्यारहवां डिप्लोमा कार्यक्रम, दूसरा चरण (विद्यालय और अनौपचारिक एकक)	1 फरवरी 1991 से 30 अप्रैल 1991 (30 दिन)	12
	चरण III	2-5 जुलाई 1992 (4 दिन)	12*
1.	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में बारहवां डिप्लोमा (विद्यालय और अनौपचारिक एकक)	11 नवंबर 1991 से 7 फरवरी 1992 (89 दिन)	14
	चरण II	8 फरवरी से 10 मई 1992 (53 दिन)	14*
	योग 1	**176**	**26**
	अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम *शैक्षिक योजना और प्रशासन में सातवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम (चरण I तथा II) (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	21जनवरी से 20 जुलाई 1991 (111 दिन)	26

1991-92

1	2	3	4
2.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में आठवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम (चरण-I) (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	3 फरवरी से 2 मई 1992 (58 दिन)	13
	योग 1	**169**	**39**
II	**विषयगत कार्यक्रम** **विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत योजना**		
3.	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के लिए संस्थागत योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक प्रशासन एकक)	3-21 जून 1991 (19 दिन)	25
4.	केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा अधिकारियों तथा वरिष्ठ प्रधानाध्यापक के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	11-15 नवंबर 1991 (5 दिन)	27
5.	आंध्र प्रदेश में करीमनगर जिले के प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के लिए संस्थागत योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित) (एस.एन.एफ.एकक)	3-7 मार्च 1992 (5 दिन)	27
	योग 3	**29**	**79**
	विद्यालय शिक्षा की योजना और प्रबंध		
6.	नवोदय विद्यालय समिति के अधिकरियो के संस्थागत निर्माण के लिए 'स्वोत' विश्लेषण (उच्च शिक्षा) और शिक्षा प्रशासन एकक द्वारा आयोजित)	28-30 अक्तूबर 1991 (3 दिन)	19
7.	सबके लिए शिक्षा के संबंध में शिक्षा में समता के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक नीति एकक)	20-24 जनवरी 1992 (5 दिन)	21

1	2	3	4
8.	वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों के लिए उन्नीसवां प्रबंध कार्यक्रम (प्रा.प्र.एकक)	10-14 फरवरी 1992 (5 दिन)	8
9.	भारत में बेसिक शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता पर संगोष्ठी (वि. और अनौ.शि. एकक)	29-31 जुलाई 1991 (3 दिन)	30
10.	भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अधिकतम तैयार करने के लिए कार्यशिविर (प्रा.प्र. तथा वि. और अनौ.शि. एकक)	9-13 दिसम्बर 1991 (5 दिन)	28
11.	समेकित योजना ढांचे के अंतर्गत शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (प्रा. प्र. एकक)	2-4 मार्च, 1992 (3 दिन)	14
	योग 6	**24**	**120**
	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंध		
12.	जिला शिक्षा और प्रशासन के योजना और प्रबंध के लिए चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रा.प्र.एकक)	19 अगस्त से 6 सितंबर 1991 (19 दिन)	25
13.	राजस्थान के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की योजना और प्रबंध शाखा के संकायों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम : उदयपुर (प्रा.प्र.ए.) और शैक्षिक नीति एकक) (क्षेत्र आधारित)	16-30 सितंबर 1991 (15 दिन)	26
14.	जिला शिक्षा और प्रशासन संस्थानों के पुस्तकालयों की योजना तथा प्रबंध (पुस्तकालय तथा प्रलेखन विभाग)	16-27 मार्च 1992 (12 दिन)	21
	योग 3	**46**	**72**

1	2	3	4
	प्र.शि.सा. और व्यष्टि स्तरीय योजना		
15.	राज्य स्तर पर सार्वजनिक आरंभिक शिक्षा की योजना के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	1-12 जुलाई 1991 (12 दिन)	6
16.	मेघालय, बारोपानी में शैक्षिक योजना की विकेंद्रीकृत प्रणाली पर अभिविन्यास कार्यक्रम (प्रादेशिक प्रणाली एकक) (क्षेत्र आधारित)	7-11 अक्तूबर 1991 (5 दिन)	20
17.	मणिपुर में शैक्षिक योजना की विकेंद्रीकृत प्रणाली पर अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित) (प्रा. प्र. एकक)	13-18 जनवरी 1992 (6 दिन)	25
18.	प्रा. शि. सा. के संचारेक्षण के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला (प्रा. प्र. एकक)	3-5 फरवरी 1992 (3 दिन)	26
	योग 4	**26**	**77**
	अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा		
19.	अनौपचारिक शिक्षा की प्रबंध गुण्वत्ता के लिए अनौपचारिक शिक्षा के सहायक निदेशकों का अभिविन्यास कार्यक्रम (प्रा. प्र. एकक)	24-26 जुलाई 1991 (3 दिन)	19
	योग 1	**3**	**19**
	अल्पसंख्यकों/वंचित वर्गों की शिक्षा की योजना और प्रबंध		
20.	विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए योजना संबंधी सुविधाओं के मिश्रित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (विद्यालय और अनौपचारिक एकक)	18-21 जून 1991 (4 दिन)	22

1	2	3	4
21.	अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंध किए गए संस्थानों के आचार्यों के लिए योजना और प्रबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक नीति एकक)	24-29 जून 1991 (6 दिन)	6
22.	आंध्र प्रदेश के उपयोजना क्षेत्र आदिवासियों के शैक्षिक विकास पर बैठक (शै. प्र. एकक)	29-31 जनवरी 1992 (3 दिन)	20
	योग 3	**13**	**48**
	संस्थानों का नेटवर्क		
23.	संसाधन व्यक्तियों का संस्थागत प्रबंध प्रशिक्षण का नेटवर्क विकास (शैक्षिक प्रशासन एकक)	24-28 जून 1991 (5 दिन)	21
24.	संस्थागत प्रबंध के नेटवर्क विकास के लिए संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक प्रशासन एकक)	22-26 जुलाई 1991 (5 दिन)	19
25.	शिक्षा के प्रबंध विकास नेटवर्क से संबंधित नीतिगत बैठक (शैक्षिक प्रशासन एकक)	9-10 मई, 1991 (2 दिन)	18
	योग 3	**12**	**58**
	शिक्षा की जिला स्तर पर योजना		
26.	जिला शिक्षा योजना की प्रणाली का प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	9-13 सितंबर 1991 (5 दिन)	9
27.	जिला स्तर पर शैक्षिक योजना का प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रा. प्र. एकक)	23 सितंबर से 4 अक्तूबर 1991 (12 दिन)	3
	योग 2	**17**	**12**

1991-92

1	2	3	4
	लंबी अवधि की परिप्रेक्ष्य योजना में कार्यप्रणाली		
28.	लंबी अवधि के योजना संप्रेक्ष्य में विधि प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	28 अक्तूबर से 1 नवंबर 1991 (5 दिन)	3
	योग 1	**5**	**3**
	शैक्षिक योजना के लिए परिमाणात्मक तकनीक		
29.	शैक्षिक योजना में मात्रात्मक तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक) (क्षेत्र आधारित)	23 सितंबर से 5 अक्तूबर 1991 (13 दिन)	44
	योग 1	**13**	**44**
	उच्च शिक्षा की योजना तथा प्रबंध-विद्यालय, अकादमिक स्टाफ कालेज तथा विश्वविद्यालय		
30.	महिला महाविद्यालयों के शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	31 जुलाई से 14 अगस्त 1991 (15 दिन)	21
31.	महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	9-27 सितंबर 1991 (19 दिन)	42
32.	विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के लिए विश्वविद्यालय की योजना और प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यशिविर (उच्च शिक्षा एकक)	16-20 दिसंबर 1991 (5 दिन)	10
33.	कालेजों में प्रभावशाली और पर्याप्त कार्यकलाप और विकास संबंधी अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए संगोष्ठी समेत कार्यशाला : कार्यात्मक अनुसंधान अध्ययन (उच्च शिक्षा एकक)	23-25 मार्च 1992 (3 दिन)	25

1	2	3	4
34.	अकादमिक स्टाफ कालेजों की योजना और प्रबंध पर निदेशकों की समीक्षार्थ परिचर्चा बैठक (उच्च शिक्षा एकक)	24-25 अक्तूबर 1991 (2 दिन)	43
	योग 5	**44**	**141**
	वित्त प्रबंध		
35.	विश्वविद्यालय वित्त के प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक वित्त एकक)	1-5 अप्रैल 1991 (5 दिन)	24
	योग 1	**5**	**24**
	संसाधनों का उपयोग		
36.	संसाधनों की समस्याओं से संघर्षरतविद्यालयों में संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर अभिविन्यास कार्यक्रम (शै. प्र. एकक)	17-21 फरवरी 1991 (5 दिन)	24
37.	शिक्षा में संसाधनों के उपयोग पर कार्यशाला (शैक्षिक वित्त एकक)	3-5 मार्च 1992 (3 दिन)	14
	योग 2	**8**	**38**
	शैक्षिक योजना और प्रबंध के लिए संगणक प्रयोग		
38.	शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए संगणकों के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	25 नवंबर 1991 से 6 दिसंबर 1991 (12 दिन)	10
39.	कालेज प्रबंधन के लिए संगणीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अभिविन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक प्रशासन एकक)	6-10 जनवरी 1992 (5 दिन)	25

1	2	3	4
40.	शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली में संगणक के अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शै.यो.एकक)	17 से 28 फरवरी 1992 (12 दिन)	19
	योग 3	**29**	**54**
	पर्यावरण शिक्षा की योजना तथा प्रबंध		
41.	पर्यावरण योजना और प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी—यूनेस्को—यू-एन.ई.पी. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (अंतर इकाई सहयोगी कार्यक्रम)	29 अप्रैल से 3 मई 1991 (5 दिन)	44
42.	दक्षिण एशियाई देशों के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यशिविर (शैक्षिक नीति एकक)	3-14 सितंबर 1991 (12 दिन)	14
43.	पर्यावरण शिक्षा (पश्चिमी क्षेत्र) पर यूनेस्को द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय कार्यशिविर, अहमदाबाद (अंतर इकाई सहयोगी कार्यक्रम)	18-20 सितंबर 1991 (3 दिन)	29
44.	पर्यावरण शिक्षा पर मद्रास में यूनेस्को प्रायोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशिविर (अंतर इकाई सहयोगी कार्यक्रम)	14-16 अक्तूबर 1991 (3 दिन)	26
45.	पर्यावरण शिक्षा पर इलाहाबाद में यूनेस्को प्रायोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशिविर (अंतर इकाई सहयोगी कार्यक्रम)	23-25 अक्तूबर 1991 (3 दिन)	17
46.	पर्यावरण शिक्षा पर शिलांग में यूनेस्को प्रायोजित क्षेत्रीय प्रशिक्षण का कार्यशिविर (अंतर इकाई सहयोगी कार्यक्रम)	28-30 अक्तूबर 1991 (3 दिन)	37
	योग 6	**29**	**167**

1	2	3	4
	सार्क देशों में शैक्षिक योजना तथा प्रबंध		
47.	शैक्षिक योजना और प्रशासन विषय पर सार्क देशों की कार्यशाला (शैक्षिक नीति एकक)	9-12 मार्च 1992 (4 दिन)	11
	योग 1	**4**	**11**
	कुल योग 47	**652**	**1032**

* पिछले वर्ष में शुरू किए गए एक राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम समीक्षाधीन वर्ष में भी जारी रहे। इनके प्रतिभागियों को भी इस सूची में शामिल किया गया है।

1991-92

अनुबंध-II

प्रशिक्षण सामग्रियों की सूची

* जिंबाबवे में शैक्षिक नीति तथा योजना
* क्षेत्रीय स्तर पर वित्तीय योजना
* वित्तीय आकलन
* विद्यालय प्राचार्य तथा वित्तीय प्रबंध—योजना तथा प्रबंध विस्तार
* संसाधन प्रबंध—सिंहावलोकन
* शिक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षणः योजना और प्रबंध के आयाम
* जिलास्तर पर योजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत
* भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा
* सबके लिए शिक्षा : संबंधित क्षेत्र
* लड़कियों की शिक्षा
* भारत में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता
* शिक्षाकर्मियों की भूमिका
* मेघालय के विशेष संदर्भ में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण
* पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा प्रणाली की आंतरिक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक : उसकी क्षमता और समानता
* सामुदायिक शिक्षा और विस्तार कार्य
* योजना और प्रबंध में समुदाय की भागीदारी
* सार्क देशों का सिंहावलोकन
* अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा पर किए गए अनुसंधानों का सारांश
* बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में रोजगार योजना
* शिक्षा में संसाधनों के प्रभावी उपयोग के माध्यम
* आंतरिक क्षमता, विद्यालय प्रभाविता और छात्रों की उपलब्धियां
* तीसरी दुनिया के देशों की चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी
* सार्क देशों की चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी
* लोक जुम्बिश की झलक
* शिक्षा में संसाधनों का उपयोग
* एशिया में शिक्षा का विकास
* शिक्षा प्रणाली की आंतरिक क्षमता का संगणक प्रतिरूप
* कर्नाटक के आंकड़े पर आधारित व्यावहारिक अनुभवों के साथ मात्रात्मक तकनीकों पर प्रशिक्षण माड्युल
* व्यापक अनुप्रयोगों सहित लम्बी अवधि की शैक्षिक योजना की प्रणाली पर शिक्षा और अध्ययन की सामग्री

अनुबंध-III

नीपा विचार मंच

दिनांक	विषय	वक्ता
22 अप्रैल, 1991	भारत में शैक्षिक नीति	श्री.एम.वी.रामा. राव शोध-छात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद
28 नवंबर, 1991	एर्नाकुलम जिले में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम	पी. के. माईकल थाराकोन विकास अध्ययन केन्द्र, उल्कोर, त्रिवेंद्रम
3 दिसंबबर, 1991	सोवियत विकास नीति में नवीनतम परिवर्तन	प्रो. कोत्सकी, मास्को विश्वविद्यालय मास्को

1991-92

अनुबध-IV

संकाय का अकादमिक योगदान

पुस्तकें

एम. मुखोपाध्याय

रिसर्च आन एजुकेशनल मैनेजमैंट-ए ट्रैंड एनालिस, बुच, एम. बी. (सं) फोर्थ सर्वे आफ **रिसर्च इन एजुकेशन,** नई दिल्ली, एन. सी. इ. आर. टी. 1991

एजुकेशनल टैक्नोलोजी : फ्युचर, एम मुखोपाध्याय और अन्य (स.) **एजुकेशनल टैक्नोलोजी तीसरी वार्षिक पुस्तक** नई दिल्ली, ए. आइ. ए. इ. टी, 1991

मैनेजमैंट आफ टीचर्स एजुकेशन, सिंह, एल. सी. (स) **रिसोर्स बुक ऑन टीचर्स एजुकेशन**, नई दिल्ली, एन.सी.इ.आर.टी. 1991

एम. एम. कपूर

माइक्रो लेवल एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट : हैंड बुक (सहयोगी लेखक) यूनेस्को, एशिया और प्रशांत क्षेत्र का मुख्यालय, बैंकाक, 1991

कोलाबरटिव कंट्रीब्युशन ऑन **'वर्ल्ड एजुकेशनल इंडिकेटर्स'** में **वर्ल्ड एजुकेशनल रिपोर्ट** : यूनेस्को, पेरिस, 1991

एजुकेशन इन अरूणाचल प्रदेश इन 2000 : ए पर्सपेक्टिव प्लान (सहयोगी लेखक) एजुकेशनल कांसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली : 1991

श्रीप्रकाश

इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया आफ इकॉनामिक्स, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली में निम्नलिखित अध्ययन :

(i) इनपुट-आउटपुट प्रोग्रामिंग मॉडल आफ इनवेंटरी इनवेस्टमेंट इन इंडियन इकानामी

(ii) इंपैक्ट आफ इकॉनामिक डवलपमेंट ऑन फारेस्ट इन मेघालय

(iii) ऐन इंटर-इंडस्ट्री मॉडल आफ इकॉनामिक इफेक्ट आफ एजुकेशन

(iv) 'डिमोग्राफिक ट्राजीसन इन इंडिया'

जे. बी. जी. तिलक

स्कूलिंग एंड इक्युटी (सोकोरोपोलस के साथ) में **एसेस ऑन पावर्टी, इक्विटी एण्ड ग्रोथ**, आक्सफोर्ड : परगैमोन, 1991

फाइनेंसिंग आफ एजुकेशन इन इंडिया (एन.बी. वर्गीस के साथ) अनुसंधान रिपोर्ट सं 92, आई.आई.इ.पी.पेरिस, 1991

एजुकेशनल प्लानिंग एंड ग्रासरूटस, आशीष प्रकाशन, नई दिल्ली, 1992

एजुकेशनल फार डवलपमेंट इन एशिया, यूनेस्को-आई.आइ.इ.पी प्रायोजित अध्ययन, सेज प्रकाशन (प्रेस में)

रूरल अर्बन इन इक्वलिटीज इन एजुकेशन : ए स्टडी आफ रिटर्नस टू एजुकेशन : ह्यूमन कैपिटल फार्मेशन एंड अर्निंगस डिफरेंशिएशन, मोनोग्राफ, श्रृंखला 2 धारवाड़, बहुशास्त्रीय अनुसंधान केंद्र (1992)

कुसुम के. प्रेमी

इंडिया पापुलेशन मुविंग टुवर्डस ए बिलियन, डी.के. पब्लिशर्स नई दिल्ली, 1991 में ''लिटरेसी डिलेमा''

एस. सी. नुना

रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल डवलपमेंट इन इंडिया, साउथ एशियन पब्लिकेशंस (प्रेस में)

के. सुधा राव

कैच देम यंग-वोकेशनेलाइजेशन आफ एजुकेशन एट प्लस टू स्टेज, स्टर्लिंग, नई दिल्ली, 1992

अनुसंधान आलेख/प्रकाशित लेख

एम. मुखोपाध्याय

कंप्यूटर्स इन एजुकेशन : फ्यूचर पर्सपेक्टिव, प्रोसिडिंग्स आफ नेशनल एक्सपोर्ट मीट ऑन फ्यूचर डारेक्शंस इन एजुकेशन, एटमा, फरवरी, 1992

एजुकेशनल टैक्नोलोजी : व्हाइ सो इगनोरड ? प्रोसिडिंग्स आफ द टवेन्टी फोर्थ नेशनल कांफ्रेंस आन एजुकेशनल टैक्नोलोजी, भुवनेश्वर, 1991

रोल आफ मीडीया इन ओपन लर्निंग, इन्वाइटेड प्रसेंटेशन इन सार्क वर्कशाप आन ओपन लर्निंग सिस्टम, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 1991

नेशनल टास्क : दूरदर्शन इवेसिव, एजुकेशनल टैक्नोलोजी, मई 1991

श्रीप्रकाश

"भारत में शिक्षा की निजी मांग", **मैनपावर जर्नल,** आई.ए.एम.आर., जिल्द 26, अंक 1-2, 1990, नई दिल्ली

"इनपुट-आउटपुट-प्रोग्रामिंग मॉडल आफ इंवेटरी इंवेस्टमेंट इन इंडिया इकॉनामी, **मार्जिन,** एन.सी.ए.इ.आर., जिल्द 23, अंक 3, अप्रैल-जून-. 1990, नई दिल्ली

डिमोग्राफिक प्रेशर एंड माइग्रेशन : ए केस स्टडी आफ मेघालय, **मैनपावर जर्नल,** आई.ए.म. आर, नई दिल्ली, 1989

जे.बी.जी. तिलक

व्हाई एजुकेशनल पालिसीज कैन फेल ? **जर्नल आफ एजुकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन,** जिल्द 5, अंक 3, (जुलाई 1991)

"डवलपमेंट आफ एजुकेशन इन एशिया," **एशियन इकॉनामिक्स** अंक 80 (मार्च, 1992)

"एजुकेशन एंड वेज अर्निंग्स" **इनसाइक्लोपीडिया आफ एजुकेशनल रिसर्च,** (न्यूयार्क, 1992)

"प्राइवेटाइजेशन आफ हायर एजुकेशन,' '**प्रास्पेकट्स,** जिल्द 21, अंक 2 (1991)

फेमिली एंड गवर्नमेंट इनवेस्टमेंट्स इन एजुकेशन," **इंटरनेशनल** जर्नल आफ एजुकेशनल डवलपमेंट, जिल्द 11, अंक 2 (1991)

ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स फार इंडिया, **आई.ए.ए.एस.आई,** त्रैमासिक जिल्द 10, अंक 2, 1991

इकॉनामिक ग्रोथ टु ह्युमन डवलपमेंट : ए कमेंटरी आन रीसेंट इनडेक्सेज आफ डवलपमेंट, **इंटरनेशनल जर्नल आफ सोशल इकॉनामिक्स,** 19 (2) 1992.

इंटरनेशनल ट्रेंडस इन कास्टस एंड फायनेसिंग हायर एजुकेशन : सम टेंटेटिव कपेरिसन बिटवीन डवलपड एंड डवलपिंग कन्ट्रीज, अमरीकन शिक्षा परिषद की 74 वीं वार्षिक बैठक, वाशिंगटन डी.सी., 1992

फायनेंसिंग एजुकेशन, **सेमिनार** सं. 389 , वार्षिक सं. 1992

1991-92

कुसुम के. प्रेमी

"प्रोटेक्टिव डिस्क्रीमीनेशन एंड रीजनल डीसपैरीटिज इन एजुकेशनल डवलपमेंट : दि केस आफ इंडियन ट्राइब्स" **जर्नल आफ एजुकेशन एंड स्पेशल चेंज**, जिल्द IV, अंक 4. 1991

"एजुकेशन फार आल" : **दि कनर्सन एरियास इन डेमोग्राफी इंडिया** जिल्द 20, अंक 1, 1991

"युनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इन रिमोट एरियास : ए केस स्टडी आफ लद्‌दाख (लेह)" **न्यु फ्रंटियर्स इन एजुकेशन** जिल्द 22, अंक 1, जनवरी- मार्च 1992

आर. एस. शर्मा

"इंस्टीटयुशनल प्लानिंग, स्ट्रेंग्थनिंग इंस्टीटयुशनल इफिसीएंसी", **प्राइमरी टीचर,** एन.सी.इ.आर.टी. जिल्द 3, जुलाई 1991

अरूण सी. मेहता

"इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इट्स एपलिकेशन इन एजुकेशन" **आल इंडिया एसोसिएशन आफ एजुकेशनल टेक्नालाजी,** जिल्द, 4, अंक 5, अक्टूबर, 1991)

"इंट्रोडक्शन टू लोटस 1-2-3" **आल इंडिया एसोसिएशन आफ एजुकेशनल टेक्नालाजी,** जिल्द 4, अंक 5, नवंबर, 1991

स.एम.आइ.ए. जैदी

"कास्ट एंड पोलिटिक्स इन एन इंडियन विलेज, **सोशल चेंज,** जिल्द 20, अंक 1, मार्च 1990

"वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन स्कूल एजुकेशन : ड्रोपआऊटस एट एलिमेन्ट्री लेवल, जर्नल आफ एजुकेशनल **प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,** जिल्द V अंक 2 अप्रैल 1991.

वाई जोसेफिन

"डवलपमेंट आफ एजुकेशन", **पैलेसतीन न्यु फ्रंटियर्स इन एजुकेशन,** जिल्द 21, अंक 1 (जनवरी मार्च) 1991.

पुस्तक समीक्षाएं

जे.बी.जी. तिलक

इकॉनामिक्स आफ एजुकेशन **"जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन",** जिल्द V अंक 2 (अप्रैल 1991)

"ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट" **किलोस**, जिल्द, (1991)

"हायर एजुकेशन इन इंडिया,' **पैसिफिक अफेयर्स** जिल्द 64, अंक 3, 1991

ग्रेजुएट अनइम्पलायमेंट इन इंडिया (जे.एल.आज़ाद), **यूनीवर्सीटी न्यूज,** जिल्द 30(11) मार्च, 16, 1992

एजुकेशन एंड द ग्लोबल कर्न्सन **'जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन',** जिल्द 5, अंक 3 (जुलाई 1991)

"फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन" एंड "फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन इन जापान", **जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन",** जिल्द VI, अंक 1 (जनवरी 1992)

"एजुकेशन एंड सोशल ट्रांसफोरमेशन इन द थर्ड वर्ल्ड", **जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,** जिल्द 5, अंक 4 (अक्तूबर 1991)

एस.सी. नूना

लिटरेसी स्निेरियो इन इंडिया : ए मार्च टूवर्ड डवलपमेंट आफ अंडरडेवलपमेंट ?" **सोशल एक्शन,** जिल्द 41, अक्तूबर 1991.

रंजना श्रीवास्तव

मैक्रो कंप्यूटर्स इन स्कूल एजुकेशन इन मिडिया एंड टैकनॉलाजी फार ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट", **जर्नल आफ एजुकेशनल टेक्नॉलाजी,** जिल्द 4, अंक 1 (अक्टूबर, 1991)

एस.एम.आइ.ए. जैदी

'स्टेट्स आफ वूमैन', **जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,** जिल्द IV, अंक 2. अप्रैल 1990

बी.के.पांडा

"ग्रासरुट्स एजुकेशन इन इंडिया : ए चैलेंज फार पॉलिसी मेकर्स" **जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,** जिल्द V, अंक 1, जनवरी 1991.

संस्थान के बाहर नीपा संकाय की भागीदारी

सत्रों की अध्यक्षता/उद्घाटन/समापन

सत्यभूषण

माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक विस्तार विषय पर आयोजित संगोष्ठी में अध्यक्षता की (18 सितंबर 1991)

एम. मुखोपाध्याय

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर में शैक्षिक प्रौद्योगिकी विषय पर आयोजित 24वें राष्ट्रीय सेमिनार की अध्यक्षता की (22 दिसंबर 1991)

दिए गए व्याख्यान

सत्यभूषण

जम्मू राज्य में क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान दिया (10 अगस्त 1991)

जम्मू में आयोजित कार्यशिविर में "ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना की पुर्नगठित योजना" पर व्याख्यान (7 दिसंबर, 1991)

जी.डी. शर्मा

एन.सी.इ.आर.टी, नई दिल्ली में "उच्च शिक्षा" विषय पर व्याख्यान (20 नवंबर 1991)

"उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ और प्रासंगिकता संबंधी मसले"-जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली (4 दिसंबर 1991)

उच्च शिक्षा व्यावसायिक विकास केंद्र में व्याख्यान दि.वि. नई दिल्ली (3 जनवरी, 1992)

(उच्च शिक्षा और सूचना प्रणाली का विकास" जा.मि.ई. नई दिल्ली (14 फरवरी, 1992)

जा.मि.ई. नई दिल्ली में 7 वें अभिविन्यास कार्यक्रम में व्याख्यान (25 फरवरी, 1992)

"शिक्षकों की सेवा और सामग्री शर्तें" विषय पर उच्च शिक्षा व्यावसायिक विकास केन्द्र, दि.वि. दिल्ली में व्याख्यान (26 मार्च, 1992)

एम. मुखोपाध्याय

मुक्त अधिगम में मीडीया की भूमिका, मुक्त अधिगम पर सार्क कार्यशाला, नई दिल्ली (10 अप्रैल 1991)

एन.सी.इ.आर.टी. नई दिल्ली में "प्रबंध उत्कर्ष "विषय पर व्याख्यान (25 जून, 1991)

शिक्षा में गैर शैक्षिक संगठनों की भूमिका, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (13 अगस्त, 1991)

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबंध, सी.आइ.इ.टी. नई दिल्ली (22 अगस्त 1991)

1991-92

विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली में 'युवा वर्ग तथा शिक्षा' विषय पर व्याख्यान (28 अगस्त 1991)

शैक्षिक दृश्य-विधान के निर्गमन में शिक्षक, शिक्षक दिवस समारोह, हावड़ा (5 सितंबर 1991)

शिक्षा : समस्याएँ तथा परिप्रेक्षय, अखिल भारतीय शैक्षिक समागम पटना (21 अक्तुबर, 1991)

अध्यक्षीय भाषण, शैक्षिक प्रौद्योगिकी : उपेक्षित क्यों ? राष्ट्रीय सम्मेलन, ए.आइ.ए.इ.टी. (22 दिसंबर 1991)

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबंध, केन्द्रीय विद्यालय प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली (18 फरवरी, 1992)

शिक्षा के क्षेत्र में संगणक प्रयोग भविष्य परिप्रेक्षय, भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में संगणकों की दिशा पर आयोजित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति में अध्यक्षीय भाषण (22 फरवरी 1992)

के.जी. विरमानी

प्रबंध : हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ (9 मई, 1991)

रांची में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारियों के समक्ष प्रबंध विषय पर व्याख्यान (15-18 मई, 1991)

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों के समक्ष "अधीक्षण विकास" विषय पर संगठनात्मक अनुसंधान और शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में व्याख्यान (22 मई, 1991)

कालेज स्टांफ और प्राचार्यों इत्यादि से संबंधित शैक्षिक नेतृत्व और अन्य विषय पर पास्ट्रोरल केंद्र शिलांग में व्याख्यान दिया (22, 24-26 जून, 1991)

एस.सी.इ.आर.टी. नई दिल्ली में व्याख्यान (27 जून, 1991)

के.वि.सं., नई दिल्ली में विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के समक्ष व्याख्यान, (4 और 17-18 फरवरी तथा 12-13 मार्च, 1992)

नवोदय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के समक्ष व्याख्यान, नई दिल्ली (9 जनवरी, 1992)

हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ (24 फरवरी, 1992

आर. गोविंद

विश्व युवक केंद्र, नई दिल्ली में भारतीय शिक्षा व्यवस्था" पर व्याख्यान (26 सितंबर 1991)

"प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका" के.शै.प्रौ.सं.अ.प्र.प., नई दिल्ली (11 नवबर, 1991)

एन.सी.इ.आर.टी., नई दिल्ली में "अनौपचारिक शिक्षा" पर व्याख्यान (22 नवंबर, 1991)

दिल्ली विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा वृतिक विकास केंद्र में "व्याख्यान विधि से ज्ञान का प्रसारण" विषय पर व्याख्यान (27 दिसंबर, 1991)

नई दिल्ली में "अकादमिक उत्कर्ष तथा नवोदय विद्यालयों के प्राचार्यों की भूमिका" विषय पर व्याख्यान (11 जनवरी 1992)

"जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की प्राथमिक विद्यालयों में न्युनतम अधिगम स्तर प्राप्त करने में भूमिका' विषय पर व्याख्यान, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली (25 फरवरी 1992)

श्री एम.एम. कपूर

एस.सी.इ.आर.टी. द्वारा आयोजित प्राचार्यों के लिए कार्यक्रम में सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन विषय पर व्याख्यान दिया (25 जून, 1991)

1991-92

एन.सी.इ.आर.टी. नई दिल्ली में महिला अध्ययन में परिमाणात्मक पद्धति पर दो व्याख्यान (8 अगस्त, 1991)

"कार्यक्रम अनुरीक्षण तथा मूल्यांकन : संकल्पना तथा तकनीक" एन.आई.पी.सी.सी.डी, नई दिल्ली (11 नवंबर, 1991)

एन.सी.इ.आर.टी, नई दिल्ली में भारत में शैक्षिक प्रशासन" विषय पर व्याख्यान (25 नवंबर, 1991)

जि.शि.प्र.सं. मोतीबाग, नई दिल्ली में प्रारंभिक शिक्षा के प्रधानाध्यापकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में "व्यष्टि स्तरीय योजना और सांस्थानिक योजना" पर व्याख्यान (27 जनवरी, 1992)

एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली में सबके लिए शिक्षा के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना विषय पर व्याख्यान (फरवरी 1992)

जि.शि.प्र.सं., राजेन्द्र नगर में प्रा.शि.सा. के लिए व्यक्ति स्तरीय योजना पर व्याख्यान (10 फरवरी, 1992)

श्रीप्रकाश

"विकास प्रक्रिया और मानव शक्ति योजना में उच्च शिक्षा को भूमिका" उच्च शिक्षा व्यावसायिक केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (1 मई, 1991)

"प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण : योजना और प्रबंध" (6 जून, 1991)

"एशियाई अर्थव्यवस्था में रोजगार-शिक्षा संबंध" : कालेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम : अकादमिक स्टाफ कालेज, जे.एन.यू. नई दिल्ली (26 जून, 1992)

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, शिलांग में 'मेघालय में प्रारंभिक शिक्षा में समुदाय की भागीदरी" विषय पर व्याख्यान (11 अक्तुबर, 1991)

डॉ. (श्रीमती) जया इंदिरेसन

"छात्र विकास के लिए मार्गदर्शन और सुझाव" : अकादमिक स्टाफ कालेज, जे.एन.यू. नई दिल्ली (14 जून, 1991)

जे.बी.जी. तिलक

आई.ए.एम.आर. में "शिक्षा में लागत और वितयन" विषय पर व्याख्यान (13 अगस्त, 1991)

एन.सी.इ.आर.टी, नई दिल्ली में "भारत में वित्त शिक्षा" विषय पर व्याख्यान (21 नवंबर, 1991)

"शैक्षिक वित्त" जा.मि.इ. नई दिल्ली (14 जनवरी 1992)

"शिक्ष में वित्तीय प्रबंध" "शैक्षिक प्रशासन विभाग, बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा 11 फरवरी, 1992)

शिक्षा में निवेश संबंधी नीतियां" वाणिज्य विभाग, बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा (12 फरवरी, 1992)

"विद्यालय में वित्तीय प्रबंध" रा.शै.प. हैदराबाद (23 फरवरी, 1992)

कुसुम. के. प्रेमी

एन.सी.इ.आर.टी., नई दिल्ली में महिला अध्ययन में मात्रात्मक और गुणात्मक विधि के पाठ्यक्रम में "महिलाओं के शैक्षिक विकास के संकेतक" विषय पर व्याख्यान (6 अगस्त, 1991)

उच्च शिक्षा में अनु.जा. और अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक समस्याओं पर दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के समक्ष व्याख्यान (13 मार्च 1992)

आर.एस. शर्मा

"प्रारंभिक शिक्षा के उभरते मुद्दे और प्रमुख चुनौतियां",

1991-92

जि.शि.प्र.अ पूराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली (2 फरवरी, 1992) पत्राचार विद्यालय, दिल्ली

शिक्षा की भूमिका तथा दूरवर्ती शिक्षा के मुद्दे' विषय पर व्याख्यान (23 मार्च, 1992)

एन. वी. वर्गीज

एन.सी.इ.आर.टी., नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में "भारत में स्वातंत्रोतर शैक्षिक विकास" पर व्याख्यान (16 जुलाई, 1991)

आई.ए.एम.आर., नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम" शिक्षत बेरोजगारी" विषय पर व्याख्यान (27 सितंबर, 1991)

डॉ. (श्रीमती) सुदेश मुखोपाध्याय

"दृष्टिहीनों की शिक्षा" : एन.सी.इ.आर.टी. नई दिल्ली (13 मई, 1991)

अरूण सी. मेहता

एन.सी.इ.आर.टी., नई दिल्ली में महिला शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में "आंकड़ा और आंकड़ा स्त्रोत" विषय पर व्याख्यान (31 जुलाई, 1991)

आई.ए.एम.आर., नई दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में "मानव शक्ति योजना में संगणक अनुप्रयोग" विषय पर व्याख्यान (12 अगस्त, 1991)

"शैक्षिक योजना के लिए संगणक प्रतिरूप" - आइ.ए.एन.आर, नई दिल्ली (26 अगस्त, 1991)

ए. मैथ्यु

एन.सी.इ.आर.टी., नई दिल्ली में "भारत में शिक्षा : एतिहासिक सिंहावलोकन" विषय पर व्याख्यान (7 जुलाई, 1991)

एन.सी.इ.आर.टी. नई दिल्ली में स्वतन्त्रता पश्चात भारत में शिक्षा : नीति-प्राथमिकता द्विभाजन" विषय पर व्याख्यान (18 जुलाई, 1991)

(श्रीमती) प्रमिला मेनन

जीसस और मेरी, नई दिल्ली में कानवेंट के शिक्षकों के समक्ष विद्यालय समुदाय के संबंध में समुदाय की भागीदारी" विषय पर व्याख्यान (मई, 1991)

एस.एम.आइ.ए. जैदी

संगणक कक्ष, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, शिमला, हि.प्र. का अध्ययन दौरा किया तथा डॉ. अरूण सी मेहता के सहयोग से इ.एम.आइ. एस के केस अध्ययन का विकास किया (13-20 जुलाई, 1991)

बी. के पांडा

निम्नलिखित विषयों पर व्याख्यान दिए

अ) विद्यालयों के संगठनात्मक योजना के लिए तैयारी

ब) करीमनगर, आंध्र प्रदेश विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों की संगठनात्मक योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यालय प्रधानाध्यापकों की भूमिका (3-7 मार्च, 1992)

संगोष्ठियों में भागीदारी

सत्य भूषण

कायरो (मिस्त्र) में माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा का समायोजन विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी में भाग लिया (4 जुलाई, 1991)

प्राथमिक शैक्षिक सचिवों के सार्वजनीकरण पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया (10 अगस्त, 1991)

1991-92

बलदेव महाजन

"सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग" के 21 वें अधिवेशन में यूनेस्को की ओर से संबधक के रूप में भाग लिया (22 जुलाई, 1991)

"1990 में विद्यालय शिक्षा : समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य" विषय पर एन.सी.इ.आर.टी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया (18-19 सितंबर 1991)

जी.डी. शर्मा

केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेंद्रम द्वारा आयोजित उपकुलपतियों के सम्मेलन में भाग लिया (9-10 अक्तुबर 1991)

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान में शैक्षिक योजना पर पैनल परिचर्चा में भाग लिया (29 जनवरी 1992)

एम. मुखोपाध्याय

मुक्त अधिगम पर सार्क कार्यशिविर, एम/एच आर डी/ एन ओ एस, नई दिल्ली (10-12 अप्रैल, 1991)

गंदी बस्ती के बच्चों के शैक्षिक विकास विषय पर बंबई में आयोजित कार्यशिविर का मार्गदर्शन किया (22-23 जून 1991)

आइ.पी.सी.एल. विद्यालयों के संगठनात्मक विकास के लिए दो दिवसी कार्यशाला का आयोजन किया (26-27 अप्रैल 1991)

अखिल भारतीय शिक्षा समागम, पटना (अक्तुबर 21-22, 1991)

अखिल भारतीय शैक्षिक प्रैद्योगिकी संघ के तत्वाधान में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया (22-24 दिसंबर, 1991)

एम.एम. कपूर

गोवाहटी, आसाम में शिक्षा के सार्वजनीकरण पर आयोजित कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया (12-13 मार्च, 1991)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ में विश्व बैंक परियोजना के संबंध में शैक्षिक प्रशासकों में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया (23-24 अप्रैल, 1991)

एन.सी.इ.आर.टी. नई दिल्ली में जि.शि.प्र.सं. के प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीति तथा दृष्टिकोण से संबंधित आलेख 'विषय पर आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया (27 मई, 1991)

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया और भारत के कामकाजी बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा" विषय पर आलेख प्रस्तुत किया (26 नवंबर 1991)

'शहरों में प्रा.शि.सा. के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना' विषय पर आयोजित कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया, जि.श.प्र.सं., राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली 15 दिसंबर 1991 तथा 9-10 फरवरी, 1992)

एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली में आयोजित प्रारंभिक शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया, नई दिल्ली (9-10 दिसंबर, 1991)

इटानगर में वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित सम्मेलन में भाग लिया और "अरूणाचल प्रदेश में शैक्षिक प्रशासन का आधुनिकरण विषय पर आलेख पड़ा (19-20 दिसंबर 1991)

आर गोविंद

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर में शिक्षक प्रशिक्षकों के

1991-92

लिए मूल्यकेंद्रित शिक्षा पर हैंड बुक" विषय पर आयोजित लेखकों के कार्य शिविर में भाग लिया (24 जून 1991)

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में "मौलाना आजाद केन्द्र के लिए प्रारंभिक और सामाजिक शिक्षा : परिप्रेक्ष्य योजना" विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया (18 दिसंबर 1991)

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा में अध्ययन विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (24 जनवरी, 1992)

शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा पूर्व परामर्श के लिए "शहरी बच्चों" पर आयोजित बैठक में भाग लिया (10 फरवरी, 1992)

करीमनगर आंध्र प्रदेश में प्रधान शिक्षकों के प्रशिक्षण में संसाधन व्यक्ति के रुप में कार्य किया (3 मार्च, 1992)

जया इंदिरेसन

बड़ोदा में आइ.पी.सी.एल. विद्यालय में आयोजित सांगठनिक विकास कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया (26-27 अप्रैल 1991)

जे.बी.जी. तिलक

एन.सी.इ.आर.टी, नई दिल्ली द्वारा "जनसंख्या शिक्षा में प्रशिक्षण के प्रतिरूपों की लागत प्रभाविता के अध्ययन के लिए उपकरणों के विकास और उसे अंतिम रूप देने के लिए आयोजित कार्यशिविर में भाग लिया (3 जून 1991)

जे.एन.यू. नई दिल्ली द्वारा "शिक्षा और श्रम बाजार" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया (21 अगस्त 1991)

विश्वविद्यालय सेवा, नई दिल्ली में "सबके लिए शिक्षा" विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशिविर में भाग लिया (6-8 सितंबर, 1991)

श्री कृष्ण देवर्या विश्वविद्यालय, अनंतपुर में भारतीय आर्थिक संघ के 74 वे वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया

कुसुम के. प्रेम।

"जनगणना 1991 : प्रारंभिक परिणाम" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में "साक्षरता की असमंजसता" पर एक चर्चा प्रस्तुत की (24 अप्रैल 1991)

"लिंग अनुपात : जनगणना 1991" विषय पर एन.सी.इ. आर.टी. द्वारा आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया (6 मई 1991)

यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय, हुआ हीम, थाइलैंड में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशिविर में भाग लिया। इस कार्यशिविर का विषय था प्रौढ़ महिलाओं और बालिकाओं के लिए कौशल प्रधान साक्षरता कार्यक्रम (10 नवंबर, -1 दिसंबर, 1991)

त्रिवेंद्रम में भारतीय जनसंख्या शिक्षा संघ द्वारा जनगणना संगोष्ठी में भाग लिया (19-22 दिसंबर 1991)

एन. वी. वर्गीज

मानव शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में 'रोजगार के लिए समेकित योजना' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया (21-22 फरवरी, 1992)

रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली में 'बालिकाओं की शिक्षा' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया (12-13 मार्च, 1992)

एस. सी. नुना

यूनेस्को, बैकाक में मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा

की अखंड योजना तथा प्रबंध विषय पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया (16-20 दिसंबर, 1991)

"भारत में साक्षरता की स्थिति 1991 : विकासशील से विकसित होने के लिए एक अभियान" विषय पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में 1991 की जनगणना के प्रथम परिणाम पर आयोजित कार्यशाला में आलेख प्रस्तुत किया (24 अप्रैल, 1991)

के.सुधा. राव

एनापोलिस, मैरीलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका में तुलनात्मक तथा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समाज द्वारा "शिक्षा की गुणवत्ता में संकट" विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। "स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनः रचना : संरचनात्मक प्रभाव तथा अकादमिक यथार्थवादिता का पारस्परिक प्रभाव" विषय पर भी आलेख प्रस्तुत किया (12-25 मार्च 1992)

कौनेक्टीकट, संयुक्त राज्य अमरीका में प्रत्यापन आयोग की बैठक में भाग लिया तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों के नवीन इंग्लैंड संघ की कार्यप्रक्रिया की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत की (6 मार्च 1992)

बेंटली कॉलेज वालथम, संयुक्त राज्य अमरीका में व्यावसायिक विकास पर आयेजित क्षेत्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी का आयोजन नवीन इंग्लैंड शिक्षक द्वारा किया गया (14 फरवरी 1992)

डॉ (श्रीमती) सुदेश मुखोपाध्याय

"अनुसंधान और कक्षा शिक्षक : शिक्षक के बदलते व्यवहार" विषय पर बड़ौदा में आयोजित कार्यशिविर में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया (26 अक्तुबर-2 नवंबर, 1991)

एस.एम.आइ.ए. जैदी

गोवाहाटी में असम सरकार के योजना और विकास विभाग द्वारा "असम में प्राथमिक शिक्षा" पर आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी में भाग लिया (27 जनवरी, 1992)

योजना विभाग, असम सरकार द्वारा गोवाहाटी में असम में प्राथमिक शिक्षा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया तथा 'जिला स्तर पर शिक्षा के लिए योजना' विषय पर आलेख प्रस्तुत किया (27-28 जनवरी 1992)

बी.के. पांडा

"विद्यालय प्राचार्यों के लिए संस्थागत योजना" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीमनगर आंध्र प्रदेश में संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया (3-7 मार्च 1992)

1991-92

परिशिष्ट I

नीपा परिषद के सदस्य

(31 मार्च 1992)

अध्यक्ष

श्री अर्जुन सिंह, मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

प्रोफेसर सत्यभूषण
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

पदेन सदस्य

प्रो. जी. राम रेड्डी	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
श्री अनिल बोर्डिया	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
श्री एस. के. बनर्जी	वित्त सलाहकार, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री ए. आर. बंधोपाध्याय	अतिरिक्त सचिव, जन शिकायत और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय, कमरा सं. 514, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
श्री एन. के. सेनगुप्ता	सचिव, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
डॉ. के. गोपालन	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

1991-92

शिक्षा सचिव

श्री लालचूमा	शिक्षा सचिव और आयुक्त, शिक्षा विभाग, नागालैंड सरकार, सिविल सचिवालय, कोहिमा—797001
श्री आर. के. श्रीवास्तव	विशेष आयुक्त और सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार पटना—800015
श्री देव स्वरूप	आयुक्त और सचिव, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002
श्री एम. वी. गार्डे	सचिव (विद्यालय तथा उच्च शिक्षा) मध्य प्रदेश सरकार, D-2/13, चार इमली, भोपाल—462004
श्री के. एस. शर्मा	सचिव, शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद—500022
श्री एन. सत्यावती	आई. ए. एस., शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, प्रधान सचिवालय, पांडिचेरी—605001

शिक्षा निदेशक/डी.पी.आई

श्रीहरन थांगा	विद्यालय निदेशक (माध्यमिक, प्राथमिक तथा प्रौढ़), मिजोरम सरकार आइज़ोल—790001
श्रीमती गौरी नाग	निदेशक, लोक निर्देश, पश्चिमी बंगाल सरकार तथा पदेन सचिव, शिक्षा विभाग, राईटर भवन, कलकत्ता—700001
श्री बी. पी. खंडेलवाल	शिक्षा निदेशक, उत्तरप्रदेश, 18—पार्ट मार्ग, लखनऊ—226001 (कैम्प कार्यालय, मुख्यालय—इलाहाबाद)
श्री पी. एस. भारद्वाज	निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
श्री के. के. विजयकुमार	निदेशक, लोकनिर्देश, जगाथी, त्रिवेंद्रम—695014
श्री जी. डी. शर्मा	शिक्षा निदेशक, लक्षद्वीप (संघ शासित प्रदेश) कवारत्ती—682555

विख्यात शिक्षाविद

डॉ. पी. सी. जोशी	(भूतपूर्व निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान) फ्लैट नं. 109, साक्षरा अपार्टमैंट्स, A-3 पश्चिम विहार, नई दिल्ली

1991-92

प्रो. बिपिन चंद्र	ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई महरौली रोड, नई दिल्ली
प्रो. प्रभात पटनायक	आर्थिक अध्ययन तथा योजना केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई महरौली रोड, नई दिल्ली
प्रो. पोरोमेश आचार्य	भारतीय प्रबंध संस्थान, डायमंड हारबर मार्ग, जोका, पोस्ट बाक्स सं. 16757, अलीपुर पोस्ट आफिस, कलकत्ता—700027
प्रो. कृष्ण कुमार	शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
श्री एम. पी. परमेश्वरन	केरल शास्त्र साहित्य परिषद, तिरूवंतापुरम, केरल

कार्यकारी समिति के सदस्य

डा. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर	संयुक्त सचिव (योजना), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
श्री एल. पांडेय	निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ
श्री डी. ए. पनीरसीवाम	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 6, आई.टी.आई. परिसर कालेज मार्ग, मद्रास, तमिलनाडु
श्री बलदेव महाजन	संयुक्त निदेशक, नीपा

संकाय सदस्य

डा. जी. डी. शर्मा	वरिष्ठ अध्येता तथा अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एकक
डॉ. (श्रीमती) कुसुम के. प्रेमी	अध्येता तथा अध्यक्ष, शैक्षिक नीति एकक
डॉ. अरुण सी. मेहता	सह अध्येता, शैक्षिक योजना एकक

सचिव

श्री के. एल. दुआ	कार्यकारी कुलसचिव

परिशिष्ट II

कार्यकारी समिति के सदस्य

(31 मार्च 1992)

1. प्रोफेसर सत्यभूषण — अध्यक्ष
   निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
   नई दिल्ली

2. डॉ. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर
   संयुक्त सचिव (योजना)
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   शास्त्री भवन
   नई दिल्ली

3. श्री एस. के. बनर्जी
   वित्त सलाहकार
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   शिक्षा विभाग
   शास्त्री भवन
   नई दिल्ली

4. श्री एम. आर. कोलहाटकर
   सलाहाकार (योजना)
   योजना आयोग
   योजना भवन
   नई दिल्ली

1991-92

5. श्री देव स्वरूप
   आयुक्त तथा सचिव (शिक्षा)
   हिमाचल प्रदेश सरकार
   शिमला—171002

6. श्री एल. पांडेय
   निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)
   उत्तर प्रदेश सरकार
   शिक्षा निदेशालय
   निशातगंज
   लखनऊ

7. श्री डी. ए. पनीरसीवाम
   निदेशक
   राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
   प्रशिक्षण परिषद
   6, आई.टी.आई. परिसर
   महाविद्यालय मार्ग
   मद्रास, तमिलनाडु

8. प्रो. कृष्ण कुमार
   शिक्षा विभाग
   दिल्ली विश्वविद्यालय
   दिल्ली

9. श्री बलदेव महाजन
   संयुक्त निदेशक
   नीपा
   नई दिल्ली

10. डॉ. जी. डी. शर्मा
    वरिष्ठ अध्येता तथा अध्यक्ष
    उच्च शिक्षा एकक
    नीपा
    नई दिल्ली

11. डॉ. (श्रीमती) कुसुम के. प्रेमी
अध्येता तथा अध्यक्ष
शैक्षिक नीति एकक
नीपा, नई दिल्ली

12. श्री के.एल. दुआ — सचिव
कार्यकारी कुलसचिव
नीपा
नई दिल्ली

परिशिष्ट III

वित्त समिति के सदस्य

(31 मार्च 1992)

1. प्रो. सत्यभूषण — अध्यक्ष
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

2. श्री एस. के. बनर्जी
वित्त सलाहकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

3. डॉ. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर
संयुक्त सचिव (योजना)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
नई दिल्ली

4. श्री बलदेव महाजन
संयुक्त निदेशक
नीपा
नई दिल्ली

5. श्री लालचूमा,
आयुक्त तथा सचिव
(विद्यालय शिक्षा)
नागालैंड सरकार
कोहिमा—797001

6. श्री के. एल. दुआ सचिव
कार्यकारी कुल सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

परिशिष्ट IV

संकाय तथा प्रशासनिक स्टाफ

(31 मार्च 1992)

सत्यभूषण, निदेशक
बलदेव महाजन, संयुक्त निदेशक

शैक्षिक प्रशासन एकक

एम. मुखोपाध्याय, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
सी.मेहता, अध्येता (अवकाश पर विदेश में)
के. सुजाता, अध्येता
ए. मैथ्यू, सह-अध्येता
वाई. जोसेफिन, सह-अध्येता
मंजू नरूला, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक वित्त एकक

जे.बी.जी. तिलक, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
अशोक कुमार, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक योजना एकक

श्रीप्रकाश, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
ब्रह्म प्रकाश, वरिष्ठ अध्येता (इ.ओ. एल. पर विदेश में)
अरुण सी. मेहता, सह-अध्येता
रंजना श्रीवास्तव, सह-अध्येता
एस.एम.आई. ए. ज़ैदी, सह-अध्येता
प्रभा देवी अग्रवाल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

1991-92

शैक्षिक नीति एकक

सुश्री कुसुम के. प्रेमी, अध्येता और अध्यक्ष
प्रमिला मेनन, सह-अध्येता
नलिनी जुनेजा, सह-अध्येता (अध्ययन अवकाश पर)
एम. मलिक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

उच्च शिक्षा एकक

जी. डी. शर्मा, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
जयलक्ष्मी इंदिरसेन, वरिष्ठ अध्येता
के. सुधा राव, अध्येता
कौसर विजारत, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

अंतर्राष्ट्रीय एकक

के. जी. विरमानी, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
अंजना मंगलागिरि, अध्येता
सुनीता चुग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक

आर. गोविंद, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
सुषमा भागिया, अध्येता
वाई.पी. अग्रवाल, अध्येता
सुदेश मुखोपाध्याय, अध्येता
वी. के. पांडा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
वी. पी. आर. एस. राजू, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

प्रादेशिक प्रणाली एकक

एम. एम. कपूर, अध्येता और अध्यक्ष
आर. एस. शर्मा, अध्येता
एस. सी. नुना, अध्येता

1991-92

एन.वी. वर्गीस, अध्येता
जयश्री जलाली, सह-अध्येता (अध्ययन अवकाश पर)

हिंदी कक्ष

एस. बी. राय, हिंदी संपादक

प्रकाशन एकक

एम. एम. अजवानी, सहायक प्रकाशन अधिकारी

मानचित्रण कक्ष

पी. एन. त्यागी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

समन्वयन

ए. एन. रेड्डी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

इलेक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग और रिप्रोग्राफिक एकक

श्री बी. एच. श्रीधर, कंप्यूटर प्रोग्रामर

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र एकक

निर्मल मल्होत्रा, पुस्तकाध्यक्ष
एन. डी. कांडपाल, प्रलेखन अधिकारी
दीपक मकोल, पुस्तकाध्यक्ष ग्रेड II

प्रशिक्षण कक्ष

योगेश्वर प्रसाद, प्रशिक्षण सहायक

1991-92

अनुसंधान परियोजना स्टाफ

जे. सी. गोयल, परियोजना अध्येता
उषा आयंगर, परियोजना अध्येता
एम. एम. रहमान, परियोजना सह-अध्येता
आर. एस. त्यागी, परियोजना सह-अध्येता
नीरा धर, परियोजना सह-अध्येता
जी. पी. सिंह, परियोजना सह-अध्येता
एस. मजुमदार, परियोजना सह-अध्येता
मोहम्मद अहमद अंसारी, परियोजना सह-अध्येता
अरूप बनर्जी, परियोजना सह-अध्येता
रघु राम राव, परियोजना सह-अध्येता
नेयाज़ खान, परियोजना सह-अध्येता
विरेंद्र त्रिवेदी, परियोजना सह-अध्येता

परियोजना सहायक

पुष्पा कथूरिया
तरुज्योति बुड़ागोहेन
जमालुद्दीन फारुकी
वासवी सरकार
सारिका सीबू
ए. के. सिन्हा
जार्ज मैथ्यू
अंजना सलूजा
मोहम्मद जमीर
डी. कें. दक्षिणमूर्ति
सी. एम. जयादिवान
अनुराधा
एम. अग्रवाल
अर्चना सक्सेना
ए. एन. सिन्हा
एम. वेंकेटेशन

1991-92

कार्यालय प्रशासन

के. एल. दुआ, कार्यवाहक कुलसचिव
ओ. पी. शर्मा, वित्त अधिकारी
जी. एस. भारद्वाज, अनुभाग अधिकारी
टी. आर. ध्यानी, अनुभाग अधिकारी
एम. एल. शर्मा, अनुभाग अधिकारी
एस. आर. चौधरी, अनुभाग अधिकारी
पी. मणि, निदेशक के निजी सचिव
सुषमा असीजा, वरिष्ठ निजी सहायक
आर. सी. शर्मा, लेखाकार

1991-92

परिशिष्ट V

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट : 1991-92

1991-92

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
वार्षिक लेखा :
1-4-1991 से 31-3-1992 तक की

प्राप्तियां		
अर्थ शेष		
हस्तगत रोकड़	5,599.00	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक में रोकड़	4,462,576.20	4,469,175.20
भारत सरकार से प्राप्त सहायता		
योजनेतर	9,528,000.00	
योजना	8,997,000.00	18,525,000.00
कार्यालय प्राप्तियां		
लाइसेंस शुल्क	50,200.00	
पानी और बिजली का बिल	4,402.00	
ई. डी. पी. आर. की प्राप्तियां	7,618.00	
फोटो कापी की प्राप्तियां	173,284.50	
खराब सामान की बिक्री से प्राप्तियां	41,892.00	
अन्य फुटकर प्राप्तियां	28,911.92	
प्रकाशन की बिक्री	27,570.00	
अवकाश वेतन तथा पेंशन	29,780.00	
सी.पी.एफ./जी.पी.एफ. पर ब्याज	1,792.00	
स्टाफ कार इस्तेमाल करने का शुल्क	948.00	

1991-92

और प्रशासन संस्थान

1991-92

प्राप्तियां और भुगतान लेखा

भुगतान		
संस्थागत व्यय		
(योजनेतर)		
वेतन	6,135,144.00	
पेंशन तथा ग्रेच्युइटी	392,806.00	
जी.पी.एफ/सी.पी.एफ. ब्याज तथा नियोक्ता का अंश	449,593.00	
अवकाश वेतन तथा पेंशन	25,150.00	
यात्रा पर किया गया व्यय	29,492.00	7,032,185.00
योजना		
वेतन	351,195.00	351,195.00
कार्यालय संबंधी व्यय		
योजनेतर	2,036,715.00	
योजना	572,791.00	2,609,506.00
छात्रावास		
आवर्ती व्यय (योजनेतर)	214,185.00	
अनावर्ती व्यय (योजना)	78,460.00	292,645.00

1991-92

प्राप्तियां

पेंशन कर्त्ता का पूंजीगत मूल्य	10,915.00	
कार्यक्रम से प्राप्तियां	118,732.00	
प्रशासनिक खर्चों की वसूली		
एल.टी.सी.	1,896.00	
अकादमिक गतिविधियों की वसूली	10,982.85	
यात्रा व्यय	80.00	509,004.27
छात्रावास शुल्क		436,770.00
उपहार तथा चंदे के रूप में प्राप्त		
(पुस्तकालय के लिए पुस्तकें)		80,215.00
ब्याज		
ब्याज की पेशगियों पर ब्याज	38,117.00	
अल्पकालिक जमा राशि पर ब्याज	586,658.50	
जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. निवेश पर ब्याज	385,914.70	1,010,690.20
प्रतिभागियों से प्राप्त राशि		500.00
जमा		
सी.पी.डब्ल्यू.डी. से वापस की गई राशि	124,320.00	124,320.00
उचंत लेखा	2,480.83	2,480.83
अनाबंटित राशि	10,125.00	10,125.00
सुरक्षा जमा		1,000.00
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
कार्यक्रम और अध्ययन से प्राप्तियां		5,135,577.75
वसूली योग्य पेशगियां		
साइकिल के लिए पेशगी	5,480.00	
स्कूटर के लिए पेशगी	33,760.00	

1991-92

भुगतान		
अकादमिक गतिविधियां (योजनेतर)		
कार्यक्रम पर खर्चे	1,769,119.00	1,769,119.00
स्टाफ प्रशिक्षण	2,020.00	2,020.00
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	185,564.00	185,564.00
अकादमिक गतिविधियां (योजना)		
अनुसंधान अध्ययन	1,363,772.25	
सहायता योजना	67,580.00	
प्रकाशन	178,130.00	1,609,482.25
उपहार और अनुदान के रूप में (पुस्तकें)	80,215.00	80,215.00
पूंजी व्यय (योजना)		
फर्नीचर तथा लगाने आदि के खर्चे	57,521.00	
अन्य कार्यालय उपकरण	502,471.00	
टाइपराइटर	46,037.00	
स्टाफ कार	194,885.00	800,914.00
जमा		
सी.पी.डब्ल्यू. के पास जमा (योजना)		4.354,517.00
उचंत लेखा		58,730.00
सुरक्षा जमा		3,000.00
सुरक्षा जमा वापसी		2,000.00
प्रायोजित कार्यक्रम तथा अध्ययन		
कार्यक्रम तथा अध्ययन के खर्चे	3,216,608.10	3,216,608.10
वसूली योग्य पेशगियां		
साइकिल के लिए पेशगी	4,800.00	

1991-92

प्राप्तियां		
त्यौहार के लिए पेशगी	29,200.00	
मकान बनाने के लिए पेशगी	106505.00	
कार के लिए पेशगी	49,378.00	
पंखे के लिए पेशगी	280.00	
कम्प्यूटर के लिए पेशगी	15,140.00	239,743.00
विविध पेशगियां (एन.सी.टी.)		
(समायोजन राशि प्राप्त की गई)		3,777.50
जी.एस.एल.आई.योजना		
एल.आई.सी. से प्राप्त		6,562.60
योग		30,554,941.35

ह.
(ओ.पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

भुगतान		
स्कूटर के लिए पेशगी	52,000.00	
त्यौहार के लिए पेशगियां	30,680.00	
मकान बनाने के लिए पेशगी	17,600.00	
कम्प्यूटर के लिए पेशगियां	90,000.00	195,080.00
विविध		13,780.00
जी.एस.एल.आई. योजना		3,262.00
एल.आई.सी. से प्राप्त की गई राशि		6,562.60
रोकड़ बाकी		
हस्तगत रोकड़	10,125.00	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक में रोकड़	7,957,431.40	7,968,556.40
योग		30,554,941.35

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1991-92

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
रोकड़बाकी का विवरण (31-3-92)

	शीर्षक	रोकड़ जमा	अनुदान
1.	योजनेतर	371,561.76	9,528,000.00
2.	योजना	503,135.78	8,997,000.00
3.	प्रायोजित कार्यक्रम	3,536,228.49	5,135,577.75
4.	उचंत लेखा	56,249.17	0.00
5.	जमा	2,000.00	0.00
6.	राशि प्राप्ति (एल.आई.सी.)	0.00	0.00
7.	यू.डी. राशि	0.00	0.00
	योग	4,469,175.20	23,660,577.75

ह.
(ओ.पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली-110016

1991-92

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
रोकड़बाकी का विवरण (31-3-92)

अन्य प्राप्तियां	योग	भुगतान	शेष
2,402,242.47	12,301,804.23	11,451,910.00	849,894.23
0.00	9,500,135.78	7,850,574.25	1,649,561.53
3,777.50	8,675,583.74	3,216,608.10	5,458,975.64
2,480.83	58,730.00	58,730.00	0.00
0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
6,562.60	6,562.60	6,562.60	0.00
10,125.00	10,125.00	0.00	10,125.00
2,425,188.40	30,554,941.35	22,586,384.95	7,968,556.40

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली-110016

1991-92

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
आय-व्यय का लेखा (वर्ष 1991-92)

व्यय	
स्थापना व्यय	7,383,380.00
कार्यालय व्यय	2,609,506.00
स्टाफ का प्रशिक्षण	2,020.00
छात्रावास का व्यय	214,185.00
अकादमिक गतिविधियां	3,378,601.25
आमदनी से ज्यादा खर्च	5,825,703.62
योग	19,413,395.87

ह.
(ओ.पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली-110016

1991-92

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
आय-व्यय का लेखा (वर्ष 1991-92)

	आय		
सहायता अनुदान		18,525,000.00	
सहायता अनुदान को छोड़कर			
कार्यालय मद	879,374.00		
पुस्तकालय की पुस्तकें	185,564.00	1,064,938.00	17,460,062.00
कार्यालय प्राप्तियां			509,004.27
होस्टल का किराया	436,770.00		
पिछले साल का निकालकर	8,700.00	428,070.00	
वर्ष का उपचय किराया		920.00	428,990.00
ब्याज		1,010,690.20	
पी.एफ. बचतखाते का उपचय ब्याज		4,649.40	1,015,339.60
योग			19,413,395.87

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली-110016

1991-92

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

तुलन पत्र (31 मार्च 1992)

देयताएं		
पूंजीकृत अनुदान		
पिछली तालिका के अनुसार शेष	25,638,767.33	
वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि	1,064,938.00	
परिवर्धन (समायोजन द्वारा)	1,587,193.00	
पूंजी निवेश -बट्टेखाते को घटाकर	52,000.00	
	108,040.51	28,130,857.82
प्रायोजित कार्यक्रम की प्राप्तियां		
पूंजीकृत प्राप्तियां	720,693.00	720,693.00
कोप/एम.आई.एस. परियोजना		
के गत वर्ष की शेष राशि	611,600.00	
वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि	82,855.00	694,455.00
प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण : संचारेक्षण प्रणाली		24,359.00
व्यय से अधिक आय		
पिछले तुलन पत्र के मुताबिक शेष राशि	7,884,497.31	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	5,825,703.62	
समायोजन करके घटाई गई राशि	1,587,193.00	12,123,007.93

1991-92

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
तुलन पत्र (31 मार्च 1992)

परिसंपत्तियां		
भूमि तथा भवन		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	15,786,176.78	
समायोजन के माध्यम से जुड़ी राशि	1,587,193.00	
वर्ष के दौरान अन्य कारणों से बढ़ी राशि	0.00	17,373,369.78
फर्नीचर तथा अन्य खर्चे, स्टाफ कार, टाइपराइटर तथा कम्प्यूटर आदि के खर्चों को शामिल करके		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	8,755,257.93	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	986,588.00	
वर्ष के दौरान डिस्पोजल को घटाने पर	160,040.51	9,581,805.42
पुस्तकालय की पुस्तकें		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	2,434,587.93	
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	185,564.00	
उपहार और अनुदान के द्वारा बढ़ोत्तरी	80,215.00	2,700,366.93
भविष्य निधि निवेश		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	2,830,000.00	
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	1,250,000.00	4,080,000.00
जमा		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	52,990.00	

देयताएं

निर्धारित कार्यक्रम तथा अध्ययन

पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	3,560,692.39	
वर्ष के दौसन बढ़ी राशि	5,135,577.75	
वर्ष के दौरान व्यय को घटाकर	3,216,608.10	5,479,662.04

भविष्य निधि

पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	3,193,511.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	2,720,920.00	
वर्ष के दौरान समाशोधन को घटाने के बाद	1,359,313.00	4,555,118.00

उचंत लेखा

पिछले तुलन पत्र कै मुताबिक शेष राशि	56,249.17	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	2,480.83	
वर्ष के दौरान समाशोधन को घटाकर	58,730.00	0.00

उपहार तथा दान

पिछले साल कै अनुसार शेष राशि	4,962.31	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	80,215.00	85,177.31

1991-92

परिसंपत्तियां

वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	3,000.00	55,990.00
कें.लो. निर्माण के पास जमा		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	5,852,208.77	
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	4,354,517.00	
वापसी को घटाने पर	124,320.00	
समायोजित राशि को घटाकर	1,587,193.00	8,495,212.77
वसूली योग्य पेशगियां		
मोटर कार की पेशगी	363,442.00	
गृह निर्माण की पेशगी	366,639.00	
त्यौहार की पेशगी	21,460.00	
साइकिल के लिए पेशगी	3,260.00	
स्कूटर के लिए पेशगी	90,470.00	
संगणक के लिए पेशगी	192,345.00	
पंखे के लिए पेशगी	0.00	
विविध पेशगियां (नीपा)	20,750.00	
स्थानांतरण यात्रा भत्ता पेशगी	7,000.00	1,065,366.00
विविध पेशगियां (एन.सी.टी.)		20,686.40
जी.एस.एल.आई. योजना : गतवर्ष की शेष राशि	1,652.00	
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरियां	3,262.00	4,914.00
छात्रावास से प्राप्त आय		
गतवर्ष की शेष राशि	8,700.00	
वर्ष के दौरान की वसूली	8,700.00	
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	920.00	920.00

1991-92

देयताएं		
यू.डी. राशि		
वर्ष के दौरान की शेष राशि	10,125.00	10,125.00
जमा		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	4,500.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	1,000.00	
वर्ष के दौरान समाशोधन	2,000.00	3,500.00
योग		**51,826,955.10**

ह.
(ओ.पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली-110016

1991-92

परिसंपत्तियां		
विविध देनदार		
पिछली तालिका के अनुसार शेष राशि	500.00	
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि को घटाकर	500.00	
वर्ष के दौरान क्लियेरंस को घटाकर	0.00	0.00
भविष्यनिधि खाते पर प्रोदभूत ब्याज		4,649.40
शेष रोकड़		
हस्तगत राशि	10,125.00	
अग्रदाय	1,000.00	
चालू खाता सी-4	7,957,431.40	
जी.पी.एफ/सी.पी.एफ. खाता-टी-2	475,118.00	8,443,674.40
योग		**51,826,955.10**

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
31 मार्च 1992 तक के निर्धारित कार्यक्रम/अध्ययन का लेखा प्रपत्र

क्र. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थशेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
	भारत सरकार					
1.	गृह मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) अनु. जाति के शैक्षिक विकास संबंधी अध्ययन एकक	(–) 116,398.25	116,398.25	0.00	0.00	0.00
2.	राष्ट्रीय शिक्षक आयोग–II • केंद्रीय तकनीकी एकक • आयोग के दौरे का आयोजन	128,713.55	0.00	128,713.55	29,881.50	98,832.05
3.	अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजना मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा मंत्रालय)	24,923.36	0.00	24,923.36	0.00	24,923.36
4.	केब समिति–शिक्षकों का तबादला	33,354.00	0.00	33,354.00	33,354.00	0.00
5.	अनौपचारिक शिक्षा समेत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का प्रारंभिक तथा नवाचारी कार्यक्रम (जिला शिक्षा अधिकारी)	1,510,772.30	0.00	1,510,772.30	589,734.00	921,038.30

क्र. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थशेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
	योजना आयोग					
6.	शिक्षा तथा रोजगार के बीच लाभकारी संबंधों का अध्ययन	13,372.90	0.00	13,372.90	0.00	13,372.90
7.	मौजूदा सुविधाओं का अधिकाधिक प्रभावी उपयोग	(—) 8,463.00	28,000.00	19,537.00	1,500.00	18,037.00
	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और अध्ययन					
8.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम	801,208.64	926,745.50	1,727,954.14	790,557.00	937,397.14
9.	उच्च शिक्षा में समता, गुणवत्ता और लागत का अध्ययन	20,954.13	0.00	20,954.13	0.00	20,954.13
10.	उच्च शिक्षा में संसाधन आवंटन की प्रविधि का अध्ययन	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
11.	कंप्यूटर किराए पर लेकर उसके प्रभावी उपयोग का अध्ययन (वि. वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)	32,000.00	0.00	32,000.00	19,250.00	12,750.00

क्र. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थशेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
12.	विकेन्द्रीकरण के उपाय के रूप में व्यष्टिस्तरीय शैक्षिक योजना और प्रबंध (डॉ. ब्रह्मप्रकाश)	8,944.61	0.00	8,944.61	0.00	8,944.61
13.	पर्यावरण शिक्षा में अंतक्षेत्रीय पाठ्यक्रम यूनेस्को (डॉ. आर. गोविंद)	12,389.15	32,971.00	45,360.15	0.00	45,360.15
14.	पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के योजनाकारों की निर्देशिका	51,900.00	0.00	51,900.00	51,900.00	0.00
15.	पर्यावरण शिक्षा का अंतक्षेत्रीय कार्यक्रम (की. न. 109. 500.8)	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
16.	पर्यावरण शिक्षा पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.00	431,400.00	431,400.00	278,290.60	153,109.40
17.	दक्षिण एशियाई देशों के लिए पर्यावरण शिक्षा	0.00	77,750.00	77,750.00	82,173.00	(—) 4423.00
18.	लेखकीय सेविदा : पर्यावरण शिक्षा निर्देशिका	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00
19.	जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रौढ़ शिक्षा) का छः सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	2,181.00	147,375.00	149,556.00	33,137.00	116,419.00

क्र. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थशेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
20.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनशिक्षा समिति	147,257.00	2,546.00	149,803.00	13,600.00	136,203.00
21.	शिक्षा में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग	(—) 12,600.00	196,000.00	183,400.00	135,077.00	48,323.00
22.	प्रारंभिक शिक्षा की संचारेक्षण प्रणाली	72,055.00	2,396,678.00	2,468,733.00	422,119.00	2,046,614.00
23.	उत्तर प्रदेश में सबके लिए शिक्षा (विश्व बैंक योजना) (इटावा जिला)	142,458.00	0.00	142,458.00	237,999.00	(—) 95,541.00
24.	शैक्षिक प्रोद्योगिकी योजना का मूल्यांकन अध्ययन	671,940.00	0.00	671,940.00	37,818.00	634,122.00
25.	चीन से यूनेस्को फेलो	11,730.00	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00
26.	प्रतिभाशाली छात्रों के लिए (देहात के) माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियों का मूल्यांकन अध्ययन (मानव सं. वि. मंत्रालय)	0.00	100,000.00	100,000.00	21,115.00	78,885.00

क्र. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अथशेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
27.	विकलांग बच्चों के लिए योजना सुविधाओं संबंधी विषय पर जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों का अभिविन्यास कार्यक्रम	0.00	78,000.00	78,000.00	14,853.00	63,147.00
28.	डी.आई.ई.टी. कार्यक्रम	0.00	97,000.00	97,000.00	8,530.00	88,470.00
29.	डायट का तीसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.00	50,464.00	50,464.00	50,464.00	0.00
30.	डायट का कार्यक्रम (रामस्वरूप शर्मा)	0.00	105,000.00	105,000.00	88,918.00	16,082.00
31.	पुस्तकालयाध्यक्षों का डायट का प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.00	93,750.00	93,750.00	51,265.00	42,485.00
32.	स्कैप कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में विदेशों से नामित प्रशिक्षार्थियों का कार्यक्रम	0.00	19,500.00	19,500.00	10,500.00	9,000.00
33.	लोक जुंबिश कार्यक्रम	0.00	80,000.00	80,000.00	26,855.00	53,145.00

क्र. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अथशेष	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
34.	सार्क विशेषज्ञों की बैठक	0.00	0.00	0.00	71,988.00	(–) 71,988.00
35.	एस.सी.ई.आर.टी. कार्यक्रम के लिए कार्यशिविर	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	योग	3,560,692.39	5,135,577.75	8,696,270.14	3,216,608.10	5,479,662.04

ह.
(ओ. पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली-110016

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली-110016

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
वर्ष 1991-92 के लिए सी.पी.एफ./जी.पी.एफ. का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

प्राप्ति		भुगतान		
अर्थशेष	363,511.00	पेशगियां और निकासी	1,359,313.00	
अंशदायी तथा पेशगियों की वापसी	2,259,726.00	निकासी को छोड़कर	1,250.000.00	
		जमा निवेश	—	2,609,313.00
कर्मचारी द्वारा नियोक्ता का भुगतान	11,601.00			
ब्याज, नियोक्ताओं का अंशदान आदि	449,593.00	अंतः शेष		475,118.00
योग	3,084,431.00			3,084,431.00

ह.
(ओ. पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आगत और भुगतान लेखा/आय और व्यय लेखा तथा 31 मार्च, 1992 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभियुक्तियों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में तथा मेरी जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण एवं संस्थान की बहियों में दर्शाए गए विवरणों के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा ये संस्थान के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक

ह.
महानिदेशक, लेखा परीक्षा
केंद्रीय राजस्व

— नीपा पुस्तकालय की एक झलक

— संगणक कक्ष में कार्यरत लोग

— अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का एक सत्र

— नीपा के शिक्षाकर्मियों के साथ डिप्लोमा कार्यक्रम के भागीदार